खण्ड-202, अंक-6
गुरूवार, 14 फाल्गुन, शक संवत् 1880
(5 मार्च, 1959 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 202 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश (भारत)

१९५९

---

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

---

## बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५९

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

---

## उपस्थित सदस्य—३५०

अक्षयवर्सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दुस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेशप्रतापसिंह, श्री
अहमद बख्श, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इन्दुभूषण गुप्त, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफ़ा हुसैन, श्री
उग्रसेन, श्री
उबैदुर्रहमान, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
ऊदल, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोइंदी, कुमारी
कमलेशचन्द्र, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण अग्रवाल, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशभानराय, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खमानीसिंह, डाक्टर
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
ग़यूर अली ख़ां, श्री
ग़रीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपाली, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्त सिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथप्रसाद, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जितेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
झारखंडेराय, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
जासिंह, श्री
लोकीसिंह, श्री

दत्त, श्री एस० जी०
दशरथ प्रसाद, श्री
दीनदयालु करुण, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवकी नन्दन विभव, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
देवीप्रसाद मिश्र, श्री
द्वारकाप्रसाद मित्तल, श्री (मुजफ्फरनगर)
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिका प्रसादपांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दराम, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्द सिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बलदेवसिंह, श्री
बलवानसिंह, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री

बालकराम, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजवासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भोखालाल, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूदअली खां, श्री (रामपुर)
अहमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महवीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेन्द्ररिपुदमनसिंह, राजा
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथ राय, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्ला प्रसाद 'हंस', श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यमुनाप्रसाद शुक्ल, श्री
यमुनासिंह, श्री (गाजीपुर)
यशपालसिंह, श्री
यशोदादवी, श्रीमती
यादवेन्द्रदत्त दुबे, राजा
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुरनतेजबहादुरसिंह, श्री
रघुवीर राम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवराम पाण्डेय, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामनारायण त्रिपाठी, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती

रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखन मिश्र, श्री
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वैद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रमहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रुकनुद्दीन खां, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मणसिंह, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लखमी सिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ़ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नक़वी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
विश्वेश्वरानन्द, स्वामी
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा, श्री
वीरेन्द्रविक्रमसिंह, श्री
व्रजगोपाल सक्सेना, श्री
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीरहसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद, श्री (देवरिया)
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्तिसिंह, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शिवशरणलाल श्रीवास्तव, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
श्यामनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्रद्धादेवी शास्त्री, कुमारी
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रसिंह, राजकुमार
सुरेशप्रकाशसिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हरकेशबहादुर, श्री

हरदयालसिंह, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिश्चन्द्रसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

सार्वजनिक निर्माण उपमंत्री, श्री महावीरसिंह भी उपस्थित थे।

---

# प्रश्नोत्तर

---

## बृहस्पतिवार, ५ मार्च, १९५९

---

## अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

### पूर्वीय जिलों में खाद्यान्न सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाने की प्रार्थना

**१--**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)--क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृप करेंगे कि आजमगढ़ जिले में फरवरी, १९५९ में कुछ सस्ते गल्ले की दूकानों को बढ़ाने का आदेश सरकार ने दिया है ?

**खाद्य मंत्री (श्री जगमोहनसिंह नेगी)**--जी नहीं। हाल ही में जिलाधीश को आदेश दिया गया है कि बाढ़-पीड़ित तथा ओला पीड़ित क्षेत्रों में अन्न के अतिरिक्त गेहूं का आटा वितरण करने का भी प्रबन्ध किया जाय।

**२--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वीय जिलों में इस समय सस्ते गल्ले की दूकानों पर प्रतिदिन जिस मात्रा में गेहूं बेचने का आदेश रहा है क्या सरकार ने उस मात्रा को बढ़ाने का आदेश दिया है ? यदि हां, तो प्रतिदिन कितना ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--सस्ते गल्ले की दुकानों पर शहरी क्षेत्रों में २५ मन के बजाय ३० मन प्रतिदिन बेचने के आदेश दिये गये थे और ग्रामीण क्षेत्रों में मोटे गल्ले के अतिरिक्त ५ मन गेहूं बांटने के लिये कहा गया था। यह भी विचाराधीन है कि ग्रामीण क्षेत्रों में गेहूं की मात्रा ५ मन से बढ़ाकर १० मन प्रतिदिन कर दी जाय।

**३--**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के पूर्वीय जिलों के वे क्षेत्र जो भयंकर रूप से ओलाग्रस्त हैं उनकी जनता को कार्ड सिस्टम से गल्ला वितरण की व्यवस्था करने का विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है। गल्ले का वितरण भलीभांति करने के लिये ग्रामीण क्षेत्रों में समितियां बनाने का विचार है जो गल्ले का वितरण कराने में सहायक होंगी।

**श्री मुक्तिनाथ राय**--क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त क्षेत्र में अन्न के अतिरिक्त कितने मन गेहूं का आटा प्रति दिन वितरित करने का आदेश सरकार ने दिया है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**--यह तो उपलब्धि पर मुनहसिर करेगा। जिस मिल एरिया के अन्दर आपका जिला पड़ेगा और वहां से जितना बाकी आटा मिलेगा और आपके जिले को दिया जायगा वह उसी क्षेत्र को भेज दिया जायगा जो कि बाढ़-पीड़ित और ओला-पीड़ित है।

**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जहां पर ओलाग्रस्त क्षेत्रों में दुकानें नहीं हैं वहां अन्यत्र से दूकानें हटाकर ओलाग्रस्त क्षेत्रों में ही दूकानें खोलने का आदेश सरकार देगी ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---मेरे खयाल से आटा बांटने के बाद इसकी आवश्यकता नहीं होगी।

**श्री गेंदासिंह** (जिला देवरिया)---यह जो गांवों में गेहूं की मात्रा बढ़ाने और समितियां कायम करने की बात माननीय मन्त्री जी ने कही तो क्या यह रबी की फसल कट जाने के बाद इस तरह की व्यवस्था की जायगी ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---नहीं। अभी हाल में गैररस्मी तरीके पर हर जिले के सदस्यों से मैं मिला था और उनके सुझाव पर होली के लिए ५ मन के बजाय १० मन गेहूं देने का आदेश पूर्वी जिलों के लिए दे दिया गया है। क्योंकि पश्चिमी जिलों में तो १५ मन प्रति दिन पहले से ही रहा है। पूर्वी जिलों में ५ मन था। उसको १० मन कर दिया ह। होली के लिए ७, ८ तारीख से देना शुरू कर देंगे।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण क्षेत्रों में जिन समितियों के निर्माण करने की बात कही गई उन समितियों का आधार क्या होगा और कौन उसका सदस्य होगा ?

**श्री जगमोहन सिंह नेगी**---यह अभी कुछ जिले के जो साथी मिले थे उन्होंने कहा था कि एम० एल० ए० हुए, एम० एल० सी०, एम० पी० और वहां की ग्राम-सभा के सभापति जिस क्षेत्र के अन्दर दुकान स्थित है उनको इस बात की देखभाल के लिए ऐसी सलाहकार समितियां बना दी जायं। तो वह जो आपने सुझाव दिये थे वह विचाराधीन हैं और आशा है कि उसके लिए हम शीघ्र ही कोई कदम उठायेंगे।

**श्री मुक्तिनाथ राय**---क्या माननीय खाद्य मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि वे ग्राम जो कि सोलह आने ओले से बरबाद हो गए उनको कार्ड सिस्टम से गल्ला वितरित करने में सरकार को क्या कठिनाई है ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---ग्रामीण क्षेत्र में मेरा खयाल यह है कि यह पहली बार है कि जब कि गल्ला वितरण करने की योजना आयी है और बड़ी कठिनाई होगी कि हम उनके लिए कार्ड सिस्टम कर सकें क्योंकि हमारे पास न तो इतना स्टाफ है और न उसके लिए इतने साधन हैं।

**श्री मुक्तिनाथ राय**---मेरे पूछने का मतलब यह है कि बहुत से गांव ऐसे हैं कि जिनमें सिर्फ रबी की पैदावार है और इस साल मकान और फसल बिलकुल बरबाद हो गई तो इस विशेश परिस्थिति में उनकी कठिनाई को दूर करने के लिए सरकार क्या विशेष प्रयत्न कर रही है ताकि लोगों को गल्ला आसानी से मिल सके ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---इसके लिए वहां के जिलाधिकारी और ये समितियां जो अभी मैंने कही हैं, ये जो सुझाव पेश करेंगी उस पर हम सहानुभूतिपूर्वक विचार करेंगे।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि वहां पर ऐसे लोगों के लिये, जिनके पास खाने के लिये कुछ भी नहीं रहा, कुछ मुफ्त राशन कार्ड की व्यवस्था भी की है ?

**श्री अध्यक्ष**---इसका जवाब दिया जा चुका है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय** (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय खाद्य मन्त्री जी इस तरह की व्यवस्था के बारे में विचार करेंगे कि ओला-पीड़ित क्षेत्र में ५ हजार की आबादी पर एक दूकान खोल दी जाय जिससे वहां के लोग अच्छी तरह और सस्ता गल्ला जल्दी से पा सकें?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---इसका उत्तर प्रारम्भ में दिया जा चुका है कि वहां के जिला मैजिस्ट्रेट और जो मैंने समिति बताई गैरसरकारी, ये जो सुझाव देंगे उसको हम तुरन्त करने की चेष्टा करेंगे ।

**श्री गेंदासिंह**---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि ओला और बाढ़ को काफी दिन बीत चुके तो क्या जिला मैजिस्ट्रेट की तरफ से ऐसी सूचना नहीं मिली है कि ओला-ग्रस्त क्षेत्र में अनाज की काफी कमी है उसकी व्यवस्था की जाय ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---मुझे जहां तक स्मरण है वाटर लागिंग, फ्लड एरिया और ओला एरिया में विशेषतौर पर दुकानें खुली हैं । कई जिलों में खुल चुकी हैं । कहीं कोई खास जगह रह गई हों तो उसकी तरफ मेरा ध्यान आकर्षित कर सकते हैं ।

**श्री रामदास आर्य** (जिला मुजफ्फरनगर)---क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि देहातों में राशन कार्ड की व्यवस्था न होने के कारण बहुत से देहातों में गल्ला नहीं मिल पा रहा है और शक्तिशाली लोग ले रहे हैं। तो इस अवस्था को देखते हुये क्या सरकार यह मुनासिब नहीं समझती है कि गांव के प्रधान को यह आदेश जारी कर दिया जाय कि वह अपने यहां राशनकार्ड बना सकते हैं ?

**श्री जगमोहनसिंह नेगी**---इस प्रश्न के बारे में मेम्बरों में बहुत मतभेद है । माननीय सदस्य कहते हैं कि सभापति बाज दफा ऐसे कार्ड ईशू करते हैं जिससे गल्ला गांव से बहुत दूर चला जाता है । अतः यह प्रश्न विचारणीय है ।

## तारांकित प्रश्न

*१-२---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी** (जिला बस्ती)---[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

### कत्था उत्पादन तथा यू० पी० हैण्डीक्रैफ्ट्स का बिक्री के अयोग्य सामान

*३---**श्री मदन पांडेय** (जिला गोरखपुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि कत्था उत्पादन घरेलू उद्योग-धन्धे के तौर पर प्रतिवर्ष कितना होता है तथा इसके प्रोत्साहन के लिये सरकार ने क्या योजना बना रखी है ?

**मुख्य मंत्री (डाक्टर सम्पूर्णानन्द)**---

(क) लगभग २७,००० मन ।

(ख) अब तक इसकी आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई ।

*४---**श्री मदन पांडेय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्राफ्ट्स में कितना पुराना बिक्री के अयोग्य सामान (Dead stock) जमा है तथा उसकी बिक्री के लिये क्या प्रबन्ध किया जा रहा है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---

(क) लगभग ५९,००० रुपये के मूल्य का ।

(ख) सरकार द्वारा एक डिस्पोजल कमेटी बनाई गई है जो उक्त सामान की बिक्री साधनों पर विचार कर रही ह ।

## इलगिन मिल्स तथा कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में रेशनलाइजेशन

*५---**श्री उमाशंकर शुक्ल** (जिला कानपुर)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि इलगिन मिल्स कं०, लि० और कानपुर टेक्सटाइल लि० में कितना रेशनलाइजेशन हो गया है ?

**श्रम उपमंत्री (श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा)**---इलगिन मिल में इस समय चोगड्डा ६८४ लूम्स पर और तिगड्डा १३२ लूम्स पर तीनों पालियों (Shifts) में चलाया जा रहा है, शेष २,७७८ लूम्स तीन पालियों में दो लूम प्रति कारीगर के आधार पर चलते हैं। कानपुर टेक्सटाइल मिल्स में इस समय तीनों पालियों में १,५२० कर्घे चौगड्डे के हिसाब से चलाये जा रहे हैं।

*६---**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि दि इलगिन मिल्स कं०, लि० और कानपुर टेक्साटाइल्स लि०, के जिन विभागों में रेशनलाइजेशन किया गया है उनमें माननीय विन्ध्यवासिनी प्रसाद की रिपोर्ट के आधार पर वेतन दिया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जी नहीं। बिन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट शासन द्वारा अभी लागू न किये जाने के कारण तथा मिल की आर्थिक स्थिति शोचनीय होने के कारण मिलों को उक्त रिपोर्ट के आधार पर वेतन देने के लिये बाध्य करना संभव नहीं था।

**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या यह सच है कि रेशनलाइजेशन के खिलाफ होने वाली आम हड़ताल के बाद सरकार ने जब कमेटी बनाई तो उसने यह स्पष्ट आश्वासन दिया था कि कोई मिल मालिक आगे रेशनलाइजेशन नहीं करेगा और जब रेशनलाइजेशन होगा तो वह विन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर होगा और मालिकों ने जो यह बीच आफ ट्रस्ट किया है बगैर सरकार से पूछे हुये तो क्या सरकार इस बीच आफ ट्रस्ट के खिलाफ कोई कार्यवाही मालिकों के खिलाफ नहीं करना चाहती है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मान्यवर, जितनी मेरी इस वक्त तक की सूचना है उसमें जो मैंने यह चौगड्डा और तिगड्डा लूम्स के चलाने की बात कही है यह सारा इन्तजाम जिस जमाने में ८० दिन की हड़ताल चल रही थी उस जमाने में स्वीकार हुआ था। श्री विन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट में इसका तजकिरा भी है और उसका मैं थोड़ा सा उद्धरण पढ़ देना चाहता हूं :---

"The negotiations which preceded the calling off of the strike leave no room for doubt that it was agreed that the rationalisation introduced during strike was to continue unless it was established that the worker consented to it under duress. That being so, it is not competent for the Committee to cancel whatever the rationalisation already introduced,."

जो रेशनलाइजेशन उस समय वहां किया गया, कमेटी का मत था कि हम उसको पलट नहीं सकते क्योंकि जो समझौता हुआ था ८० दिन की हड़ताल खत्म होने के सिलसिले में उसमें यह बात मान ली गयी थी कि उस जमाने में जो रेशनलाइजेशन हुआ है वह तभी रद्द किया जायगा अगर यह साबित कर दिया जाय कि कमजोर समझ कर या गलत ढंग से इस रेशनलाइजेशन को मिल मालिकों ने इंट्रोड्यूस किया था। चूंकि ऐसी कोई बात सरकार के सामने नहीं आयी, इसलिये उस रेशनलाइजेशन को या उस काम को खतम करने का सरकार कोई कारण नहीं देखती। उसके पश्चात् और अब के बीच में जब सामने ऐसा प्रश्न आयेगा और आता है तो हम उसको जरूर देखते हैं कि कोई रेशनलाइजेशन ऐसा मालिक लोग न करें कि जिससे काम की बढ़ोत्तरी हो और मजदूरों को जो लाभ होना चाहिये वह न हो।

**श्री उमाशंकर शुक्ल**---श्रीमन्, जो मैंने सवाल किया है उसमें साफ है कि उस जमाने में जो रेशनलाइजेशन किया गया है उसका जिक्र मैं नहीं कर रहा हूं, बल्कि उस के बाद जिन लोगों ने किया है मैंने उसका जिक्र किया है।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---उसके बाद होने वाले रेशनलाइजेशन के सिलसिले में मान्यवर, हमारी त्रिदलीय समिति के सामने प्रश्न विचाराधीन है, लेकिन कोई प्रश्न ऐसा नहीं आया है कि मालिकों ने दबाव डाल कर या खराब नीयत से या खराब ढंग से रेशनलाइजेशन को किसी मिल में इंट्रोड्यूस किया हो।

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि इस विन्ध्यवासिनी कमेटी की रिपोर्ट को स्वीकार करने में सरकार को क्या दिक्कतें हैं ?

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**---कपड़ा उद्योग सारे देश भर का उद्योग है केवल उत्तर प्रदेश का नहीं और चूंकि केन्द्रीय सरकार ने कपड़ा उद्योग के सम्बन्ध में एक वेज बोर्ड बैठा रखा है और उस के सामने कानपुर का भी मामला है इसलिये यह उचित नहीं समझा गया कि तावक्ते फैसला इस बोर्ड के, हम बीच में वेज स्ट्रक्चर, वर्कलोड स्ट्रक्चर नये इंट्रोड्यूस कर दें। इस से दिक्कत हो सकती थी, दिक्कत हल होने का सवाल नहीं पैदा हो सकता था।

**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)---क्या माननीय मंत्री महोदय बताने का कष्ट करेंगे कि इस रेशनलाइजेशन की योजना के लागू होने के समय मंत्री जी की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि इसके लागू होने पर मजदूरों पर जो वर्कलोड बढ़ेगा उसके हिसाब से वेतन में बढ़ोत्तरी की जायगी, लेकिन अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मैं यह स्वीकार नहीं करता कि जहां काम बढ़ा वहां वेतन नहीं बढ़ा। वेतन बढ़ा लेकिन उस हिसाब से जिस हिसाब से मालिक बढ़ाना चाहते थे। प्रश्न हमारे सामने था विन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट की सिफारिश के मुताबिक वेतन और कार्यभार बढ़ा या नहीं, वह नहीं हुआ। लेकिन आश्वासन के सम्बन्ध में जो उद्धरण मैंने पढ़ा उससे स्पष्ट है कि उस जमाने में रेशनलाइजेशन के सम्बन्ध में या वेतन क्रम के सम्बन्ध में या कार्यभार के सम्बन्ध में कोई इस तरह की बात सरकार की तरफ से नहीं की गयी।

**श्री भगवतीसिंह विशारद**---क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि इस विन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने के सिलसिले में आखिरी बार कब त्रिदलीय सम्मेलन में इस सम्बन्ध में वार्ता हुई और उसको क्यों नहीं अब तक लागू किया गया ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मान्यवर, यह त्रिदलीय सम्मेलन रानीखेत में हुआ था। उसमें इस पर विचार किया गया था। लेकिन इस त्रिदलीय सम्मेलन को यह बता दिया गया था कि केन्द्रीय सरकार के श्रम मंत्रालय द्वारा हमारे पास यह सिफारिश आयी थी कि चूंकि इंडियन लेबर कांफरेंस जो कि उसके बाद १५ अगस्त तक होने वाली थी दिल्ली में, वह इस पर विचार कर रही थी और हम अपने प्रदेश में अकेले इस सम्बन्ध कोई फैसला न लें। त्रिदलीय सम्मेलन में जो केन्द्रीय सरकार की सलाह थी, एक मत से स्वीकार की गयी और उसमें विन्ध्यवासिनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के लागू करने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया गया।

**श्री उमाशंकर शुक्ल**---क्या यह सही है कि एलगिन मिल मुनाफे पर चल रही है और मुनाफे पर चलने के बाद भी विन्ध्यवासनी प्रसाद कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वहां मजदूरों को वेतन नहीं दिया जा रहा है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मैं इससे इन्कार नहीं करता कि एलगिन मिल मुनाफे पर चल रही है लेकिन जैसा मैंने निवेदन किया कि कपड़ा मिलों में काम करने वाले मजदूरों का वेतन क्रम और कार्यभार, वेजेज ऐन्ड वर्कलोड, आल इन्डिया बेसिस पर होने जारहा है इसलिये इस बीच में यदि हम कोई बात करें तो वह इस प्रदेश के इस उद्योग के हित में नहीं होगा।

## दीक्षितों में बेकारी

*७---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)---क्या यह सही है कि प्रदेश में दीक्षित (स्किल्ड) बेकारों की संख्या बढ़ रही है ? अगर हां, तो क्यों ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---इसका कोई प्रमाण नहीं है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या सरकार ने दीक्षित बेकारों के आंकड़े रखने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था की है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मान्यवर, जो लड़के स्किल्ड ट्रेड्स में सीखकर बाहर निकलते हैं उसकी सूचना हमारे पास है और उसमें से बहुतों को काम मिलता है। इस सम्बन्ध में मैं इतना निवेदन कर दूं कि अभी हमने कानपुर क्षेत्र में इस बात की इम्पलायमेन्ट मार्केट स्टडी करवाई थी और उसके जो नतीजे हमारे पास आते हैं उससे मालूम होता है कि यही नहीं कि सब को काम मिल गया बल्कि टर्नर्स, वेल्डर्स, ऐलेक्ट्रिशियन्स, मेकेनिक्स, रेडियो इन्जीनियर, ऐलेक्ट्रिकल ऐन्ड मेकेनिकल इन्जीनियर्स, ड्राफ्ट्समैन, केबिल ज्वाइन्टर्स, इस तरह की ट्रेड्स के बहुत से लोगों की भारी संख्या में कमी है, हमारे प्रदेश में और जो स्टडी से हमको अनुभव प्राप्त हुआ है उससे हम समझते हैं कि उनके लिये काम की कमी नहीं है जोकि स्किल्ड कैटेगरी में निकल कर आते हैं।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---कानपुर में सरकार ने जो आकड़े एकत्र किये हैं क्या उनसे सरकार को यह भी मालूम हुआ कि दीक्षित बेकारों की कुछ श्रेणियां ऐसी हैं जिनकी बहुत बड़ी संख्या बेकार पड़ी है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जी नहीं, ऐसे लोगों को जिनको हम इस तरह की स्किल्ड कैटेगरी में रखते हैं उनके लिये बाजार में बहुत बड़ी जगह है।

**राजा यादवेन्द्र दत्त दुबे** (जिला जौनपुर)---जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि उनके पास आंकड़े हैं स्किल्ड लोगों के तो क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि कितने स्किल्ड अनइम्प्लायड थ और कितनों को इम्पलायमेन्ट मिला ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मैंने यह निवेदन किया था कि जितने सीखकर हर साल निकलते हैं उनके आंकड़े हैं, कितनों को काम मिल गया, इसके आंकड़े नहीं हैं लेकिन कानपुर में स्टडी के आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि इस तरह के लोगों के लिये काम की कमी नहीं है।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि दीक्षित बेकारों की संख्या घटने और बढ़ने के बारे में सूचना रखने के लिये सरकार इस बात की व्यवस्था करेगी कि प्रदेश के स्तर पर उनके आकड़े रखे जायं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---कानपुर की तरह जो स्टडी हमने वहां की है उसको हम सारे प्रदेश में लागू करने जा रहे हैं और आशा है कि इस स्टडी के नतीजों से हमें इस सम्बन्ध में उचित जानकारी मिल सकेगी।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि इम्पालायमेन्ट एक्सचेन्ज में स्किल्ड अनइम्पलायड का रजिस्ट्रेशन जो होता है उससे पता चला है कि पिछले वर्षों में उनको जगह दिलाये जाने में कमी हुई है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मैं आपके द्वारा नारायणदत्त जी से निवेदन कर दूं कि इम्पालायमेन्ट एक्सचेन्ज के रजिस्टर में स्किल्ड कहे जाने वाले लोगों में पढ़े-लिखे लोग भी स्किल्ड कहे जाते हैं। उनकी परिभाषा में एक स्किल्ड और दूसरे टेक्निकल पर्सोनल कहे जाते हैं। स्किल्ड में हमारे और नारायणदत्त जी जैसे ग्रेजुएट लोग भी आते हैं और इस तरह के लोगों में बहुत बड़ी संख्या बेकार है।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज द्वारा जो फीगर्स अनइम्पलायड की रखी जाती थी उसमें इस प्रकार की व्यवस्था थी कि स्किल्ड लेबर की लिस्ट अलग से रखी जाय ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जी हां, जैसा मैंने निवेदन किया कि स्किल्ड लोगों में हाई स्कूल, इन्टरमीडिएट वगैरह आते हैं और टेक्निकल पर्सोनल में टर्नर, फिटर, कारपेन्टर, ब्लैकस्मिथ वगैरह शामिल हैं।

## आजमगढ़ जिले के लिये वृद्धावस्था की पेन्शन की स्वीकृति

*८---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला आजमगढ़ में इस समय तक कितने व्यक्तियों की वृद्धावस्था की पेन्शन स्वीकार की गई है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जिला आजमगढ़ में अब तक (२०-१-५९ तक) ८० व्यक्तियों की पेंशन स्वीकृत की गई।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि कितने प्रार्थना-पत्र कुल आये, कितने खारिज हुये और कितने विचाराधीन हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---२३९ आये थे, १५१ जिलाधीश ने खारिज किये, ८५ पर उन्होंने सिफारिश करके श्रम आयुक्त को भेजे। उन्होंने ८० को दे दिया, ३ को खारिज किया और २ को पुनः विचार के लिये जिले में भेजा है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---सबसे बड़ी रकम एक व्यक्ति को कितनी दी गई ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---पहले भी मैंने कहा था कि सबके लिये १५ रुपये महीना है, कम ज्यादा नहीं है।

*९-१०---**श्री हरदयाल सिंह** (जिला शाहजहांपुर)---[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## मद्यनिषेध अधिकारी

*११---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (जिला सीतापुर) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९४८-४९ में कितने मद्यनिषेध अधिकारी नियुक्त किये गये थे ?

**परिवहन मंत्री (डाक्टर सीताराम)**---६।

*१२---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---इन मद्य-निषेध अधिकारियों में से कितने अधिकारी स्थायी (Confirm) किये गये ?

**डाक्टर सीताराम**---५।

*१३---**श्री गनेशीलाल चौधरी** (अनुपस्थित)---इन अधिकारियों में से कितने अधिकारी हरिजन थे और उनमें से कितनों को स्थायी बनाया गया और कब ?

**डाक्टर सीताराम**---१ स्थायी। १ अप्रैल, १९५८ से।

## खेल-कूद के शिक्षक

*१४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसने उत्तर प्रदेश में खेल-कूद की कोचिंग के लिये कोच (शिक्षक) नियुक्त किये हैं ?

नियोजन उपमंत्री (श्री सुल्तान आलम खां)--जी हां ।

*१५--श्री कल्याणचन्द मोहिले--ये शिक्षक कितने हैं, इनका वेतन कितना है तथा इनकी नियुक्ति कैसे होती है ?

श्री सुल्तान आलम खां--पांच शिक्षकों का वेतन क्रम २००-१५-३५०-२०-४५० रुपये है । एक सहायक शिक्षक है, जिसका वेतन-क्रम १००-१०-१६०-१५-२५० रुपये है ।

उत्तर प्रदेश खेल-कूद परिषद् ने देश के खेल-कूद विशेषज्ञों से उक्त पदों के लिए प्रार्थना-पत्र आमंत्रित किये थे । परिषद् की मंत्रणा समिति ने, इन प्रार्थना-पत्रों पर विचार किया तथा नियुक्ति के लिये, उपयुक्त नामावली, परिषद् के सचिव तथा सभापति के समक्ष प्रस्तुत की । सचिव तथा सभापति की स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर इनकी नियुक्ति की गई ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस खेलकूद परिषद् की स्थापना कब हुई और उसके सभापति और मंत्री कौन हैं ?

श्री अध्यक्ष--इसके लिये स्वतंत्र प्रश्न होना चाहिये ।

श्री चन्द्रजीत यादव--इन शिक्षकों का कार्यक्षेत्र क्या है और वे किन-किन खेलों का प्रशिक्षण देते हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--एक हाकी के लिये, एक वालीबाल के लिये, एक बास्केट-बाल के लिये, एक स्विमिंग के लिये और एक टैनिस के लिये हैं । एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी टैनिस के हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इन शिक्षकों के लिये क्या क्वालिफीकेशन्स रखी गई थीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--कोशिश यह की गई थी कि जो स्पोर्ट्स के प्रेमी हों उन्हें इसमें रखा जाय । जो बेहतरीन स्किल हमको मिल सकी उसे हमने हासिल करके नियुक्त किया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--भारतीय व्यायाम के लिये कोई शिक्षक क्यों नहीं है ?

श्री सुल्तान आलम खां--एक हाकी के लिये, एक वालीबाल के लिये, एक बास्केट-बाल के लिये, एक स्विमिंग के लिये और एक टैनिस के लिये हैं । एक असिस्टेंट इंस्ट्रक्टर भी टैनिस के हैं ।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--इन शिक्षकों के लिये क्या क्वालिफीकेशन्स रखी गई थीं ?

श्री सुल्तान आलम खां--कोशिश यह की गई थी कि जो स्पोर्ट्स के प्रेमी हों उन्हें इसमें रखा जाय । जो बेहतरीन स्किल हमको मिल सकी उसे हमने हासिल करके नियुक्त किया ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--भारतीय व्यायाम के लिये कोई शिक्षक क्यों नहीं है ?

श्री सुल्तान आलम खां--सरेदस्त जैसी जरूरत थी रख लिये गये । मौका आने पर उसके लिये भी रख लिये जावेंगे । यह काम बढ़ता हुआ ही है ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले--क्या यह सही है कि यू० पी० काउंसिल आफ स्पोर्ट्स की देखरेख के लिये एक आनरेरी अफसर की नियुक्ति की गई है जो एक रिटायर्ड सरकारी नौकर हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां--नोटिस चाहिये ।

श्री रामस्वरूप वर्मा--क्या इन शिक्षकों की भर्ती के लिये एडवर्टाइज किया गया था ?

श्री सुल्तान आलम खां--स्पोर्ट्स के अच्छे से अच्छे प्रेमी हासिल करने के लिये सभी कोशिशें की गईं ।

## द्वितीय पंचवर्षीय योजना का पुनरीक्षण

*१६---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या प्लानिंग कमीशन के आदेश पर अभी हाल ही में प्रदेश की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कुछ कटौती की गई है ? यदि हां, तो किस विभाग में कितने की ?

श्री सुल्तान आलम खां---जी नहीं ।

*१७---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त कटौती के आधार पर माताटीला, रिहन्द आदि सिंचाई एवं बिजली की बड़ी योजनायें स्थगित कर दी गई हैं ?

श्री सुल्तान आलम खां---प्रश्न नहीं उठता।

*१८---श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या सरकार ने तृतीय पंचवर्षीय योजना बनाये जाने की तैयारी शुरू कर दी है ?

श्री सुल्तान आलम खां---तृतीय पंचवर्षीय योजना के बनाने के लिये कुछ प्रारम्भिक कार्य शुरू किया गया है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि कटौती न होने पर रामगंगा प्रोजक्ट और पूर्वी जिलों की बाढ़ नियंत्रण योजना में और पी० डब्ल्यू० डी० में सड़कों में ५० लाख रुपये की कमी अनुदान में क्यों की गई ?

श्री सुल्तान आलम खां---अक्तूबर, १९५८ में प्लान को रिवाइज किया गया था। उसकी वजह से कुछ कामों को स्लो-डाउन किया गया, कुछ को ड्राप किया गया और कुछ को आगे बढ़ाया गया है । मसलन्, रिहंड डैम प्लान की कोर में आ गया है और उसके ४६ करोड़ के खर्चे में से ३४.३८ करोड़ रुपया हम इस प्लान में खर्च कर रहे हैं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---इस रिवीजन में पुरानी प्लान की किन आइटमों को काटा गया और किन-किन मुख्य आइटमों को बढ़ाया गया ?

श्री सुल्तान आलम खां---मुख्य आइटम कोई नहीं कटी है । प्लान का वह हिस्सा जो स्लो-डाउन किया गया है इर्रीगेशन में, यह है । रामगंगा रीवर प्रोजैक्ट, जिरगो रिजर्वायर, नानक सागर, मेजा रिजर्वायर, कुवानो पम्प्ड कैनाल और सारदा सागर स्टेज २। पावर में ड्राप होने वाले ये हैं---पावर डिस्ट्रीव्यूशन सेंटर अलीगढ़ में, स्टाफ क्वार्टर एंड अदर बिल्डिंग्स आफ शैड्यल डी हाइडिल ग्रिड, इन्सटालेशन आफ न्यू इक्विपमैंट ऐट चन्दौसी, स्माल हाइडिल स्कीम्स इन हिल डिस्ट्रिक्ट्स, युमना हाइडिल स्कीम्स, पायलट हायडिल पावर स्टेशन इन बुन्देलखंड ट्रांसमिशन लाइन्स, न्यू स्टीम स्टेशन फार सप्लाई टु गढ़वाल, रामगंगा रीवर प्रोजैक्टर। पावर में स्लो-डाउन होने वाली ये हैं---गंगा ट्रांसमिशन लाइन्स स्टेज फोर, न्यू स्टीम स्टेशन एट हरदुआगंज, इलैक्ट्रिफीकेशन आफ स्टेट ट्यूबवैल्स ड्यूरिंग सैकिन्ड फाइव ईयर प्लान।

श्री नारायणदत्त तिवारी---स्लो-डाउन या रिवाइज की गई स्कीमों से प्लान के टोटल आउटले में कितनी कमी या बढ़ोत्तरी हुई है ?

श्री सुल्तान आलम खां---आउटले में कोई कमी नहीं हुई है ।

## गन्ने का मूल्य बढ़ाने के लिये विधान सभा का प्रस्ताव

*१९—**श्री सजीवनलाल** (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत गन्ने के न्यूनतम मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव के सम्बन्ध में अब तक केन्द्रीय सरकार से क्या बातचीत हुई है और क्या केन्द्रीय सरकार विधान सभा के उक्त प्रस्ताव की सिफारिश को मानने को तैयार है या नहीं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा स्वीकृत गन्ने के न्यूनतम मूल्य सम्बन्धी प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि केन्द्रीय सरकार को भेज दी गई थी। गन्ने का न्यूनतम मूल्य केन्द्रीय सरकार द्वारा एक सीजन पूर्व निर्धारित किया जाता है। समाचार-पत्रों से विदित हुआ है कि केन्द्रीय सरकार १९५७–५८ तथा १९५८–५९ सीजन के लिये नियत किये गये न्यूनतम गन्ने के मूल्य को बढ़ाने के लिये तैयार नहीं है। गन्ने के न्यूनतम मूल्य न बढ़ाने के कारणों पर समय-समय पर प्रकाश डाला जा चुका है।

*२०—**श्री सजीवन लाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १९५८–५९ के वर्ष में कितने एकड़ पर गन्ना बोया गया और अनुमानतः इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में कितना गन्ना पैदा हुआ? किन जिलों में इस वर्ष गन्ने की पैदावार गत वर्ष की तुलना में अधिकतम हुई है?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—वांछित सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

*२१—**श्री सजीवनलाल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार उत्तर प्रदेश में कोल्हू या क्रशर लगाने या चलाने पर पूरे राज्य या कुछ जिलों या कुछ क्षेत्रों में कोई रोक लगाने या गुड़ तथा खंडसारी के उत्पादन में चीनी मिलों के रिजर्व क्षेत्र के गन्ने के बढ़ते हुये हुये इस्तेमाल को रोकने के लिये कोई कदम उठाने पर विचार कर रही है?

**श्री डाक्टर सम्पूर्णानन्द**—इस सम्बन्ध में जो कदम उठाया गया है उसकी सूचना हाल ही में सदन के सामने आ चुकी है।

## देवरिया जिले में बनवारी टोला और बरवा जंगल के गन्ना केन्द्र

*२२—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह बतायेगी कि क्या देवरिया जिले के परचेजिंग सेन्टर सिसवा बनवारी टोला तथा बरवा जंगल कांटे पर गन्ने की तौल नहीं हो रही है जब कि सन् १९५८–५९ सीजन के लिये कांटा लग चुका है? यदि हां, तो क्यों।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—देवरिया जिले के बनवारी टोला और बरवा जंगल कांटे पर गन्ने की तौल क्रमशः दिनांक १०–१२–५८ तथा ७–१२–५८ से हो रही है। सिसवा में कोई गन्ना क्रय केन्द्र नहीं है, अतः उक्त स्थान पर कांटा लगने या गन्ने की तौल होने का प्रश्न नहीं उठता।

*२३—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उक्त कांटे का गन्ना पिछले सीजन १९५७–५८ ई० में किस मिल को दिया गया था और सीजन १९५८–५९ के लिये किस मिल को दिया गया है?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—गत १९५७–५८ सीजन में बरवा जंगल तथा बनवारी टोला कांटे का गन्ना देवरिया शुगर मिल, देवरिया को पेराई के लिये दिया गया था और वर्तमान सीजन में उक्त कांटे का गन्ना क्रमशः रामकोला (पी) तथा रामकोला (खेतान) चीनी मिलों को पेराई के लिये दिया गया है।

*२४—**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि क्या उक्त कांटा क्षेत्र के किसानों ने अपना क्षेत्र देवरिया मिल से अलग करने के लिये कोई प्रार्थना-पत्र सरकार को दिया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ।

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—उक्ट कांटा क्षेत्र के किसानों से ऐसा कोई प्रार्थना-पत्र प्राप्त नहीं हुआ है ।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या मंत्री महोदय बतावेंगे कि यह नई व्यवस्था मुस्तकिल की गई है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—कोई व्यवस्था मुस्तकिल होती नहीं, सीजन के लिये की गई है ।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या वहां के किसानों ने शिकायत की थी कि देवरिया मिल उनसे अधिक काटती है और नयी व्यवस्था में कम है, इसलिये नई व्यवस्था को मुस्तकिल कर दिया जाय ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—गन्ना उत्पादक और मिल वालों के दोनों के हित में यह व्यवस्था है, सो की गई । भविष्य में फिर विचार किया जायगा ।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—उक्त कांटों का गन्ना जब पहले देवरिया में आता था और बाद में रामकोला को दिया गया, तो बीच में किसानों के नुक्सान की जिम्मेदारी किसकी है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—किसानों को कोई हानि नहीं हुई ।

**श्री ब्रजनारायण तिवारी**—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस वक्त वर्तमान भाड़े में क्या कटौती होती है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—भाड़े की कटौती जो चल रही है वह नियमानुकूल है, ज्यादा कम का प्रश्न नहीं उठता ।

*२५–२७—**श्री मुक्तिनाथ राय**—[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

## साहू केमिकल्स यूनिट, वाराणसी को दिया गया ऋण

*२८—**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)— क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या वह साहू जैन कैमिकल्स फैक्टरी, वाराणसी को दिय गये एक करोड़ ४५ लाख के ऋण की वसूलयाबी में अब तक कोई रकम प्राप्त कर चुकी है और कब तक उस ऋण के बेवाक होने की आशा करती है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—(क) इस नाम की कोई फैक्टरी को सरकार ने ऋण नहीं दिया है । सम्भवतः माननीय सदस्य का तात्पर्य न्यू सेन्ट्रल जूट कम्पनी लि०, कलकत्ता की वाराणसी में स्थित (साहू केमिकल्स) यूनिट (unit) से है । यदि यह खयाल सही है तो उपरोक्त कंपनी को जो १.४५ करोड़ रुपये ऋण दिया गया था उसकी वसूलयाबी में अभी तक कोई रकम प्राप्त नहीं हुई है ।

(ख) सितम्बर, १९६७ तक ।

**श्री देवनारायण भारतीय**— क्या सरकार बतायेगी कि ऋण देते समय इस कम्पनी से उसका कोई इकरार हुआ था ? यदि हां, तो उसके अनुसार ऋण की अदायगी कब से शुरू होने वाली है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**— पहला इंस्टालमेंट १ मार्च, १९५८ से शुरू हो जाना चाहिये था और १९६७ तक, जैसा मंने कहा पूरा का पूरा पेमेन्ट हो जाना चाहिये ।

**श्री देवनारायण भारतीय**—१ मार्च, १९५८ को पहला इंस्टालमेंट देना चाहिये, लेकिन अब मार्च, १९५९ भी हो गया तो भी कम्पनी ने अभी तक कोई किस्त अदा क्यों नहीं की ?

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**—क्योंकि सरकार इस बात से संतुष्ट थी कि उस कंपनी को काम चालू करने में इस बात से कठिनाई हुई कि उस के लिये जमीन लेने के संबंध में मामला हाई कोर्ट में चला गया जो १८ अक्तूबर, १९५७ को फैसल हुआ, उसके बाद उनको कब्जा मिला। और इसलिये इस स्थिति में थे ही नहीं, अतः सरकार ने भी उनके ऊपर जोर नहीं डाला।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**— क्या सरकार इस बात को देखते हुये कि उस कम्पनी के बोर्ड आफ डायरेक्टर्स में दो सरकारी नामिनी उच्चाधिकारी हैं, सरकार इस बात का उनको आदेश देगी कि उस कंपनी की आर्थिक हालत ठीक रहे ताकि सरकार का रुपया समय पर मिल सके और ऋण भी अदा हो सके ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—इस बात की पूरी व्यवस्था है कि कंपनी की हालत ठीक रहे। इस कम्पनी के लग जाने से बहुत सारे उद्योगों की हालत और लोगों की हालत सुधरेगी। सरकार का रुपया जाने वाला नहीं है, यह पूरे तरह से कब्जे में है।

**श्री देवकीनन्दन विभव** (जिला आगरा)—क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि इस कम्पनी के कार्य में अब तक क्या प्रगति हो चुकी है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—अभी तो कंस्ट्रक्शन का फेज चल रहा है और बड़ी तेजी से चल रहा है। वहां की स्थानीय कमेटी जब बैठी थी तो मेरी वहां के एक जर्मन टेक्नीशियन से बातचीत हुई। मैंने उससे पूछा कि हमारे यहां के कारीगर कैसा काम कर रहे हैं और अगर यह काम जर्मनी में होता तो उसके मुकाबले में यहां कैसा काम हो रहा है तो उसने बताया कि अच्छा काम हो रहा है और इतने ही दिनों में जर्मनी में हुआ होता, उसी शिड्यूल में पूरा हो रहा है।

**श्री चन्द्रजीत यादव**—जब कंपनी को ऋण दिया गया था तो उससे जो शरायत तय हुई थीं उनको उसने पूरा नहीं किया, इसके लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—जी नहीं, यह कहना गलत है। सब शर्तें पूरी हुई हैं सिवाय उसके जिसका अभी बयान किया गया कि कंपनी अपनी एक किस्त नहीं दे पायी, क्योंकि जमीन का मामला हाईकोर्ट में चला गया था। इसकी वजह से उसके लाइसेंस में देर हो गई और उसमें कंपनी का कोई हाथ न था।

**श्री देवनारायण भारतीय**—क्या सरकार बतायेगी कि इस कंपनी के किसी कारखाने को सरकार खरीदना चाहती थी, लेकिन अब सरकार ने अपने विचार को स्थगित कर दिया है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**—खरीदे जाने का कोई सवाल नहीं है। कंपनी ने एक प्रस्ताव रखा था। हमारे इंजीनियर ने उस को देखा लेकिन वह सौदा ठीक नहीं मालूम हुआ, इसलिये वह हमने नहीं लिया।

**श्री उग्रसेन**—क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि जो जायदाद सेंट्रल जूट मिल को साहू जैन केमिकल्स फैक्टरी के कर्जे के सम्बन्ध में सिक्योरिटी के तौर पर थी, उसे उसने वापस ले लिया है और अब उस कम्पनी की कोई जायदाद कर्जे की सिक्योरिटी में नहीं है ?

†**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**---माननीय वर, जिस वक्त हमने इस कम्पनी को कर्जा दिया तो तय हुआ कि सेन्ट्रल जूट मिल की जो जायदाद है उसको हमारे हाथ रेहन रखना होगा और उसने रेहन रखा। दूसरी शर्त यह थी कि जैसे-जैसे उसके एसेट्स यहां खड़े होने लगेंगे, कंस्ट्रक्शन होते जायेगा वैसे वैसे वहां की जूट मिल की जायदाद को छोड़ कर हम यहां के एसेट्स को अपने यहां रेहन रख लेंगे। इसके बावजूद भी कलकत्ता जूट मिल्स कंपनी की सम्पत्ति अभी तक हमारे यहां रेहन है, किन्तु कम्पनी ने वाराणसी स्थित साहू केमिकल्स की १,६०,४५,७०० रुपये की संपत्ति को बंधक करके उसी मात्रा में न्यू सेन्ट्रल जूट मिल्स कंपनी, कलकत्ता, की संपत्ति को मुक्त करने की मांग सरकार से की है और इस सम्बन्ध में यथोचित कार्यवाही की जा रही है।

**कुंवर श्रीपाल सिंह**---अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि जर्मनी में जितनी तेजी से काम होता है उसी के बराबर यहां भी काम हो रहा है, तो क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां के मजदूरों को मजदूरी भी उतनी ही दी जाती है, जितनी जर्मनी में मजदूरों को मिलती है ?

**श्री अध्यक्ष**---यह प्रश्न इससे उठता तो नहीं है, लेकिन आप चाहें तो उनके कौतूहल को दूर कर दें।

**श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा**---जर्मनी में पर कैपिटा आमदनी के अनुपात में जो वहां की मजदूरी है, उसके हिसाब से यहां की पर कैपिटा आमदनी के अनुपात में जो मजदूरी यहां दी जाती है वह बिलकुल सही है।

## हमीरपुर जिले के एक मैजिस्ट्रेट के विरुद्ध जस्टिस देसाई का लांछन

*२९---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या यह सही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश, देसाई महोदय ने नवम्बर, १९५८ को २४ या २५ तारीख को प्रादेशिक सरकार को लिखा है कि हमीरपुर के एक मैजिस्ट्रेट ने एक मुकदमें में न्याय को विपथ या फरीकों को परेशान करने वाली और सार्वजनिक श्रम तथा समय को नष्ट करने वाली कार्यवाही की, सरकार को चाहिये कि ऐसी कार्यवाहियों को रोकने के लिये कदम उठायें ? सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायाधीश श्री देसाई ने हमीरपुर जिले के एक मामले में यह बात कही। जहां तक मजिस्ट्रेट का प्रश्न है, उसके विरुद्ध उचित कार्यवाही हो रही है।

*३०---**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या यह सही है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश देसाई महोदय ने इन्हीं दिनों में यह टिप्पणी की है कि प्रदेश में ऐसे कई प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट हैं जो प्रारम्भिक बातें भी नहीं जानते तथा अपने अज्ञान पर कायम रहते हैं ? अगर हां, तो सरकार इसे दूर करने के लिये क्या कर रही है या क्या करने जा रही है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी हां। मेरठ जिले के एक मामले में न्यायाधीश श्री देसाई ने ऐसा कहा है। ऐसे मामले सरकार के पास बहुत कम आये हैं। सरकार ने इन कठिनाइयों को दूर करने के लिये ही आफीसर्स ट्रेनिंग स्कूल की स्थापना की है, ताकि अधिकारियों को समुचित शिक्षा मिल सके तथा वे इस प्रकार की गलतियां न कर सकें। आगे के लिये प्रयत्न हो रहा है कि प्रथम श्रेणी के मैजिस्ट्रेट के अधिकार अनुभव प्राप्त हो जाने पर ही दिये जायं।

---

†१९ मार्च, १९५९ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---क्या माननीय मुख्य मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जो कार्यवाही की जा रही है वह किस अधिकारी द्वारा की जा रही है और वह हुई है अभी तक या नहीं हुई है ? हुई है तो क्या हुई है और नहीं हुई है तो कब तक हो जायगी ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---कार्यवाही का स्टेज यह है कि उनका एक्सप्लेनेशन तलब किया गया है, अभी तक उनके एक्सप्लेनेशन पर गौर नहीं हो सका है ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**--- इस अधिकारी के अलावा न्यायाधीश देसाई ने यह रिमार्क दिया है कि आमतौर पर इस तरह की गलतियां होती हैं, तो उसको रोकने के लिये सरकार ने कोई कार्यवाही की है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---मैं किसी न्यायाधीश ने जो कुछ कहा उसकी आलोचना तो नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो इसमें एक वाक्य उत्तर में लिखा है उसकी तरफ माननीय सदस्य खयाल करें । इसमें लिखा है कि हमारे सामने ऐसे मामले बहुत कम आये हैं । इसका तात्पर्य यह है कि आमतौर से उत्तर प्रदेश में मैजिस्ट्रेट्स ऐसी गलतियां करते हैं, इसका ज्ञान हमें नहीं है । माननीय देसाई के सामने ऐसे मामले आये होंगे । आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो खुला है उसमें खासतौर पर प्रोसीजर आदि की शिक्षा दी जाती है, ताकि जो थोड़ी बहुत गलतियां होती भी हैं वे न हों ।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल**---जैसा कि माननीय देसाई ने बतलाया है, और भी कई जगह ऐसी गलतियां होती हैं, तो ऐसी कार्यवाही को रोकने के लिये कोई कदम उठाया गया है या नहीं उठाया गया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---अगर इस तरह की कोई गलती होती है तो कार्यवाही तो होती ही होगी, लेकिन ऐसे उदाहरण बहुत कम हमारे सामने आये हैं । फिर भी हम आशा करते हैं कि आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में शिक्षा पाने के बाद और ऐसी कार्यवाही होने के बाद लोगों को शिक्षा मिल जायगी ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या यह सही है कि आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल जो हमारे प्रदेश में कई साल से काम कर रहा है, वही स्कूल है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--- जी हां, बिलकुल वही स्कूल है ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**---क्या सरकार कोई नया प्राविधान आफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल के सिलेबस में करने जा रही है जिसकी वजह से ऐसा उत्तर दिया गया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--- खास तौर से ध्यान दिया जाता है, प्रोसीजर जो अदालतों का होता है उसकी तरफ ध्यान दिला दिया जाता है ।

*३१---**श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी**--- [माननीय सदस्या की प्रार्थना पर १२ मार्च, १६५६ के लिए स्थगित किया गया । ]

## सिविल ड्राफ्ट्समैन की डिग्री

*३२---**श्री जगदीश शरण अग्रवाल** (जिला बरेली) (अनुपस्थित)--- क्या उत्तर प्रदेश सरकार के केन्द्रीय सरकार के Directorate General of Resettlement and Employment, Ministry of Labour, New Delhi, द्वारा संचालित विद्यालयों (जैसा एक रामपुर में भी है) द्वारा प्रदत्त सिविल ड्राफ्ट्समैन (Draftsman) की डिग्री प्राप्त करे हुए व्यक्ति को ड्राफ्ट्समैन (Draftsman) की नौकरी के लिये योग्य (qualified) नहीं मानती है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जी हां । किन्तु यह प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ।

*३३---श्री जगदीशशरण अग्रवाल (अनुपस्थित)--- क्या सरकार ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि उन सारे Draftsmen को जो रुड़की की डिग्री नहीं रखते हैं या अन्यथा unqualified हैं निकाल कर उनके स्थान पर अविलम्ब रुड़की के पासशुदा Draftsmen रक्खे जायं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी नहीं।

## कानपुर की बन्द मिलें

*३४---श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कानपुर में कितनी मिलें पूर्णतया बन्द पड़ी हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---इस समय कानपुर में निम्नलिखित मिलें पूर्णतया बन्द पड़ी है :--

१---न्यू कानपुर फ्लावर मिल्स, कानपुर ।

२---राजेन्द्र प्रसाद आयल मिल्स, कानपुर।

३---प्रह्लादराय आयल मिल्स, कानपुर ।

४---कुंज बिहारी आयल मिल्स, कानपुर ।

५---जे० के० वुलेन मैनुफैक्चरर्स लिमिटेड, कानपुर।

६---बी० आई० सी० लिमिटेड, कानपुर, काटन मिल्स ब्रांच, कानपुर।

इनके अतिरिक्त बी० आई० सी० लिमिटेड, कानपुर काटन मिल्स, जूही ब्रांच, कानपुर सन् १९५४ में व जे० के० होजरी फैक्टरी लिमिटेड कानपुर, सन् १९५३ में बन्द हो गई थी।

*३५---श्री झारखंडे राय---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इस समय कानपुर में कितनी ऐसी मिले हैं जो आंशिक रूप से बन्द हैं और उनमें कितनी कपड़ा मिलें हैं ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---जिन मिलों में कुछ विभागों की कुछ पालियां बन्द हुई हैं या जिनके कुछ विभाग आंशिक रूप से बन्द हुये हैं उनके नाम इस प्रकार हैं :

१---स्वदेशी काटन मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।

२---जे० के० काटन स्पीनिंग एन्ड वीविंग मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।

३---कानपुर टेक्सटाइल्स लिमि०, कानपुर ।

४---म्योर मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।

५---लक्ष्मी रतन काटन मिल्स कं० लिमि०, कानपुर ।

६---जे० के० काटन मैनुफैक्चरर्स लिमि०, कानपुर ।

७---कान्टीनेन्टल इंजीनियरिंग वर्क्स, कानपुर ।

८---प्रकाश यू० पी० दाल मिल्स, कानपुर।

इनमें से ६ कपड़ा मिलें हैं।

*३६---श्री झारखंडे राय---क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि कानपुर की मिलों के पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बन्द होने से किस-किस मिल में कितने-कितने कुल मजदूर बेकार हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---कानपुर की मिलों के पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से बन्द होने में बेकार हुये मजदूरों का विवरण निम्नलिखित है :

| | | |
|---|---|---|
| १---न्यू कानपुर फ्लावर मिल्स, कानपुर | .. .. | ४०० |
| २---राजेन्द्र प्रसाद आयल मिल्स, कानपुर | .. .. | ४० |
| ३---प्रहलाद राय आयल मिल्स, कानपुर | .. .. | २४ |
| ४---कुंज बिहारी आयल मिल्स, कानपुर | .. .. | १८ |
| ५---जे० के० वुलेन मैनुफैक्चरर्स लिमि०, कानपुर | .. .. | २५० |
| ६---बी० आई० सी० लिमि०, कानपुर काटन मिल्स ब्रांच, कानपुर | .. | ३,६३२ |
| ७---स्वदेशी काटन मिल्स कं० लिमि०, कानपुर | .. .. | ३० |
| ८---कानपुर टैक्सटाइल्स लिमि०, कानपुर | .. .. | ७३ |
| ९---जे० के० काटन मैनुफैक्चरर्स लिमि०, कानपुर | .. .. | २३० |
| १०---प्रकाश यू० पी० दाल मिल्स, कानपुर | .. .. | २७ |
| योग | .. | ४,७२४ |

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या माननीय मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि कानपुर में इतनी बड़ी संख्या में कपड़ा मिलों के बन्द होने का क्या कारण है और इस सम्बन्ध में सरकार क्या करने जा रही है ?

**श्री हेमवती नन्दनबहुगुणा**---मान्यवर, कानपुर की मिलों की बन्दी के सम्बन्ध में इस सदन में कुछ महीनों पहले विचार हुआ था । सब कारणों पर प्रकाश डालने के साथ प्रश्नों का जो समय है वह सारा निकल जायगा । सिर्फ इतना कह सकता हूं कि कपड़ा उद्योग में सारी दुनियां में जो डिप्रेशन आया और उसका जो असर हमारे देश व प्रदेश पर पड़ा है लड़ाई के बाद और हमारी कानपुर की मिलों का जो पुराना ढांचा है वह इन सबका जिम्मेदार है कि कपड़ा उद्योग हमारे यहां फ्लरिश नहीं कर रहा है और उसकी वजह से बुरा असर पड़ा रहा है कानपुर के मजदूरों पर । इसके पहले भी मैं बतला चुका था कि कानपुर में जो कपड़ा इकट्ठा होता जाता है उसकी तादाद इतनी अधिक है कि कोई मिल बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कपड़ा बनता रहे, इकट्ठा होता रहे और मिल चलती रहे । इन कारणों से कई मिलें बन्द हो गई हैं ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---क्या सरकार ने कोई इस प्रकार का निश्चय किया है कि कानपुर में जो कपड़े की मिलें बन्द हैं उनमें से कुछ मिलों का संचालन सरकार खुद करेगी और यदि हां, तो सरकार ने क्या किया ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---जैसा मुख्य मंत्री जी ने कुछ समय पूर्व सदन में और सदन के बाहर भी संकेत किया था, हमारा इरादा है कि हम एथर्टन वेस्ट को हाथ में लें । इस दिशा में कोशिश हो रही है और योजना भी बन रही है और अगर सब तरफ से सहयोग मिला तो उम्मीद है कि यह कार्य सम्पन्न हो जायगा ।

**श्री गैंदासिंह**---कितना कपड़ा इस वक्त कानपुर में पड़ा हुआ है और उसके न बिकने की क्या वजह है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---अलग-अलग मिलों की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है, लेकिन इतना कह सकता हूं कि कानपुर में इस समय काफी कपड़ा इकट्ठा है, यही मैं कह सकता हूं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**---क्या मंत्री जी को मालूम है कि कानपुर में एक मिल लिक्वीडेट किये जाने का विचार किया जा रहा है, उसका कारण क्या है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मुझे नहीं मालूम कौन मिल लिक्वीडेशन में जा रही है ।

**श्री गेंदासिंह**---कपड़ा न बिकने के कारण क्या हैं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---देश भर के बाजार में कपड़ा इतना ज्यादा है जितने खरीदार नहीं हैं । हमारे प्रदेश में जो कपड़ा बनता है वह कोर्स और मीडियम ज्यादा बनता है । पिछले दिनों में खाद्यान्नों के जो भाव बढ़े खास तौर से उसकी वजह से लोगों को कपड़ा खरीदने के सिलसिले में बहुत थोड़ा पैसा बचा जिसकी वजह से जो हमारे खरीदार थे वे कम हो गये । बाहर के मुकाबले में, जहां चार लूम पर काम करने वाले मजदूर काम करते हैं और अच्छी मशीनें हैं, हमारे यहां पुरानी जर्जर मशीनें हैं और उन से कम काम जो जर्जर मशीनों से हो सकता है हो रहा है । श्रमिकों का कोई दोष नहीं है । इन दोनों वजहों से अपने यहां कपड़ा उद्योग बाजार का बाहर के मुकाबले में गला घुट रहा है ।

**श्री चन्द्रजीत यादव**---इस सूचना के अनुसार ४,७२४ मजदूर कानपुर में बेकार पड़े हैं, इनको रोजी दिलाने के लिये सरकार अपनी तरफ से कोई कदम उठा रही है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---इन खास मजदूरों के लियें कोई खास योजना तो हमारे पास नहीं है, लेकिन कानपुर में पिछले सालों से और उद्योगों में बराबर वृद्धि हो रही है और वहां इंडस्ट्रियल ऐस्टेट भी बन रही है उनमें मजदूर खपेंगे ।

*३७-३९---**श्री शिवप्रसाद नागर** (जिला खीरी)---[गृह मंत्री से सम्बन्धित अट्ठाइसवें शुक्रवार के लिये प्रश्न संख्या १-३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## बांदा जिले में खनिज पदार्थों की खोज

*४०---**श्री जगपति सिंह** (जिला बांदा) (अनुपस्थित)---क्या मुख्य मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि बांदा जिले में जो भूगर्भ वेत्ता पिछले सितम्बर-अक्तूबर, १९५८ में निरीक्षण के लिये भेजे गये थे उन्होंने जिले के किन-किन स्थानों में कौन-कौन से खनिज पदार्थों के मिलने की रिपोर्ट दी है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---बांदा जिले में कामतानाथ, संग्रामपुर, बरतौल, मोहकमगढ़, मरजादपुर पहाड़ियों में सीमेंट बनाने योग्य लाइमस्टोन की जांच की गयी, परन्तु जांच से यह मालूम हुआ कि यह लाइमस्टोन सीमेंट बनाने के योग्य नहीं है । अन्य किसी खनिज पदार्थ की जांच नहीं की गई ।

*४१-४३---**श्री उग्रसेन**---[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये ।]

*४४---**श्रीमती शकुन्तला देवी** (जिला सहारनपुर)---[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

## गोंडा जिले में ऊख तौलने के कांटे

*४५---**श्री गंगाप्रसाद** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या जिला गोंडा, परगना महादेवा, तहसील तरबगंज के उत्तरी भाग में डुमरियाडीह पर ऊख तौलने का कोई कांटा नहीं है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---इस वर्ष जिला गोंडा, परगना महादेवा, तहसील तरबगंज के उत्तरी भाग में डुमरियाडीह के बजाय गांधी बस्ती में ऊख तौलने का कांटा लगाया गया है ।

*४६---**श्री गंगा प्रसाद** (अनुपस्थित)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला गोंडा में ऊख तौलने के कितने कांटे लगे हैं और किन स्थानों पर ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**--वर्त्तमान सीजन में गोंडा जिले में ऊख तौलाने के २७ कांटे जिन स्थानों पर लगे हैं उनका विवरण संलग्न पत्र में दिया हुआ है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ५६२ पर)

*४७--**श्री गोविन्द नारायण तिवारी** (जिला जालौन)--[२३ फरवरी, १९५९ को प्रश्न संख्या २४ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है ।]

## खेलकूद के लिये अनुदान

*४८--**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि प्रदेश में किन-किन संस्थाओं को खेलकूद बढ़ाने के लिये वित्तीय वर्ष १९५७-५८ में किस-किस रूप में और कितनी सहायता दी गयी ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--विवरण† माननीय सदस्य की मेज पर प्रस्तुत है ।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इस सूची में जो २३,००० रुपये का वितरण ६ संस्थाओं में हुआ है यह रजिस्टर्ड हैं या नहीं ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--यह तो मैं नहीं कह सकता कि रजिस्टर्ड हैं या नहीं ।

**श्री कल्याणचन्द मोहिले**--मंत्री जी बतायेंगे कि जो रुपया बांटा गया यह किसके द्वारा बांटा गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--कुछ रुपया तो स्पोर्ट्स काउन्सिल के द्वारा बांटा गया, कुछ जिले की जिला परिषद् के जरिये से बांटा गया और कुछ प्रान्तीय रक्षक दल के जरिये से बांटा गया ।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या यह सही है कि जो अनुदान स्पोर्ट्स काउन्सिल को डेवलप करने के लिये दिया जा रहा है इनसे खेलकूद का स्टैन्डर्ड ज्यादा इमप्रूव नहीं कर रहा है बल्कि गिर रहा है, क्रिकेट वगैरह में ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--मैं तो यह बात मानने के लिये तैयार नहीं हूं ।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**--क्या मंत्री जी बतायेंगे कि २३,००० रुपया जो बांटा गया यह प्रान्तीय रक्षक दल द्वारा कितना बांटा गया, कितना परिषद् द्वारा बांटा गया और कितना अन्य द्वारा बांटा गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--बड़ी लम्बी सूची है; अगर इजाजत हो तो पढ़ दूं ।

**श्री अध्यक्ष**--वह टोटल पूछना चाहते हैं कि कितना-कितना किसके द्वारा बांटा गया ।

**श्री सुल्तान आलम खां**--टोटल तो नहीं है; अगर माननीय सदस्य तकलीफ करके मेरे कार्यालय में आ जायं तो मैं बतला दूंगा ।

*४९--**श्री चिरंजीलाल जाटव** (जिला एटा)--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया ।]

## बलिया जिले के गजटेड अफसर

*५०--**श्री जगन्नाथ चौधरी** (जिला बलिया)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बलिया जिले में ऐसे कितने गजटेड आफिसर हैं जो उसी जिले के रहने वाले हैं ?

---

†विवरण छापा नहीं गया है ।

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---दो ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि ये २ व्यक्ति किस विभाग में किन पदों पर कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---एक तो हैं राजकीय बालिका विद्यालय, बलिया में प्रधान अध्यापिका, यह कोई ३-४ वर्ष से काम कर रही हैं । दूसरे हैं डाक्टर विजय बहादुर सिंह, पी० एम० एस० द्वितीय, मेडिकल आफिसर नव बरार, कोडरहा, जिला बलिया । यह ६-७ वर्ष से हैं ।

श्री जगन्नाथ चौधरी---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसका कोई ऐसा आदेश है कि गजटेड आफिसर अपने जिले में कार्य नहीं कर सकते । यदि हां, तो ये व्यक्ति किस नियम के अनुसार अपने जिले में कार्य कर रहे हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द---जी हां, साधारणतः ऐसा है कि अपने जिले में कोई कार्य नहीं करता, लेकिन जहां तक महिलाओं की बात है, उनके लिये नियम में थोड़ा-सा अपवाद रहता है, इसलिये कि औरतों के रहने के लिये सुरक्षित जगह हर जगह नहीं मिलती और उनके लिये थोड़ी रियायत होती है । बाकी पुरुषों के लिये रियायत नहीं होनी चाहिये । मुझको खुद देखकर ताज्जुब हुआ कि डाक्टर साहब अपने जिले में कैसे रह गये । बहरहाल, अब उनके ट्रांसफर का हुक्म चला गया है ।

## सीमांत क्षेत्र में ऊन के केन्द्र

*५१---श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि अल्मोड़ा, गढ़वाल तथा टेहरी-गढ़वाल के सीमान्त क्षेत्रों में ऊन के कारोबार सम्बन्धी योजना कब से चालू है और अभी तक इसमें क्या प्रगति हुई है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) सन् १९५५ से ।

(ख) प्रगति की सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ५६३ पर)

*५२---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या डिवीजनल सुपरिन्टेंडेन्ट का एक पद इन्डो-टिबटन ऊन योजना के लिये भी रक्खा गया है ? यदि हां, तो उनका हेडक्वार्टर कहां है ?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---(क) जी हां ।

(ख) अल्मोड़े में ।

श्री प्रताप सिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षण, उत्पादन और डिजाइन में सन् १९५७-५८ के मकाबले में १९५८-५९ में कमी हुई, उसका क्या कारण है?

श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा---डिजाइन में तो कमी हुई नहीं १९५७-५८ के मुकाबले में । डिजाइन का यह है कि जैसे-जैसे डिजाइन बनते जायेंगे अनलिमिटेड रिसोर्सेज तो हैं नहीं-धीरे-धीरे वह कुछ दिनों के लिये कम होते जाएगें । चार-पांच साल चलती है जो निकल जाती है । जहां तक बुनकरों का सम्बन्ध है, मैं खुद परेशान था । मैं इसकी जानकारी कर रहा हूं कि क्यों ऐसा हुआ ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५५ से लेकर ५८ तक बार्डर एरियाज के लिये क्या टारगट था ? वह पूरा हुआ या नहीं ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--६८० स्पिनर, १० वीवर हर ट्रेनिंग सेन्टर में बन रहे हैं। इस पंचवर्षीय योजना में हर साल का टारगेट यही है। टारगेट को देखा जाय तब तो हमारा काम हमारे कब्जे में है, लेकिन यह जरूर है कि ५७-५८ की जो प्रगति हैं उससे कुछ ऊंचा ही जाना चाहिये, कम नहीं होना चाहिये।

**श्री प्रतापसिंह**--क्या मंत्री जी इस तालिका को देखते हुए यह जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह जो प्रगति है वह प्रगति नहीं हुई बल्कि और गिरती जा रही है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**--जी हां, मैंने कहा कि इसको देखकर मुझे ऐसा लगा था। मैं कारणों की जांच करवा रहा हूं।

*५३--**श्री भीखालाल** (जिला उन्नाव)--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया। ]

*५४--**श्री बालकराम** (जिला शाहजहांपुर)--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

## गोरखपुर जिले को खेल कूद के लिये सहायता

* ५५--**श्री गौरीराम गुप्त** (जिला गोरखपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि विगत दो वर्षों के अन्दर गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में स्पोर्ट्स और गेम्स को बढ़ावा देने के लिये सरकार ने क्या किया है और इस काम पर इन दो सालों के अन्दर सरकार ने कुल कितना रुपया खर्च किया है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--सरकार ने गोरखपुर जिले में स्पोर्ट्स और गेम्स को बढ़ावा देने के लिये प्रत्येक तहसील में विगत दो वर्षों में खेलकूद प्रतियोगिताएं आयोजित की थीं तथा खेल कूद का सामान वितरित किया था। इस सम्बन्ध में, इन दो वर्षों में कुल २,९८३ रुपये ७ आने खर्च हुए।

**श्री गौरीराम गुप्त**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो २,९८३ रुपया ७ आना गोरखपुर जिले में दिया गया है, वह प्रत्येक तहसील में कितना-कितना दिया गया है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--सदर में १९५६-५७ में ३४३ रुपया, १९५७-५८ में १३० रुपया। बांसगांव में १९५६-५७ में ३४३ रुपया, १९५७-५८ में ३०० रुपया। महाराजगंज में १९५६-५७ में २५७ रुपया ४ आना, १९५७-५८ में १२५ रुपया। फरेंदा में १७१ रुपया ८ आना १९५६-५७ में और ७५ रुपया १९५७-५८ में।

**श्री गौरीराम गुप्त**--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले की फरेंदा तहसील में क्यों कम बांटा गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**--जैसी तहसीलों की जरूरत थी उसके हिसाब से बांटा गया। अगर माननीय सदस्य इसकी तरफ तवज्जह दिलाएंगे तो आइंदा खयाल रक्खा जाएगा।

## प्रशिक्षित ग्राम सेवकों की बेकारी

*५६--**श्री रामसुन्दर पांडेय**--क्या मुख्य मंत्री ४-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर के सम्बन्ध में बताने की कृपा करेंगे कि उन प्रशिक्षित ग्राम सेवकों को जिन्हें अभी तक नियुक्ति नहीं मिली है कब और कौन सा स्थान मिलने की सम्भावना है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**---दिनांक ४ दिसम्बर, १६५८ के तारांकित प्रश्न संख्या १०७ के उत्तर में निवेदन किया गया था कि ३३० प्रशिक्षितों को ग्राम-सेवक अथवा उसके समकक्ष पद पर नियुक्त नहीं किया जा सका है। इस सम्बन्ध में वर्तमान स्थिति यह है कि १३० प्रशिक्षितों के ग्राम सेवक पद पर अप्रैल, १६५६ के अन्त तक नियुक्त हो जाने की संभावना है, तथा ५६ अन्य प्रशिक्षितों को, कोआपरेटिव सुपरवाइजर के पदों के लिये, नियुक्ति-पत्र दिया जा चुका है। शेष १४१ प्रशिक्षितों का प्रशिक्षण-फल पूर्णरूपेण सन्तोषजनक नहीं रहा, अतएव इनकी नियुक्ति ग्राम सेवक पद पर नहीं की जायगी। ये पंचायत मंत्री के पद पर कार्य करते रहेंगे।

**श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि** (जिला हरदोई)---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन ग्राम सेवकों की अभी नियुक्ति नहीं हुई है उनको ट्रेनिंग पास किये कितना समय हो गया ?

**श्री सुल्तान आलम खां**---जो लोग ट्रेनिंग में भेजे जाते हैं उनको करीब डेढ़ साल ट्रेनिंग में लगते हैं पिछले बैच में सबकी नियुक्ति इसलिये नहीं की जा सकी कि जो ब्लाक खुलने वाले थे उनकी संख्या में कमी हो गई और इसी वास्ते कुछ लोग रह गये और उनको हम अब दूसरे मुहकमों में जगह दिला रहे हैं, साथ ही जो ३ साल तक काम करने की उन पर पाबन्दी थी उससे भी हमने उन्हें बरी कर दिया है ताकि दूसरी जगह उन्हें नौकरी मिल जाय, तो वहां वह कर लें। इसलिये कम ब्लाक खुलने की वजह से उनको जगहें नहीं दी जा सकीं और हर इमकानी कोशिश उनको काम में लगाने की की जा रही है।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---यह जो १४४ प्रशिक्षित हैं क्या सबको पंचायत सेक्रेटरी का पद दे दिया गया है ?

**श्री सुल्तान आलम खां**---मैंने जवाब में कहा है कि वे पंचायत मंत्रियों के पद पर काम करते रहेंगे।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---मैंने पूछा है कि क्या उनको वह जगह दे दी गई है ? मेरी जानकारी है कि १४१ आदमियों को जो स्थान पंचायत सेक्रेटरियों का दिया जाने वाला है वह अभी तक सबको नहीं दिया जा सका है।

**श्री सुल्तान आलम खां**---मेरी ऐसी इत्तला नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अगर नोटिस में लायेंगे तो छानबीन की जायगी।

## ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, को गन्ने के दाम की वापसी

*५७---**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मुख्य मंत्री ४-१२-५८ के तारांकित प्रश्न संख्या ६७ के उत्तर के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामोन्नति सहकारी भंडार, कमलसागर, पो० रामपुर, जिला आजमगढ़, को गन्ने की बाकी कीमत देवरिया शुगर मिल द्वारा आखिरी बार दी गई है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---१० अक्तूबर, १६५८ को।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १० अक्तूबर, सन् ५८ को जो आखिरी पेमेंट हुआ है उसका कुछ सूद भी क्या किसानों को दिलाया गया है ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---इन्टरेस्ट की सूचना इस वक्त मेरे पास नहीं है।

---

नोट---तारांकित प्रश्न ५७ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

**श्री रामसुन्दर पांडेय**---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इसका क्या कारण है कि मिल ने इतनी देर में किसानों का भुगतान किया ?

**श्री हेमवतीनन्दन बहुगुणा**---मान्यवर, यह ३,००० की रकम सन् १६५७-५८ की बाकी थी जो सितम्बर, ५८ तक नहीं दी गई थी। इस पर उनको लिखा कि वह दे दो, तब उन्होंने चेक से पेमेंट करना चाहा लेकिन चेक लेने से उन्होंने इंकार किया, उसके बाद उनको लिखा गया कि २३-७-५८ को आकर मिल से पैसा कैश ले जाओ, लेकिन वह भी स्वीकार नहीं हो पाया, शायद किसी वजह से सेक्रेटरी साहब न आ पाये हों और १० अक्टूबर में मामला तय हो गया। सोसाइटी ने कोई और भुगतान का मामला सरकार के सामने नहीं भेजा।

## गोरखपुर रोडवेज क्षेत्र में अनुसूचित जाति के कर्मचारी

*५८---**श्री रामसूरतप्रसाद** (जिला गोरखपुर)---क्या सरकार बतायेगी कि गोरखपुर रीजन में रोडवेज में कुल कितने ए० टी० आई०, स्टेशन इंचार्ज, कंडक्टर व ड्राइवर काम कर रहे हैं तथा प्रत्येक श्रेणी के कर्मचारियों में अनुसूचित जाति के कर्मचारियों की क्या संख्या व प्रतिशत है ?

**डाक्टर सीताराम**---कुल ३४ ए० टी० आई०, ३१ स्टेशन इंचार्ज, ३१५ कंडक्टर और ३४५ ड्राइवर हैं जिनमें १ स्टेशन इंचार्ज, २५ कंडक्टर और ७ ड्राइवर अनुसूचित जाति के हैं। उनका क्रमशः प्रतिशत ३·२,७.६ और २.०२ है।

## महारानी लक्ष्मी बाई से सम्बन्धित इमारतें

*५६---**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वह किन-किन ऐतिहासिक वा सांस्कृतिक इमारतों तथा स्थानों का रख-रखाव करती है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---सरकार उन इमारतों और स्मारकों का रख-रखाव करती है जो ऐतिहासिक या कलात्मक दृष्टि से प्राचीन हैं और जिनकी सुरक्षा भारत सरकार द्वारा नहीं होती।

*६०---**श्री लक्ष्मणराव कदम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि झांसी में महारानी लक्ष्मी बाई व उनके पति राजा गंगाधर राव से संबंधित कौन-कौन सी इमारतें व स्थान हैं जो उसके अधिकार में हैं ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---सूचना संलग्न सूची में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ५६४ पर)

## तिलहर तहसील में श्रमदान द्वारा निर्मित सड़कें

*६१---**श्री बालकराम**---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में १६५७ व १६५८ में श्रमदान से कितनी लम्बी सड़कें बनाई गई हैं और उनके लिये कितना-कितना अनुदान किस-किस को दिया गया है ?

**डाक्टर सम्पूर्णानन्द**---जिला शाहजहांपुर की तहसील तिलहर में १६५७ व १६५८ में श्रमदान से क्रमशः १२ मील ५ फर्लांग व १६ मील ६ फर्लांग १२५ गज लम्बी सड़कें विभिन्न ग्रामों में बनाई गईं। इनके लिये कोई अनुदान नहीं दिया गया।

*६२-६४---**राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे**---[३ मार्च, १६५६ को प्रश्न संख्या १५-१७ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

*६५---**श्रीमती सरस्वती देवी शुक्ल** (जिला गोंडा)---[१६ मार्च, १६५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*६६-६७—श्रीमती चन्द्रावती (जिला बिजनौर)—[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## पाइलेट वर्कशाप बकेवर से प्रशिक्षित परिगणित तथा पिछड़े वर्ग के लोग

*६८—श्री भजनलाल (जिला इटावा)—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इटावा जिले के पाइलेट वर्कशाप बकेवर राजकीय वस्तु केंद्र इटावा में १९५७ व ५८ में कितने व्यक्तियों ने ट्रेनिंग पाई, उसमें कितने परिगणित तथा कितने पिछड़े वर्ग के थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(अ) ४२ व्यक्तियों ने।

(ब) क्रमशः ६ और ४।

*६९—श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)—[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

## बरेली चीनी मिल पर सेस का बकाया

*७०—श्री बाबूराम (जिला बरेली)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गन्ना मिल बरेली पर ३० नवम्बर, १९५८ तक कितना रुपया किसानों तथा सरकार का बाकी था?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—३० नवम्बर, १९५८ तक एच०आर०शुगर फैक्ट्री, बरेली, पर किसानों और केन सेस की मद के अन्तर्गत सरकार का क्रमशः २.७० लाख तथा १०.७७ लाख रुपया बकाया था।

## गाजीपुर जिले में उद्योग-धंधे

*७१—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले में सन् १९५७-५८ में उसके द्वारा कितने उद्योग-धंधे खोले गये?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—तीन।

*७२-७३—श्री सजीवनलाल—[सहकारिता मंत्री से संबंधित १६ मार्च, १९५९ के लिये प्रश्न संख्या १६-१७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*७४-७५—श्री भजनलाल—[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## सेवायोजन कार्यालय, गोरखपुर का कार्य

*७६—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि पिछले दो वर्षों में इम्पलायमेंट एक्सचेंज, गोरखपुर में कितनी दरख्वास्तें रोजगार दिलाने के लिये प्राप्त हुईं और कितनों को रोजगार दिलाया जा सका?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सेवायोजन कार्यालय गोरखपुर में १९५७ तथा १९५८ में क्रमशः १८,३१६ तथा २०,२१२ व्यक्तियों ने अपना नाम पंजीकृत कराया। इन वर्षों में ८८९ तथा २,३३३ व्यक्तियों को क्रमशः रोजगार दिलाया गया।

## श्रम अधिकारी रखने वाली फैक्टरियां

*७७—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उत्तर प्रदेश में कुल कितनी ऐसी फैक्टरियां हैं जहां लेबर वेलफेयर आफिसर्स नियुक्त हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—११६।

*७८--श्री नेकराम शर्मा--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इनमें से कौन-कौन फैक्टरियां 'ए' श्रेणी की हैं, कौन 'बी' श्रेणी की तथा कौन-कौन 'सी' श्रेणी की हैं?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उपरोक्त फैक्ट्रियों में से १९(ए) श्रेणी, ६३ (बी) श्रेणी, था ३४(सी) श्रेणी की हैं, जिनके नाम संलग्न तालिका † में हैं।

## उन्नाव के शराबखाने से आय

*७९--श्री खजानसिंह चौधरी (जिला उन्नाव)--क्या परिवहन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या उन्नाव में शराब बनाने का कारखाना है और उसमें शराब बनती है? यदि हां, तो कितनी शराब १ अप्रैल, सन् १९५७ ई० से ३१ मार्च, सन् १९५८ तक बनी और सरकार को इससे कितनी आमद हुई?

डाक्टर सीताराम--जी हां। १ अप्रैल, १९५७ से ३१ मार्च, १९५८ तक की अवधि में शराबखाने (डिस्टीलरी) में ३,८१,२९९ एल०पी० गैलन पेय शराब बनाई गई तथा उक्त अवधि मे सरकार को कुल ३१,७७,६७८ रुपये की ड्यूटी के रूप में आय हुई।

*८०-८२--श्री धर्मदत्त वैद्य (जिला बरेली)--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## नैनीताल जिले में तहसीलदारों का कथित चुनाव

*८३--श्री रामशरण यादव (जिला लखनऊ)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मई सन् १९५६ में नैनीताल में डिप्टी कलेक्टर के पद के लिये रेगुलर तहसीलदारों का डिपार्टमेंटल चुनाव हुआ था? यदि हां, तो कितने उम्मीदवार लिये गये थे? उनमें कितने हरिजन तथा कितने बैकवर्ड थे?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--मई १९५६ में ऐसा कोई चुनाव नहीं हुआ। शेष प्रश्न उठते नहीं।

*८४--श्री रामशरण यादव--उक्त उम्मीदवारों में से कितने ऐसे हैं जिनको डिप्टी कलेक्टर के पद पर नियुक्त नहीं किया गया है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--प्रश्न नहीं उठता।

*८५-८७--श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किये गये।]

## गुन्नौर तहसील में सिंचाई के कुओं के लिये तकावी

*८८--श्री यमुनासिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गुन्नौर, जिला बदायूं, में सन् १९५७-५८ में सिंचाई के कुओं की तकावी के लिये कितने प्रार्थना-पत्र आये और कितनों को तकावी दी गई?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--तहसील गुन्नौर, जिला बदायूं, में सन् १८५७-५८ में सिंचाई के कुओं की तकावी के निमित्त कुल १० प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये और उन दसों प्रार्थियों को तकावी दी गई।

*८९--श्री टीकाराम (जिला बदायूं)--[हटा दिया गया।]

---

† तालिका छापी नहीं गई।

## सचिवालय की रद्दी

*९०--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सरकारी सचिवालय, लखनऊ, से प्रतिमास साधारणतया कितनी कागज की रद्दी निकलती है ? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि इस रद्दी को किस काम में लाया जाता है, अर्थात् यह बेची जाती है या किसी और काम में लाई जाती है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--उत्तर प्रदेश सचिवालय में प्रतिमास साधारणतया लगभग ५० मन रद्दी कागज निकलता है। अभी तक शासन की गोपनीयता को रखने के लिये पुराने अखबार तथा गजट इत्यादि के अतिरिक्त अन्य सभी प्रयोग किये हुये कागज जला दिये जाते थे। अब ऐसे कागजों को भी, जो गोपनीय नहीं हैं, बेचने का निश्चय किया गया है।

## ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन की कानपुर काटन मिल्स की तालाबन्दी

*९१--श्री भगवती सिंह विशारद--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि क्या ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन कानपुर काटन मिल्स, कानपुर बन्द हो गई है या बन्द होने वाली है ? यदि हां, तो कब से और क्यों ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--ब्रिटिश इंडिया कार्पोरेशन लिमिटेड की कानपुर काटन मिल्स ब्रांच १६ फरवरी, १९५९ से आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो गई है।

*९२--श्री भगवतीसिंह विशारद--क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि उक्त मिल ने अपने से संबंधित श्रमिकों के समस्त देयों ( dues ) की अदायगी कर दी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द--जी नहीं।

*९३--श्री गैंदासिंह--[१९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगित किया गया।]

## मद्य निषेध आर्गेनाइजरों की सेवा समाप्ति के लिये समिति की नियुक्ति

*९४--श्री गज्जूराम (जिला झांसी) तथा श्री माता प्रसाद (जिला जौनपुर)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मद्य-निषेध के कुछ आर्गनाइजरों की सेवायें समाप्त करने के लिये समिति बैठाई गई है ? यदि हां, तो उसके सदस्य कौन-कौन हैं तथा इसकी नियुक्ति कब की गई ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, एक विभागीय समिति बिठाई गई थी जिसमें (१) आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, (२) विशेष..कार्याधिकारी (मद्य-निषेध), (३) मद्य-निषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, लखनऊ थे। इसकी नियुक्ति ९ फरवरी, १९५९ को की गई।

*९५--श्री मन्नालाल (जिला खीरी)--[ १९ मार्च, १९५९ के लिये स्थगि किया गया।]

## जौनपुर मालखाना सम्बन्धित गांजा व शराब का कथित मामला

*९६--कुंवर श्रीपालसिंह--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या जून, १९५८ से अब तक जौनपुर जिले के मालखाने से गांजा तथा शराब निकाल कर बेंचते हुये कोई सरकारी अधिकारी पकड़े गये हैं ? यदि हां, तो वे किस-किस पद के व्यक्ति थे ?

डाक्टर सीताराम--जौनपुर जिले में कोई ऐसी घटना नहीं हुई और न कोई सरकारी अधिकारी मालखाने से गांजा तथा शराब निकाल कर बेंचता हुआ पकड़ा गया।

*९७—कुंवर श्रीपालसिंह—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त मामले को किस अधिकारी ने पकड़ा है तथा पकड़े गये लोगों को क्या सजायें मिलीं ?

डाक्टर सीताराम—उपरोक्त उत्तर से यह प्रश्न नहीं उठता है ।

## विष्णुप्रताप शुगर मिल, खड्डा, पर बकाया मजदूरी

*९८—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विष्णुप्रताप शुगर मिल, खड्डा, जिला देवरिया, के मजदूरों की मजदूरी अब तक कितनी बाकी है ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—इस चीनी मिल में अथोराइज्ड कंट्रोलर की नियुक्ति के बाद अर्थात् सितम्बर, १९५७ से अब तक मजदूरों का कोई वेतन भुगतान हेतु शेष नहीं है, किन्तु सितम्बर, १९५७ से पूर्व के वेतन का २८,३६८ रु० भुगतान हेतु शेष है ।

*९९—श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि उक्त मिल के मजदूरों की मजदूरी जो बकाया है, उसको दिलाने की क्या व्यवस्था की जा रही है?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—प्राप्त सूचनानुसार, मिल के अथोराइज्ड कंट्रोलर चीनी की बिक्री से प्राप्त धन में से वर्तमान खर्च काटने के उपरान्त बची रकम से पूर्व काल के बकाया वेतन का भुगतान कर रहे हैं। सेवायोजकों द्वारा बकाया वेतन भुगतान कराने के हेतु श्रम अधिकारी भी प्रयत्नशील हैं।

## नगर बस सर्विस वाल शहर

*१००—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के किन-किन मुख्य शहरों में परिवहन विभाग की नगर बस-सर्विस चल रही है ?

डाक्टर सीताराम—लखनऊ, आगरा, बरेली, इलाहाबाद तथा वाराणसी में।

*१०१—श्री गनेशीलाल चौधरी—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि प्रदेश के और किन नगरों में उपर्युक्त सर्विस की योजना चालू करने का विचार है ?

डाक्टर सीताराम—मथुरा में।

## रोडवेज बसों का क्रय तथा कंडेम्नेशन

*१०२—श्री गज्जूराम—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि झांसी जिले में रोडवेज बसें चलाने की योजना बनायी है ? यदि हां, तो कब और कौन-कौन सी रोडों पर ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

*१०३—श्री गज्जूराम—क्या परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९५७–५८ में कितनी रोडवेज बसें कंडेम की गई हैं और कितनी नई मंगाई गई हैं ?

डाक्टर सीताराम—सन् १९५७–५८ में रोडवेज की १७३ बसें कंडेम की गई हैं और ३५६ नई बसें मंगाई गई हैं।

## बुलन्दशहर जिले में हरिजनों को उद्योग के लिये सहायता

*१०४—श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बुलन्दशहर में उद्योग विभाग की ओर से १९५६–५७ व १९५७–५८ में हरिजनों को उद्योगों के लिये कितनी-कितनी सहायता दी गई ? क्या सरकार उक्त सहायता पाने वाले व्यक्तियों की सूची भी सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही है।

## गोरखपुर जिले के बाढ़ क्षेत्र में अम्बर चरखा केन्द्र तोड़ना

*१०५—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाढ़ एरिया में चर्खे से कते हुये सूत पर फी गुन्डी जो दो आना कतिनों को मिलता था क्या वह बन्द कर दिया गया ? अगर हां, तो उसे मार्च, १९५९ तक दो आना फिर देने का विचार सरकार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*१०६—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिले में बाढ़ एरिया क्षेत्र में कुछ अम्बर चर्खे के केंद्र तोड़ दिये गये हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी हां।

*१०७—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार पुनः वहां अम्बर चर्खे के केंद्रों को खोलने का विचार करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—जी नहीं।

## प्राइवेट कम्पनियों के डाइरेक्टरों में गजटेड अफसर

*१०८—राजा यादवेन्द्रदत्त दुबे—क्या सरकार बतायेगी कि राज्य में कितने गजेटेड अधिकारी जो सर्विस में हैं प्राइवेट कम्पनियों में डाइरेक्टर हैं ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—सरकार के केवल दो गजेटेड अधिकारी एक प्राइवेट कम्पनी के डाइरेक्टर हैं।

## गोरखपुर जिले से वृद्धावस्था पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र

*१०९—श्री गौरीराम गुप्त—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि किन-किन ग्राम सभाओं में गोरखपुर जिले के प्रत्येक तहतील में बुढ़ापे के पेंशन के फार्म भेजे गये थे ? अगर नहीं, तो भेजने की तत्काल कृपा करेगी ?

डाक्टर सम्पूर्णानन्द—गोरखपुर जिले की प्रत्येक तहसील में एक-एक हजार बुढ़ापे के पेंशन के फार्म नवम्बर सन् १९५७ में भेजे गये थे। विवरण का ब्योरा निम्नलिखित है:

१—तहसील सदर गोरखपुर में यह फार्म प्रत्येक ग्राम सभाओं में कानूनगो द्वारा भेजे गये हैं।

२—तहसील महराजगंज में फार्म प्रत्येक कानूनगो तथा तीन विकास खंड निचलौल, परतावल, महराजगंज द्वारा बांटे गये।

३—तहसील फरेंदा में दस ग्राम सभाओं (समरधीरा-बनकटा-अड्डा बाजार करीम-नगर धानी, पी०पी०गंज, सेखुआनी-बृजमनगंज-लक्ष्मीपुर-आनन्द नगर) में फार्म भेजे गये हैं। इसके अतिरिक्त यह फार्म टाउन एरिया पंचायत इंस्पेक्टर तथा कानूनगो हल्का द्वारा भी बांटे गये हैं।

४—तहसील बांसगांव में लेखपाल तथा कानूनगो हल्का द्वारा बांटे गये हैं।

बुढ़ापे की पेंशन के फार्म काफी संख्या में प्रत्येक तहसील में इस आदेश के साथ फिर भेजे गये हैं कि संबंधित ग्राम सभाओं में बांटे जायें।

## प्राक्कलन समिति का (सूचना विभाग से सम्बन्धित) तृतीय प्रतिवेदन

**श्री नवलकिशोर** (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्राक्कलन समिति द्वारा दिये गये अधिकारों के अनुसार इस समिति का तृतीय प्रतिवेदन जो सूचना विभाग से सबंधित है, प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, क्योंकि प्रतिवेदन की कापियां सब को बंट गयी है, इसके विषय में कुछ न कहते हुये मैं यह अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि आपने जो मुझको और समिति को समय-समय पर सहायता और सहयोग दिया है और हमारा पथ-प्रदर्शन किया है उसके लिये मैं अपना आभार प्रकट करूं। साथ ही साथ सूचना विभाग के उन सभी पदाधिकारियों और विशेषकर संचालक के प्रति उनके सहयोग के लिये भी अपना आभार आपके द्वारा प्रकट करना चाहता हूं और इसके साथ ही साथ जो हमारी समिति के पदाधिकारी हैं विशेषकर हमारे कमेटी आफिसर उपाध्याय जी, उन्होंने जो इस प्रतिवेदन के संबंध में अपना सहयोग दिया है और परिश्रम किया है उसके लिये भी मैं अपना आभार प्रकट करता हूं।

## रजा चीनी मिल तथा कुन्दन चीनी मिल के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचना

**श्री अध्यक्ष**—अब ये कार्य-स्थगन प्रस्ताव मेरे पास दो आये हुए हैं। एक तो रामपुर स्थित रजा मिल्स के संबंध में है कि २२५ बाहरी मजदूरों को मिल में रख दिया गया है, हड़ताल तोड़ने के संबंध में, मेरे पास इस तरह का तार आया था, लेकिन यह विषय ऐसा है कि इस पर एक वक्तव्य दिया जा चुका है। इसके अलावा १२ तारीख को उद्योग वाला अनुदान है और १३ को है श्रम, उसमें यह विषय उठ सकता है। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

दूसरा कुंदन मिल्स, अमरोहा, के संबंध में उग्रसेन जी का है, उसमें कुछ लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं, वह भी अनुदानों पर विवाद के समय उठाया जा सकता है। तो ये दोनों उसी वक्त उठाये जा सकते हैं।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—श्रीमन्, वहां २ मजदूर भूख हड़ताल कर रहे हैं और १४४ जिलाधीश ने लगा दी और स्थिति बड़ी भयंकर है। तो १२ तारीख तक स्थिति न बिगड़े उसमें मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री इंटरवीन कर लें।

**श्री अध्यक्ष**—वह आपने सूचना दे दी, मंत्री जी सुन रहे हैं।

**श्री उग्रसेन**—इसे नोट कर लें।

**श्री अध्यक्ष**—उन्होंने नोट कर लिया, अब आप बैठें।

## नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना पर अछनेरा, जिला आगरा के टाउन एरिया के चेयरमैन श्री शिव प्रसाद अग्रवाल की हत्या के सम्बन्ध में वक्तव्य

**श्री अध्यक्ष**—नियम ५२ के अन्तर्गत उठाये गये विषय पर कल मंत्री जी ने वादा किया था उसमें जानकारी हासिल करने के लिये। तो गृह मंत्री जी अपना वक्तव्य दें।

**स्वायत्त शासन उपमंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)**—श्रीमन्, टेलीफोन द्वारा यह सूचना मिली है कि थाना अछनेरा में पहली मार्च, १९५९ को श्री धनीराम ने सायंकाल ७ बजकर १० मिनट पर यह रिपोर्ट दर्ज करायी कि श्री शिवप्रसाद अग्रवाल अजमेर सर्वोदय

सम्मेलन में शामिल होने गये थे और वह रेल द्वारा लौटे और साढ़े ६ बजे के करीब स्टेशन से जबकि रूखा हलवाई की दुकान के निकट आये तो एक शख़्स बृजेंद्र सिंह उनकी तरफ आ कर लपका। उस समय श्री अग्रवाल अपने साथियों से कुछ आगे थे। बृजेंद्र सिंह उन पर दौड़े और तलवार से हमला किया और यह भी आवाज सुनने में आयी कि आज तेरा खात्मा है। सख़्त चोटें खा कर श्री अग्रवाल गिर पड़े। श्री छत्तरमल और श्री धनीराम ने शोर मचाया और कहा कि हमला क्यों कर रहे हो। धनीराम ने बचाने की कोशिश भी की, लेकिन बृजेंद्र सिंह ने उस पर भी हमला किया जिससे कि उसके हाथ में चोट आयी और लोग भी वहां पर काफी आ गये। श्री अग्रवाल के साथियों ने यह जान कर कि चोटें बहुत सख़्त हैं उनको ट्रक द्वारा आगरा पहुंचाया। रास्ते में उनकी जान निकल गयी। अन्दाज यह किया जाता है कि जो घटना है वह करीब ६.५० मिनट पर हुई थी। तुरन्त एस०ओ० वहां पर गये। डी०वाई०एस०पी० भी करीब ९ बजे पहुंच गये और बृजेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। खून से सने हुये जो कपड़े थे जिनको वह बदलने की कोशिश कर रहा था उनको भी पा लिया और तलवार भी जो कि कुंयें में डाल दी गई थी पा ली। बृजेंद्र सिंह एक डिस्मिस्ड सिपाही था, सन् १९४३ में वह निकाल दिया गया था। वह हिस्ट्री-शीटर भी है। कुछ दिनों तक श्री अग्रवाल से उसके संबंध अच्छे रहे, लेकिन बाद में उनसे संबंध बिगड़ गये। इस वक्त कुछ ऐसा मालूम पड़ता था कि वे दोनों आपस में दुश्मन नहीं थे, लेकिन वह श्री अग्रवाल से नौकरी की इच्छा करता था। वह शायद उनसे न पा सका।

**श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल** (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय को यह मालूम है कि आगरा के लगभग सभी राजनीतिक दलों के लोगों का यह कहना है कि इस हत्या के पीछे एक षड़यंत्र है और इसलिये इसकी जांच स्पेशल सी०आई०डी० से कराई जानी चाहिये और इस सदन में जो माननीय विश्वेश्वरानन्द जी किरावली तहसील के, जिसमें अछनेरा एक कस्बा है, प्रतिनिधि हैं वे भी इस मांग में शामिल हैं? तो क्या सरकार इस मांग पर सहानुभूति के साथ विचार करेगी?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, इस समय तक जो सूचना है उससे तो कोई षड़यंत्र मालूम नहीं होता। साथ में ही जैसी कि रिपोर्ट थाने में दर्ज हुई है उसके आधार पर जिस शख़्स ने हमला किया है वह भी गिरफ्तार हो गया है। अगर कोई विशेष परिस्थिति बाद में मालूम होगी, क्योंकि अभी तो जो सूचना है वह टेलीफोन से प्राप्त हुई है, तब विचार जा सकता है।

**स्वामी विश्वेश्वरानन्द** (जिला आगरा)—क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि बाबू शिव प्रसाद अग्रवाल के ऊपर इसी बृजेंद्र सिंह ने एक बार और हमला किया था रिवाल्वर से?

**श्री रामस्वरूप यादव**—मेरे पास यह सूचना तो है कि धारा २९ जो आर्म्स ऐक्ट की है उसमें इस शख़्स को सजा हुई थी और सन् १९५६ में यह जेल से छूटा था, लेकिन यह सूचना नहीं है कि उसी शख़्स ने पहले हमला किया था।

**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या मंत्री महोदय को इस बात की जानकारी है कि जिस वक्त बृजेंद्र सिंह ने पहले बाबू शिव प्रसाद अग्रवाल पर हमला किया था उस समय समाचार पत्रों में भी अन्य व्यक्तियों के नाम आये थे और इस बात की मांग की गयी थी कि उन व्यक्तियों के खिलाफ सरकार को पूरी पूरी जांच करनी चाहिये कि इन व्यक्तियों का हाथ यह हमला कराने में कितना है?

**श्री अध्यक्ष**—वह तो यह कहते हैं कि उनको जानकारी नहीं है कि उसने हमला किया तो इससे यह प्रश्न उठता नहीं है क्योंकि वह कैसे बता देंगे।

**श्री झारखंडे राय** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि श्री शिवप्रसाद जी की हत्या के पहले उन्होंने पुलिस में ऐसी रिपोर्ट की थी कि मेरी जान माल का खतरा है, यदि हां तो उनकी जान बचाने के लिये क्या व्यवस्था की गई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, इस समय सरकार के पास यह सूचना नहीं है कि उन्होंने ऐसी रिपोर्ट या दरख्वास्त दी थी या नहीं।

**श्री चन्द्रजीत यादव** (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि स्थानीय पुलिस को उन्होंने बता दिया था कि उनके ऊपर घातक प्रहार होने की संभावना है और स्थानीय पुलिस की लापरवाही के कारण ऐसी घटना हुई ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, जो रिपोर्ट आई है उससे मालूम होता है कि जिले में ऐसी कोई बात नहीं कही जा रही है कि स्थानीय पुलिस की अकर्मण्यता के कारण ऐसी घटना हुई है इसलिये जांच का कोई प्रश्न नहीं है।

**श्री गोविन्दसिंह विष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—क्या पुलिस का लिखा हुआ चित्रगुप्त का लेख समझा जाता है कि जिसे बदला न जाय ?

**श्री अध्यक्ष**—यह तो आप बहस कर रहे हैं।

**स्वामी विश्वेश्वरानन्द**—क्या मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे कि वहां जो सब इंस्पेक्टर पुलिस है उससे बृजेंद्र सिंह ने यह कहा था कि अगर आप २-४ दिन के लिये चले जायं तो मेरा काम पूरा हो जायगा ?

**श्री रामस्वरूप यादव**—श्रीमन्, इसकी सूचना सरकार के पास नहीं है और जैसा कि प्रश्न पूछा गया है उससे जाहिर होता है कि उस एस०ओ० से मुलजिम घबराता था।

## नियम ५२ के अन्तर्गत अन्य सूचनाएं

**श्री अध्यक्ष**—२-३ सूचनाएं मेरे पास नियम ५२ के अनुसार हैं, लेकिन मैं उनकी इजाजत नहीं दे रहा हूं कि उन विषयों में वक्तव्य देने के लिये कहा जाय।

**श्री मोतीलाल अवस्थी** (जिला कानपुर)—श्रीमन्, मैं एक व्यवस्था चाहता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—आप कृपा कर बैठिये। मेरे बोलते हुये कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठ सकता है।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, तो व्यवस्था का प्रश्न कब उठ सकता है ?

**श्री अध्यक्ष**—मेरे बोलने के बाद। मैंने फैसला दिया है कि इस विषय को, जो बहस होगी अनुदानों के संबंध में, उसमें उठाया जा सकता है और वह अनुदान शीघ्र आने वाले हैं इसलिये मैं इजाजत नहीं दे सकता हूं।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि आप कामरोको प्रस्ताव ले लेते हैं तो कम से कम उनका उल्लेख तो होना चाहिये। मेरा २ तारीख का कामरोको प्रस्ताव ले लिया गया, लेकिन उसका कोई उल्लेख नहीं हुआ।

**श्री अध्यक्ष**—वह मैंने स्वीकार नहीं किया था।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—स्वीकार नहीं किया, लेकिन विदिन टाइम आ गया था और ले लिया गया था तो कम से कम उसका उल्लेख तो होना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष**—केवल समय पर मेरे पास प्रस्ताव आने से ही उसका कोई जिक्र नहीं आयेगा। कार्यवाही में यह आयेगा कि आपका कामरीको प्रस्ताव आया वह स्वीकार नहीं किया गया।

**श्री मोतीलाल अवस्थी**—श्रीमन्, यही मैं चाहता हूं कि उसका कम से कम जिक्र तो हो वरना सदन को कैसे मालूम होगा कि कोई प्रस्ताव आया या नहीं।

**श्री प्रतापसिंह** (जिला नैनीताल)—मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। हमारा विषय खाडसारी वाला है। बरेली में हड़ताल हो रही है तो उसके ऊपर बहस नहीं हो सकेगी?

**श्री अध्यक्ष**—यह विषय उद्योग और श्रम के अनुदानों की बहस में आयेगा।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—श्रीमन् मैंने भी महेश्वरी जूट मिल के संबंध में सूचना दी थी उसमें भी तीन हजार मजदूरों का सवाल है।

## प्राक्कलन समिति के प्रतिवेदन पर सूचना मंत्री से वक्तव्य की मांग

**श्री नारायणदत्त तिवारी** (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, मैं आपका ध्यान नियम २१७(३) की तरफ दिलाना चाहता हूं जिसके अनुसार आवश्यक है कि जो रिपोर्ट प्रस्तुत हुई है उससे संबंधित सूचना मंत्री जी उसी दिन या किसी दूसरे दिन सरकारी दृष्टिकोण यानी प्रस्तावित कार्यों की व्याख्या करें। सूचना विभाग के संबंध में आज रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत हुई है तो मैं जानना चाहूंगा कि सूचना मंत्री जी या सरकार सूचना विभाग के संबंध में आज ही वक्तव्य देंगे या दूसरे दिन देना चाहेंगे?

**श्री अध्यक्ष**—नियम २१७ (३) इस प्रकार है—

"संबंधित मंत्री या कोई मंत्री उसी दिन या किसी भावी दिनांक को, जब तक के लिये वह विषय स्थगित किया गया है, सरकारी दृष्टिकोण और शासन द्वारा किये जाने वाले प्रस्तावित कार्य की व्याख्या करते हुये संक्षिप्त उत्तर दे सकेंगे।"

यह मंत्री जी को इसकी सूचना देनी है। सूचना मंत्री मौजूद हैं। लेकिन २१७ (२) में यह है —

"प्रतिवेदन उपस्थित करने में सभापति या उसकी अनुपस्थिति में प्रतिवेदन उपस्थित करने वाला सदस्य यदि कोई अभियुक्ति करे तो अपने आप को तथ्य के संक्षिप्त कथन तक सीमित रखेगा या समिति द्वारा की गई सिफारिशों की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करेगा किन्तु उस कथन पर वाद-विवाद नहीं होगा।"

उन्होंने अपना प्रतिवेदन उपस्थित करते हुये कोई ऐसी चीज नहीं कही कि अमुक बात होनी चाहिए थी जिसके बारे में समिति को संतोष नहीं है। अगर ऐसा कोई वक्तव्य सभापति प्राक्कलन समिति देते तो मंत्री जी या तो उसी वक्त उत्तर देते या फिर दूसरे दिन सरकार की नीति उस पर क्या है बताते। लेकिन चूंकि उन्होंने प्रतिवेदन उपस्थित करते हुये इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं की इसलिए यह प्रश्न उठता नहीं है।

**श्री नारायणदत्त तिवारी**—समिति की जो राय है वही चेयरमैन की राय है। उन्होंने अपना प्रतिवेदन दे दिया है तो हमें जानने का अधिकार है।

**श्री अध्यक्ष**—उसके लिये अगर आप समिति के प्रतिवेदन का उपयोग बजट की बहस में करना चाहें तो कर लीजिये।

## १९५९-६० के आय व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ३३--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

**श्री अध्यक्ष**--अब वित्तीय वर्ष १९५९-६० के आय-व्ययक की मांगों पर मतदान होगा।

**सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारी लाल)**--मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--निर्माण-कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ६,०८,८७,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह भी प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४--यातायात के साधनों का सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित)--लेखा शीर्षक ५०--नागरिक निर्माण-कार्य--केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १८,३४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिए स्वीकार की जाय।

अध्यक्ष महोदय, मुझे इन मांगों के सिलसिले में सदन का ज्यादा समय नहीं लेना है। जहां तक इस विभाग का सम्बन्ध है जैसा कि पहले भी कई दफा मैं बतला चुका हूं कि उसके कुल कामों को मैं इस वक्त सदन को दर्शाऊं यह तो सम्भव नहीं है। वह तो सूबे भर में जितनी सड़कें हैं, जितने सरकारी भवन हैं, जिनका कि निर्माण होता चला जा रहा है और हुआ है वह सब इस बात के सूचक हैं। मैं केवल दो एक बातें थोड़े में बतलाऊंगा। पहली पंचवर्षीय योजना के अन्त में हमारे सूबे के अन्दर ९,९०४ मील पक्की सड़कें थीं और २,१९० मील कच्ची सड़कें उस वक्त तक बनी हुई थीं। दूसरी पंचवर्षीय योजना के मातहत हमारे यहां का जो लक्ष्य था वह १,७७० मील पक्की सड़कों का और ३२६ मील ब्राइडिल पाथ या पगडंडी पहाड़ी सड़क जिसको कहते हैं उसका था। इस वर्ष के अन्त तक १,४३२ मील पक्की सड़क और २२१ मील कच्ची सड़क के बनने की आशा है। इसमें इस साल की ४०० मील पक्की और १०० मील कच्ची सड़क भी शामिल है।

इन बातों के अलावा मैं एक और विशेष बात जिसका कि मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूं, उसकी तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं। आजकल यातायात में पुलों की एक बड़ी महत्ता है, बहुत ऊंचा स्थान है। पहली योजना के अन्दर हमारे पूरे सूबे भर में २६ पुल बनाये गये थे। दूसरी योजना में हमारा लक्ष्य २२२ पुलों का है जिनमें से करीब ५५ पुल बना लिये गए हैं और ४० पुल वह हैं जिन पर काम चालू है और बहुत ही जल्द वे जनता के लिये खोल दिये जायेंगे। इनमें से विशेष पुल जो दो चार हैं जो कि इस वर्ष खोले गये हैं उनके नाम मैं बतला देना चाहता हूं। देहरादून में सोंग का पुल है, बाराबंकी में गोमती का पुल है, गोरखपुर में रोहिणी नदी का पुल है और वाराणसी में कर्मनाशा नदी का पुल है। ये पुल इस वर्ष खोले गए हैं और जल्द ही बहराइच में सरयू नदी पर, मुरादाबाद में सोत नदी पर, गाजीपुर में विसू नदी पर और एटा में काली नदी पर भी पुल बन जाने की आशा है। बरेली में रामगंगा का एक पुल भी बन रहा है। हम उम्मीद करते हैं कि सन् ६० के मार्च या अप्रैल तक वह पुल पूरा हो जायगा।

जहां तक कि यातायात का सम्बन्ध है इसमें हमारे यहां सन् १९४२ में तमाम चीफ इंजीनियर्स का एक सम्मेलन हुआ था उसमें उन्होंने कुछ बातें तय की थीं और उसके हिसाब से तमाम सड़कों का एक क्लासिफिकेशन हो गया है। तब से हिन्दुस्तान भर में नेशनल हाईवेज कुछ अलग बांट दी गई हैं। नेशनल हाई वेज जिनका एक सूबे से दूसरे सूबे तक सम्बन्ध है ये केन्द्रीय सरकार द्वारा पोषित की जाती हैं। लेकिन उसके ऊपर जितना काम होता है, उसकी

देखरेख का या उसके निर्माण का कार्य वह सब का सब प्रदेश की सरकार करती है। इस प्रकार की सड़कें हमारे सूबे में १,४०० मील हैं और इन पर १८ बड़े-बड़े पुल हैं जो कि बनाये जाने हैं और ये जितनी सड़कें हैं वह अभी तक १८ फुट चौड़ी हैं, इनके लिये यह योजना है कि इनको २२ फुट चौड़ा कर दिया जाय।

एक और बात की तरफ मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें कि सदन का और इस सरकार का कुछ रुपया खर्च हुआ है। हमारे सूबे में पहले तो पूर्वी जिलों में बाढ़ आया करती थी, लेकिन दो वर्षों से पश्चिमी जिलों में भी अतिवृष्टि होने लगी है जिससे जहां बहुत से खेतों में पानी भर जाता है वहां सड़कों को भी उससे बहुत ज्यादा नुक्सान पहुंचता है। वहां पर पिछले वर्ष भी करीब २८ लाख रुपया खर्च किया गया था उनकी मरम्मत के लिए, उनको सुधारने के खयाल से और पानी वगैरह निकालने के खयाल से इस वर्ष भी ३४ लाख रुपया खर्च करना पड़ रहा है।

इन बातों के अलावा भवन निर्माण का भी कार्य इस विभाग के जरिये से सम्पादित किया जा रहा है जिसमें कि ५ करोड़ रुपये का काम होने जा रहा है। उसमें स्कूल, कालेज, होस्टल्स और आबजर्वेटरी जो कि नैनीताल में है और शिक्षा विभाग के और काम हैं यह सब हो रहे हैं। इसी तरीके से मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट जो है उसके भी बहुत से अस्पताल वगैरह, मेडिकल कालेज इत्यादि बनाये जा रहे हैं। कौंसिल हाउस में दोनों तरफ के हिस्से बढ़ाये जा रहे हैं और इसके साथ-साथ कुछ और कन्टीन वगैरा का काम है। लखनऊ में नेशनल स्पोर्ट्स स्टेडियम के लिये भी करीब २ लाख रुपया खर्च होगा। इसके अलावा हमारे प्रान्त में बहुत से स्थानों पर जैसे लखनऊ, कानपुर, झांसी, मेरठ, इलाहाबाद, वाराणसी और विठूर में आजादी के युग की स्मृति में कुछ स्मारक बनाये गये हैं उनमें भी काफी पैसा खर्च हुआ है।

१९५९–६० के कार्यक्रम के सिलसिले में मैं इतना बतलाना चाहता हूं कि जिन नई सड़कों को हम लेना चाहते हैं उनमें ५०० मील तो पक्की सड़कें हैं। ७५ मील कच्ची सड़के है। ५० मील सड़क का फिर से निर्माण होगा। ९० मील सड़क पगडंडी के रूप में बनाई जायगी। ७५ मील की कंकड़ की सड़क है जिस पर डामर डालना है। १४ बड़े-बड़े पुल भी तैयार होने की आशा है। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो माननीय सदस्य कहेंगे उससे फायदा उठाने की कोशिश करूंगा।

**कुंवर श्रीपालसिंह** (जिला जौनपुर)—अध्यक्ष महोदय, मैं आप की आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव उपस्थित करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर व्यय, जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं—लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। रुपया लैप्स होता है तथा प्रदेश की स्वीकृत यातायातीय आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं।

अनुदान संख्या ३४—यातायात के साधनों का सुधार, लेखा शीर्षक ५०—नागरिक निर्माण कार्य के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का व्योरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है। योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के साधनों के सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्त पोषित) से सम्बन्धित बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिससे योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

अध्यक्ष महोदय, मनुष्य की जो भी मौलिक आवश्यकतायें हैं, भोजन, वस्त्र और आवास, इनके बाद जिस किसी चीज की परम आवश्यकता होती है वह है सड़क। जिस प्रकार से मोटर गाड़ी सड़क पर चलती है, जिस प्रकार से साइकिल सड़क पर चलती है, जिस प्रकार से इक्का सड़क पर चलता है, जिस प्रकार से बैलगाड़ी सड़क पर चलती है, ठीक उसी प्रकार से सभ्यता भी सड़क से ही चलती है। बिना सड़क के विस्तार के एक जगह की सभ्यता दूसरी जगह नहीं पहुंच सकती है और एक जगह का उत्पादन दूसरी जगह नहीं पहुंच सकता है, एक जगह की लक्ष्मी दूसरी जगह नहीं जा सकती हैं। तो जिस प्रकार मानव के लिये वस्त्र और आवास नितांत आवश्यक हैं ठीक उसी प्रकार सड़कें भी उसके जीवन में अत्यन्त आवश्यक वस्तुओं में से एक है। इतनी आवश्यक वस्तु होते हुये भी यह देखा जाता है कि सड़कों के ऊपर हमारी सरकार का ध्यान ठीक उसी प्रकार का है जैसे विमाता का पुत्र पर होता है। किसी भी अनुदान में रुपयों की कमी पड़ती है, किसी भी प्लान में रुपयों की कमी पड़ती है तो उसके लिये कटौती सड़कों से ही की जाती है। इतनी आवश्यक वस्तु के लिये ऐसा समझा जाता है कि उस पर बेकार धन व्यय हो रहा है और उसमें से कटौती की जाती है। मैं अपनी इस बात के समर्थन के लिये यह थोड़ी सी बातें निवेदन करना चाहता हूं।

"सन् १९५६-५७ के कार्यों का संक्षिप्त विवरण" के नाम से एक पुस्तक जो राज्य की ओर से प्रकाशित हुई थी उसमें बतलाया गया है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना पहले ३२ करोड़ रुपये की लागत की बनायी गयी, लेकिन अभाग्यवश इस धनराशि को कम कर के १६ करोड़ रुपया कर दिया गया जिसके फलस्वरूप बहुत सी आवश्यक सड़कें योजना से निकालनी पड़ीं। श्रीमन्, यह पुस्तिका सरकार की तरफ से ही बांटी गयी थी, उसमें यह भाव व्यक्त किये गये हैं। ठीक इसी प्रकार १९५७-५८ में जो पुस्तिका बांटी गयी उसमें भी यही भाव व्यक्त किये गये हैं। उसमें कहा गया है कि इस प्रकार हमारे प्रदेश में ४०,००० मील पक्की तथा २६,००० मील कच्ची सड़कों की आवश्यकता पड़ेगी। प्रथम पंचवर्षीय योजना के अन्दर अब तक प्रदेश में ११,५३४ मील पक्की सड़कें थीं और आशा है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक लगभग १४,८०० मील लम्बी सड़कें होंगी। इस प्रकार २५,००० मील लम्बी सड़कों की कमी रह जायगी। यह भी श्रीमन्, सरकार की ही पुस्तिका में वर्णित है। इस वर्ष भी जो पुस्तिका दी गई है उसमें भी इन सड़कों के अनुदान में ही कमी की गयी है, ऐसा इसमें लिखा है। पहले सड़कों के लिये द्वितीय पंच वर्षीय योजना २१.६९ करोड़ रुपये की लागत की बनी थी जिसके अन्तर्गत अधिकतम १६.१४ करोड़ रुपया व्यय करने की व्यवस्था थी। सड़क निर्माण की जितनी आवश्यकता थी वह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं ली जा सकी, अतएव ३२१·२२ लाख रुपये के निर्माण-कार्य इस योजना से बाहर स्वीकृत हुए यानी सड़कों के अलावा और कामों में वह रुपया खर्च किया गया। वह देखने वाली चीज है। इन्हीं पुस्तकों में जितने आंकड़े दिये गये हैं, जितने पृष्ठों में सरकार की नीति का वर्णन किया गया है उसके कम से कम दुगने पन्नों में केवल तसवीरें दी गयी हैं और वह किन चीजों की हैं? कहीं कोई बड़ा हाल बना है, कहीं कुछ क्वार्टर बने हैं, कहीं कुछ मकानात बने हैं, उनकी तसवीरें छपी हैं। मैं मानता हूं कि इन मकानों की भी आवश्यकता है। रूस से आई हुई कठपुतलियों का नाच दिखलाने के लिये लखनऊ में एक बड़े हाल की आवश्यकता है। मगर हिन्दुस्तान की वह कठपुतलियां जिनके भरण-पोषण के लिये ही यह राज्य कायम हुआ है उनके लिये क्या ध्यान दिया जाता है? उनके इस्तेमाल में आने वाली जो सड़कें हैं उनकी ओर से सरकार का ध्यान बिलकुल हट जाया करता है।

श्रीमन्, अपना प्रदेश भारत के ए क्लास के राज्यों में एक है मगर सड़कों के मामले में सब से पिछड़ा हुआ है। यह मैं श्रीमन्, कहीं दूसरी जगह से नहीं कह रहा हूं यह सरकारी ही आंकड़े हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अलग-अलग राज्यों में उनके क्षेत्रफल के आधार पर कितने मील पक्की और कितने मील कच्ची सड़कें हैं। इसको देखने से यह स्पष्ट हो जायेगा कि अपना प्रदेश इस मामले में कितना पिछड़ा हुआ है। मद्रास का कुल क्षेत्रफल ६०,३६२ वर्गमील है और वहां की पक्की सड़कों की लम्बाई, १८,०९२

मील है जो प्रति वर्ग सैकड़ा मील के हिसाब से २९.९ का औसत आता है । आंध्र प्रदेश का क्षेत्रफल ६३,६११ वर्गमील है और वहां पक्की सड़कों की लम्बाई १३,१८७ मील है जो प्रति वर्ग सैकड़ा मील औसत २०.७ आता है। पश्चिमी बंगाल का क्षेत्रफल ३०,७७० वर्गमील है, पक्की सड़कें ४,७३० मील हैं और प्रति वर्ग सैकड़ा मील औसत १५.३ है। बम्बई का क्षेत्रफल १,११,२७० वर्गमील है, पक्की सड़कों की लम्बाई १४,५११ मील है और सड़कों का प्रति वर्ग सैकड़ा मील औसत १३.१ है।

**श्री अध्यक्ष**---शायद आप बम्बई प्रदेश का पुराना क्षेत्रफल पढ़ रहे हैं?

**कुवर श्रीपाल सिंह**---जी हां।

और श्रीमन्, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल १,१३,४०९ वर्गमील होते हुये भी यहां पर सिर्फ ११,५३४ मील पक्की सड़क हैं और यहां पर प्रति वर्ग सैकड़ा मील औसत १०.२ आता है। तो श्रीमन्, इसको देखने से सिद्ध हो जाता है कि इस प्रदेश में प्रति वर्ग सैकड़ा मील के आधार पर सड़कों का औसत बहुत कम है और यह बड़ा दुख का विषय है। श्रीमन्, कुछ देशों के कुछ मुख्य अभियन्ताओं की एक कान्फ्रेन्स हुई थी। उस में उन लोगों ने जो सुझाव दिये थे, अपने प्रदेश की सघन आबादी को देखते हुये, यहां की जन संख्या को देखते हुये, वह यह थे कि उत्तर प्रदेश में ५२ मील सभी प्रकार की तथा ३३ मील पक्की सड़कों की आवश्यकता प्रति वर्ग सैकड़ा मील में है। इस सुझाव के अनुसार इस प्रदेश में ३७,४२५ मील पक्की सड़कों की जरूरत है जिसमें अभी तक केवल ११,६७२ मील सड़कें बन सकती हैं। इस प्रकार से हमें अभी २५,७५३ मील पक्की सड़कों की आवश्यकता है। इतनी जरूरी चीज होते हुये भी, जिन पर दूसरे देशों के अभियन्ताओं ने अपना मत व्यक्त किया है, हमारी सरकार की ओर से केवल छटा बिचली नजर ही डाली जाती है। आज भी माननीय मंत्री जी ने अपनी वक्तृता में कुछ बतलाया कि आगे क्या होने वाला है, उसमें कौंसिल हाउस बन जायगा, स्टेडियम बन जायगा, कुछ स्मारक बन जायंगे पर सड़कों के बारे में वही छंटी बिचली नजर---थोड़ी सी सड़कें भी बन जायंगी, जब कि ८५ फीसदी आबादी गांव में रहने वाली है और प्रतिदिन सरकार की तरफ से यह नारा बुलन्द किया जाता है कि उपज बढ़नी चाहिये। हमारे प्रधान मंत्री ने ११ साल बाद इस चीज का अनुभव भी किया कि हमारे देश की सब से प्रथम समस्या, जिसको प्राथमिकता मिलनी चाहिये, वह खाद्य समस्या है। इतनी आवश्यक बात जिसको पूरा करने वाली सड़कें ही हैं इन्हीं के जरिये से गांवों को खाद पहुंच सकती है, इन्हीं के जरिये से गांवों में खेतों के औजार पहुंच सकते हैं इन्हीं के जरिये से गांवों की उपज मंडियों में आ सकती है तथा इन्हीं के जरिये से गांवों में सभ्यता की रोशनी पहुंच सकती है, लेकिन फिर भी सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान वैसा ही है, जैसा मैंने कहा कि विमाता का अपने पुत्र पर होता है।

मकान भी जो बनाये जा रहे हैं वे इसलिये बनाये जा रहे हैं कि विदेशों से जो लोग आते हैं वह यह देखें कि हमारे यहां क्या कार्य हो रहा है। सड़कें बनाने का काम जो किया जाता है वह भी राष्ट्राय सड़कों पर ही किया जाता है. जैसे दिल्ली से बनारस जाने वाली, कहीं सारनाथ का चौराहा बनाया जाता है तो कहीं चैतगंज की सड़क बनायी जाती है। इस प्रकार से केवल दिखावट का काम किया जाता है, लेकिन जहां तक गांव की सड़कों का संबंध है, अंग्रेजों के जमाने से अब तक कोई परिवर्तन दिखायी नहीं पड़ता है। कच्ची-धूलभरी सड़कों पर अगर आदमी चलता है तो ऐसा मालूम होता है कि सड़क पर से मोटर गुजर रही है। क्या उन सड़कों पर कोई कार्य हुआ? बिलकुल नहीं। मैं यह नहीं कहता कि इसमें माननीय मंत्री जी का ही दोष है। लेकिन उन्हीं को ग्रान्ट पर कटौती आती है। किसी भी अनुदान में कमी दिखलायी दी कि पी० डब्ल्यू० डी० के अनुदान में से कटौती कर दी गयी। मालूम पड़ता है रिजर्व फंड पी० डब्ल्यू० डी० में ही है।

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

श्रीमन, गांवों में जो सड़कें हैं उनके लिये एक उम्दा बहाना लोगों को मिल जाता है कि ये सड़कें तो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स को दे दी गयी हैं। हमेशा माननीय मंत्री जी की तरफ से यही जवाब गांवों का सड़कों के बारे म मिलता है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि डिस्ट्रक्ट बोर्ड्स के जिम्मे जो सड़कें हैं क्या उनकी तरफ कभी यह भी देखा जाता है कि उन पर कितनी मिट्टी पड़ी है, जिन सड़कों का स्तर भूमि से जितना ऊंचा था अब वह उतना ही नीचा हो गया है, क्या उन सड़कों ने नालों का रूप ग्रहण कर लिया है ? गांव की सड़कों के ऊपर अगर सरकार ध्यान नहीं देती है तो उसका नतीजा यह होगा कि जितने भी ये चमत्कार के कार्य हो रहे हैं वे केवल विदेशियों की आंखों में ही चकाचौंध पैदा कर समाप्त हो जायंगे, लेकिन हम जो यहां के रहने वाले हैं उनकी आंखों में तो आज से २०-२५ साल पहले जो गांव की सड़कों की हालत थी वही झलक आज भी दिखायी पड़ रही है। इसके लिये मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स की सड़कें हैं उनको पी० डब्लू० डी० अपने अन्दर ले ले और उन सड़कों पर जितना रुपया खर्च करने की इजाजत बोर्डों की है उन रुपयों को भी पी० डब्ल्यू० डी० ले ले ताकि वे सड़कें अगर डामर और सीमेंट की न बन सकें तो कम से कम कंकड़ की तो बन जायं ताकि लोगों को धूल तो न फांकनी पड़े। आखिर गांव वाले भी मनुष्य ही हैं, लेकिन सरकार उनको उसी नजर से देखती है जैसे एक बड़ा भारी किसान अपने हलवाहे को देखता है। आप उन गरीब बेचारे गांव वालों को रोज-रोज के धूल खाने से बचाइये, उनके फेफड़ों को तो बचाइये ताकि उनको टी० बी० न हो सके। इसलिये मेरा निवेदन यह है कि उन सड़कों को डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स से अवश्य ले लिया जाय।

श्रीमन्, अब मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ निवेदन कर देना चाहता हूं। जहां के लोगों ने मुझे चाहा और चुन कर भेज दिया। शाहगंज क्षेत्र की कई जरूरी सड़कों के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी को एक आवेदन पत्र दिया था और माननीय मंत्री जी ने कहा था कि वे उसके ऊपर सहानुभूतिपूर्ण विचार करेंगे। एक सड़क बदलापुर बाजार से घनश्यामपुर को जाती है। यह बाढ़-ग्रस्त क्षेत्र है जो बाढ़ के दिनों में पानी से भर जाता है। वहां जीप भी उस समय नहीं जा पाती और किसी प्रकार की सहायता भी वहां नहीं पहुंच पाती है जिससे लोगों को बड़ी परेशानी होती है। एक सड़क मल्हनी से तीहरा को जाती है जिस पर कम से कम चार बाजारें पड़ती हैं। उन बाजारों में रहने वाले और उस सड़क के किनारे के गांवों में रहने वाले आदमियों को किसी तरह की सहायता नहीं पहुंच पाती है और उनके सामान घरों में ही रखे रह जाते हैं। एक सड़क खुटहन से समोदनपुर को जाती है जिस पर चार, पांच बाजार पड़ते हैं। एकसड़क सरायमोदी से खुटहन और एक सड़क रामनगर से गैरवाह को जाती है जिस पर चार, पांच बाजार पड़ते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने निवेदन किया कि उन गांव वालों के साथ हलवाहे सा व्यवहार किया जाता है। इसलिये मैंने माननीय मंत्री जी का ध्यान उस ओर दिलाया, शायद सरकार के पास रुपया था या नहीं था, यह वे जानें। जहां गांव की इन धूल भरी सड़कों पर चलना मुश्किल होता वहां अगर लखनऊ-कानपुर की सड़क को देखा जाय, कानपुर-देहली सड़क को देखा जाय, बनारस से लखनऊ तक देखा जाय, लखनऊ से बरेली तक, बरेली से नैनीताल तक देखा जाय, तो ऐसा मालम पड़ता है कि ये सड़कें हररोज रात में पानी से धो दी जाया करती हैं। क्योंकि जिस वक्त विदेशी लोग आते हैं जो कि आज हमारे अन्नदाता हैं और जिनके कर्जे के बल पर आज हम पल रहे हैं और जिनसे आज रुपया लेकर हम अपनी बुद्धि भी उन्हीं के हाथ बेचने को तैयार हैं। श्रीमन्, इसकी भी मिसाल बहुत जल्द मिलने वाली है कि हम कर्जा लेकर अपनी बुद्धि भी बेच रहे हैं। उनको दिखलाने के लिये बढ़िया बढ़िया सीमेंटड सड़कें बन रही हैं और गांवों की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता है। अन्त में आपके द्वारा मन्त्री जी से मैं यह निवेदन करूंगा कि इन चमत्कारी चीजों को छोड़ कर जरा सच्चाई की तरफ आयें और थोड़ा गांव वालों की तरफ भी ध्यान दें और उनकी भी जिन्दगी को सुधारने का प्रयत्न करें।

**श्री रामस्वरूप वर्मा** (जिला कानपुर)––श्रीमन्, मैं एक निवेदन करूंगा क्योंकि अब बाकी प्रस्ताव उपस्थित मान लिये जायेंगे । इस सम्बन्ध में एक संशोधन करना है कि एक कटमोशन मेरे, राजनारायणजी तथा उग्रसेन जी के नाम है जिसमें कमी करने के उद्देश्य में लिखा है " कंकड़ की सड़कें न बनवा कर, अलकतरा की सड़कें न बनवाना" । इसमें " न" गलत छप गया है । इसलिये यह 'न' निकाल दिया जाय ।

**श्री अध्यक्ष**––ठीक है । एक बात यह कह देना चाहता हूं कि जो लोग इस समय मौजूद नहीं हैं उनके कटमोशंस उपस्थित नहीं माने जायेंगे ।

## अनुदान संख्या ३३

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| [१ | श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री मुक्तिनाथ राय | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करनेका उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । अनुत्पादक व्यय पर अधिक ध्यान देने की नीति से असहमति प्रकट करना । |
| २ | श्री ब्रजनारायण तिवारी<br>श्री होरीलाल यादव,<br>श्री बंशीधर शुक्ल,<br>श्री बुद्धी सिंह तथा<br>श्री स्वामी विश्वेश्वरानन्द । | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । ठेकेदारों द्वारा कार्य करने की प्रथा का निषेध । |
| ३ | श्री राजनारायण,<br>श्री उग्रसेन, तथा<br>श्री रामस्वरूप वर्मा । | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । जनोपयोगी निर्माण-कार्य पर विशेष महत्व न देना । |
| ४ | श्री हरिदत्त काण्डपाल | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । द्वारा हाट––गनाई मोटर मार्ग का प्रस्तुत बजट में प्राविधान न होना । |
| ५ | श्री कन्हैया लाल बाल्मीकि | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।<br>देहाती क्षेत्रों में सड़कों की खराब दशा तथा उस ओर पर्याप्त ध्यान न दिया जाना । |

[ ] ये कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये गये वरन् उपस्थित किए गये माने गये ।

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| ६ | श्री भगवती सिंह विशारद | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । |
| ७ | श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह | जिला उन्नाव में विक्रमपुर रुझिहई, वक्सर और बिहार भगवन्तनगर, ऊंचागांव-वक्सर सड़कों के न बनवाने से उत्पन्न कठिनाइयां ।<br>सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।<br>जिला गोंडा मनकापुर-मसकनवा सड़क पर मनवर नदी पर स्थाई पुल न होने के कारण बर्षा में जनता को कष्ट । |
| ८ | श्री प्रताप सिंह | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि यें १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।<br>खटीमा, सितारगंज, किच्छा-टनकपुर-हल्द्वानी चांभी खन्स्यूं गोखलढुंगा-विजयपुर पट्टाडपानी, सौरफुटक, मोटर मार्गों को तथा गोला नदी, कैलाश नदी, दोहानदी स्थान खन्स्यूं में पुलों का अभी तक पूरा न किया जाना । |
| ९ | श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी | सम्पूर्ण अनुदान क अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।<br>द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५९-५० में भी पिछड़े हुये क्षेत्र (सल्ट) जिला अल्मेड़ा की मोटर रोडें मरचूला भानिला को स्थान न दिये जाने की शिकायत । |
| १० | श्री काशी प्रसाद पांडेय | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देष्य--विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है ।<br>सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील के नेमपुरघाट, दीवारघाट तथा कोयरीपुर के पीली नदी के पुलों को न वनवाना । |

१९५९–६० के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान––अनुदान ५१५ संख्या ३३––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य–निर्माण-कार्यों पर लागत तथा अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५०–नागरिक निर्माण-कार्य–केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता

| क्रम-संख्या | प्रस्तावक का नाम | प्रस्ताव का रूप |
|---|---|---|
| ११ | श्री काशी प्रसाद पांडेय | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । कादीपुर–दोस्तपुर–कूड़ेभार–मझवाड़ा, सड़कों को पक्का न करना । |

## अनुदान संख्या ३४

| | | |
|---|---|---|
| १ | श्री ब्रजनारायण तिवारी तथा श्री मुक्तिनाथ राय | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । अनुत्पादक व्यय की नीति की आलोचना । |
| २ | श्री राजनारायण, श्री उग्रसेन तथा श्री राम स्वरूप वर्मा | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । कंकड़ की सड़कें न बनवा कर, अलकतरा की सड़कें बनवाना । |
| ३ | श्री सूरतचन्द्र रमोला | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । जिला टिहरी–गढ़वाल में ? ऋषिकेश, नरेन्द्रनगर टिहरी, टिहरी मंसूरी के सड़क के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान नहीं है । |
| ४ | श्री राघवेन्द्र प्रताप सिंह | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है । जिला गोंडा में मनकापुर–दर्जीकुंवा सड़क पर यातायात की बहुतायत पर भी उसका पेंट न करवाना । |
| ५ | श्री लक्ष्मण सिंह अधिकारी | सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।<br>कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है । द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५९–६० में भी पिछड़े क्षेत्र की मोटर मार्ग भरचूला मानिला (सल्ट) जिला अल्मोड़ा तथा तत्सम्बन्धी पुल को स्थान न दिये जाने की शिकायत । |

**श्री मुक्तिनाथ राय** (जिला आजमगढ़)---माननीय अध्यक्ष महोदय, सड़कों का निर्माण न केवल आने-जाने के लिये होता है बल्कि इसका सांस्कृतिक तथा सामाजिक असर भी पड़ता है । मुझे यह निवेदन करना है खास कर अपने जिले के बारे में कि स्वराज्य हुए १२, १३ साल हुए हम प्रतिवर्ष देखते हैं कि बड़ी-बड़ी सड़कों का पुनर्निर्माण होता है, सीमेंटड सड़कें बनायी जाती है, लेकिन जहां सड़कें नहीं हैं उनकी तरफ ध्यान नही दिया जाता है । मैं अपने जिले की बात कहता हूं, कहते है कि वहां सड़कें बहुत ज्यादा है, लेकिन जबसे स्वराज्य स्थापित हुआ है मैं समझता हूं तब से शायद बहुत कम सड़कें ली गयी है । ब्रिटिश राज्य में सड़कें वहां बहुत थीं । लेकिन जो सड़कें ली गयी थीं उनका पुनर्निर्माण किया गया है । लम्बा चौड़ा किया गया है शहरों में, लेकिन उनसे सारे जिले की सड़कों पर असर पड़ा हो ऐसी बात नही है । सगड़ी तहसील के उत्तरी हिस्से की बात कहता हूं । वहां के लोग आज भी अपने को बहुत पिछड़े हुए कहते है । अभी १८ मार्च, १९५८ को हमारे राजस्व मंत्री हमारे जिले के प्रोग्राम में गये । वहां एक स्थान है भीमबर । आजमगढ़ से १३ मील उत्तर की तरफ है । बिलरियागंज से वहां ३ मील की एक कच्ची सड़क है । बिलरियागंज से गोलाघाट जाने वाली सड़क १३ मील है । वह बिल्कुल कच्ची है मिनिस्टर साहब का प्रोग्राम बना तो सवाल हुआ कि कैसे आयें । आज तक वहां के लोगों ने किसी नेता का दर्शन नहीं किया था। लिहाजा प्रोग्राम बनाया गया लेकिन मिनिस्टर साहब के जाने के लिये सड़क नहीं थी। बहरहाल प्रोग्राम बना, मंत्री जी गये । तीन मील का रास्ता मान्यवर उनकी गाड़ी ४० मिनट में तय कर पायी और उन्होंने देखा कि किस तरीके से एक भीड़ आ रही है । लोग छोटी-छोटी बैलगाड़ियों पर सामान लाद कर ला रहे हैं और वह क्षेत्र बहुत डेंसली पापूलेटेड है लेकिन कोई सड़क नहीं । पहले कहा जाता है स्वीकृति थी लेकिन बाद में धन की कमी के कारण कटौती कर दी गई । यह सड़क बिलरियागंज से गोलाघाट तक जाती है जो इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है । हरसाल हजारों आदमी गोरखपुर से उतर कर इस पर आते है । इस सड़क पर २५, २६ इक्के, तीन-चार लारियां, बैलगाड़ियां चलती हैं और जनता अपने को बिल्कुल पिछड़ा हुआ मानती है यातायात की सुविधा न होने के कारण ।

मान्यवर, यह पुस्तक जो मिली ह इसको अगर उस क्षेत्र की जनता को दिखायें तो हमको वोट नहीं मिलेगा क्योंकि वह यही कहेगी कि समाजवादी समाज की स्थापना के लिये निर्माण की इतनी योजनायें चल रही हैं लेकिन हमारे यहां कुछ नही। वहां सड़क बिल्कुल है ही नहीं । हमारे यहां एक परसरामपुर डिस्पेंसरी है, साल भर हुआ अस्पताल की स्वीकृति हो चुकी है लेकिन यातायात की सुविधा न होने के कारण कोई डाक्टर वहां जाने को तैयार नहीं है । परिणाम यह है कि वहां ठीक से काम नहीं हो रहा है । अगर कोई बीमार पड़ जाय तो उसको दवा हेतु लेजाना मुश्किल है ।

हमने बजट को पढ़ा तो कुछ चीजों की तरफ हमारा ध्यान गया । यह कहा जाता है कि पैसे की कमी है । लेकिन जो कुछ मैं समझ सका हूं मैं देखता हूं बहुत-सा पैसा ऐसा खर्च किया जाता है जिसको बचाया जा सकता है । जैसे सरकार के सार्वजनिक निर्माण विभाग के सचिव के अधिकार में सचिवालय और दूसरी इमारतों के सम्बन्ध में छोटे और क्षुद्र निर्माण-कार्यों के लिये सुरक्षित धनराशि १,४२,५०० । २---लैंडरिफार्म कमिश्नर के अधिकार में इसी कार्य हेतु ५५,००० रु० । ३---विधायक निवास खंड १ व २ के बीच सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण १६,२०० रु० । ४---पुलिस के इंसपेक्टर जनरल के अधिकार में माइनर और छोटे निर्माण-कार्यों के लिये सुरक्षित धनराशि १,१ ,००० रु० । ५---शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश ३६,१०० रु० । ६---मरम्मत-भवन अनुरक्षण और मरम्मत ११,०५,५०० रु० । ७---कार्यालयों को पहाड़ ले जाने के सम्बन्ध में निवास स्थान की व्यवस्था के लिये ९०,००० रु० । इन इन चीजों के लिये इतना रुपया है । तो हमारे विचार में इन चीजों में से कमी की जा सकती है और उन जगहों के ऊपर जहां सड़कें बिल्कुल नहीं हैं, सीमेंट, तारकोल, की न सही, लोग कंकड़ की सड़क चाहते हैं, वही हो जायं तो अच्छा हो ।

(इस समय १२ बज कर ५९ मिनट पर श्री अध्यक्ष चले गये, और अधिष्ठाता श्री नेकराम शर्मा पीठासीन हुए ।)

मैं मान्यवर, एक निवेदन यह करना चाहता हूं कि अगर सरकार को किसी ओर कमी करनी होती है तो सड़कों के अनुदान में से काट लेती है। इसके लिये मैं निवेदन करूंगा कि हम लोगों को कोशिश करनी चाहिये, कमेटी बनानी चाहिये जो सरकार के सामने सुझाव रखे कि यह धन की कटौती कहां होनी चाहिये, सड़कों के अनुदान में नहीं की जानी चाहिये। क्योंकि आज हम देखते हैं कि तमाम सिंचाई के काम हुए और भी काम होते हैं, जो जरूरी हैं, लेकिन जब तक सड़कों का प्रबन्ध ठीक नहीं होगा तब तक किसान को उसकी मेहनत का उचित फायदा नहीं मिल सकता। मैंने माना नलकूप बनाये गये, खेती अच्छी हुई, लेकिन जब हमारे पास सड़कों की कमी है, कमी क्या नहीं है, तो लोग कच्चे माल को शहरों तक नहीं पहुंचा सकते जिसके कारण उनको माकूल दाम नहीं मिलते। तो मेरी दृष्टि में सिंचाई से, कृषि से, यह मैं नहीं कहता कि यह जरूरी नहीं हैं, हैं जरूरी, लेकिन इन सबसे जरूरी सड़कों का ठीक होना है। किसी भी हालत में हमको इस चीज को बर्दाश्त नहीं करना चाहिये कि जितनी कटौती है वह सड़क के अनुदान में की जाय। क्योंकि जब तक सड़कें ठीक नहीं होंगी तब तक हम अपने को फारवर्ड नहीं मान सकते हैं, पिछड़े हुए बने रह जाएंगे।

मैं दो सड़कों के बारे में निवेदन करना चाहता हूं जिसमें से एक बिलरियागंज–गोला रोड है। यह इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड है। इसको बनाने से लाखों आदमियों को फायदा होगा और जो बाढ़-पीड़ित क्षेत्र हैं जिनमें मदद देनी पड़ती है उससे भी हम बच जाएंगे। दूसरी सड़क बूढ़नपुर महाराजगंज–बिलरियागंज–जीअनपुर है। यह दोहरीघाट–इलाहाबाद प्राविन्शियल हाईवे से जीअनपुर के पास मिल जाती है। यह ३०–३५ मील लम्बी होगी। लेकिन मान्यवर बहुत घने क्षेत्र से आती है। यहां पर ३–४ कस्बे हैं, पुलिस स्टेशंस है और बहुत घनी आबादी है। वहां के रहने वाले लोगों की आर्थिक दशा पर इसका बहुत असर पड़ेगा। इसलिये इन दोनों सड़कों का बनवाना बहुत जरूरी है।

अंत में मैं यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि यह बड़े-बड़े जो काम होते हैं हम चाहे उनमें से कटौती करें लेकिन सड़कों का काम किसी तरह से कम न होने पावे। हम सबको मिलकर इस बात की कोशिश करनी चाहिये और सरकार के ऊपर दबाव डालना चाहिये। मैंने सुना था कि केन्द्रीय सरकार ने पूर्वी जिलों के उत्थान के लिये एवं सड़कों के निर्माण के लिये कुछ धन स्वीकार किया है। पता नहीं वह प्राप्त हुआ या नहीं ? अगर नहीं प्राप्त हुआ हो तो केन्द्रीय सरकार के ऊपर दबाव डाला जाय कि वह हमको मिले।

**श्री प्रताप सिंह** (जिला नैनीताल)—माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं जिला जौनपुर के माननीय सदस्य द्वारा रक्खे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज के अनुदान की क्या अहमियत है, उसको मैं ५ जनवरी, सन् १९५८ को भारतीय रोड कांग्रेस में हमारे राष्ट्रपति ने जो उपदेश दिया था पढ़कर बताना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि "हमारे राष्ट्र का यह आदर्श है कि सबको समान अवसर मिले और पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास द्रुतगति से किया जाय ताकि वे क्षेत्र भी अधिक विकसित क्षेत्रों के समकक्ष आ सकें।" मान्यवर, रोड कांग्रेस में हमारे देश के सबसे बड़े महापुरुष ने ये शब्द कहे। मैं आपके द्वारा माननीय निर्माण मंत्री जी से यह पूछना चाहता हूं कि आज हमारी सड़कों को कितनी अहमियत दी जाती है ? इस बात का ज्वलन्त उदाहरण यह है कि एक साल में पचास लाख रुपये की कटौती की गई। एक ओर कहा जाता है कि जो इलाके उपेक्षित हैं उनको आगे ले जाना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि पचास लाख रुपये की कटौती क्यों हुई ?

सरकार मानती है कि नागपुर वाली पालिसी रिवाइज की गई। १९४३ में नागपुर की बात थी कि पांच मील का कोई ऐसा इलाका नहीं होना चाहिये जहां सड़क न हो। लेकिन आज दो मील की दूरी पर पक्की सड़क और एक मील की दूरी पर कच्ची सड़क की बात है।

[श्री प्रताप सिंह]

लेकिन जो माननीय मंत्री जी ने उपदेश दिया उससे जाहिर है कि अभी पांच पंचवर्षीय योजनायें और आयेंगी तब वह पूरा होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि लैप्सेज क्यों होते हैं। पिछले साल भी सुझाव दिया था कि चीफ इंजीनियर साहब का परसनल लेजर एकाउन्ट खुलना चाहिये जिससे लैप्सेज बचाई जायं।

अभी इस प्लान में ३७ पुल हैं पहाड़ों के लिये। लेकिन माननीय मंत्री जी से जब सवाल किया जाता है कि क्यों नहीं बने तो जवाब मिलता है कि लोहा नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि ब्लैक मार्केट में लोहा बिकता है तो सरकार के लिये क्यों नहीं है? यह पुस्तिका बंटी है इसमें १३७ लाख रुपया पहाड़ों के लिये रक्खा गया है। जब कि केंद्रीय सरकार ने ५ करोड़ रुपया हिमांचल प्रदेश को दिया है और जब कि सब तरफ से पर्वतीय इलाके पर विशेष ध्यान दिये जाने की बात है, लेकिन हमारे यहां कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया है। हम इस विभाग की पालिसी में चेंज चाहते हैं। पहले कोई चीज चीफ इंजीनियर के यहां से चलती है उस के बाद सेक्रेटरिएट लेविल पर आती है और उसके बाद वह वित्त विभाग में जाती है। इस तरह से ६-६ मास तक फाइलें पड़ी रहती हैं। प्रोपोजल्स सेक्रेटेरियेट के विभागों में और फाइनेंस विभाग में पड़े रहते हैं और जब मार्च आता है तो तार जाते हैं कि रुपया लैप्स हो जायगा उस का उपयोग करो। मैं चाहता हूं कि इस पालिसी को चेंज किया जाय। क्या जरूरत है कि ६ मास इस में लगाये जायं और जो हमारे निर्माण-कार्य होने हैं, जिन के लिये हमारे राष्ट्रपति तक कहते हैं और मंत्री महोदय कहते हैं कि हम हर झोपड़ी तक सड़क ले जायंगे, कैसे वह ले जायेंगे? क्या कोई अलादीन का चिराग एक दम से वह जला देंगे और सड़कें बन जायंगी। हम चाहते हैं कि यह जो तरीका है जिस में बजट मंजूर होने में देर लगती है उसको सुधारा जाय।

दूसरे, जो प्रोपोजल आते हैं और जिन को टेक्निकल आदमी भेजते हैं उन को नान-टेक्निकल मैन एगजामिन करते हैं। अगर ऐसा है तो किस तरह से प्लान ठीक से चल सकता है मेरी समझ में नहीं आया। यह भी कहा गया, और कल बहुत बहस हुई कि कोआपरेटिव को प्रोत्साहन दिया जाय, लेकिन आज प्रोत्साहन बड़े-बड़े पूंजीपति ठेकेदारों को दिया जाता है। पी० डब्लू० डी० विभाग के बारे में वैसे ही करप्ट होने की बात कही जाती है, लेकिन जबतक विभाग में यह ठेकेदारी सिस्टम रहेगा तबतक सुधार इस स्थिति में नहीं हो सकता। एकानामीक कमेटी की रिपोर्ट के पेज ४५ पर उस की भी यह सिफारिश है कि जब तक ठेकेदारी सिस्टम रहेगा तबतक करप्शन रहेगा। परसेंटेज के विषय में मुझे सन्देह है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन कोआपरेटिव सिस्टम से अगर काम कराये जायं तो बेहतर होगा। हमारे यहां अल्मोड़ा में एक स्कूल का ठेका कोआपरेटिव को दिया गया था काम अच्छा हुआ लेकिन समय से पैसा नहीं दिया गया और उस का नतीजा यह हुआ कि वह कोआपरेटिव सोसाइटी खत्म हो गई। आप जानते हैं कि मजदूरों के घने परिश्रम के फलस्वरूप सड़क या तमाम काम बनते हैं। मजदूरों से कहीं भी जाकर मंत्री जी मिनिस्टर की तरह नहीं, एक लेमैन की तरह पूछें कि कब से तुम को वेतन नहीं मिला है तो उन को मालूम होगा कि तीन-तीन मास से पैसा नहीं मिला है, आज भी मजदूरों की वही दिक्कत है वही हालत है, वही साढे ३३ रुपया वेतन आज भी उन को मिलता है जो अंग्रेजी जमाने में मिलता था और वह भी तीन तीन महीने के बाद। माननीय उपमंत्री जी स्वयं पिठौरागढ़ का मुआयना कर आये हैं और उन्होंने यह जानकारी कर ली थी कि यह बात ठीक है कि मजदूरों को देर से पैसा मिलता है। तमाम इंजीनियर्स, ओवरसियर्स हैं, लेकिन मजदूरों को समय से वेतन नहीं मिलता।

बड़ा दावा किया जाता है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि दूसरे देशों के मुकाबले में हमारे यहां का रोड सिस्टम कहां पहुंचा है। यूनाइटेड किन्गडम का है २०९, फ्रांन्स का है २३७, यू० एस० पी० का है १११, जर्मनी का है ८९ और सीलोन का है ७० और अगर हम अपने देश का देखते हैं तो वह केवल २२ है जो कि यूनाइटेड किंगडम का १/९ है और सीलोन का है १/३,

इस तरह से हम अपने टारगेट को किस तरह से पूरा कर सकते हैं और हमारा नागपुर का जो फार्मूला है वह भी अधूरा रहा जा रहा है। हमारी १९५७–५८ की रिपोर्ट कहती है कि हमें अपने यहां इतनी सड़कों को पूरा करना है और हमें ४० हजार मील सड़कें बनानी है, लेकिन अगर हम इस तरह से चलेंगे तो मैं यकीन दिलाऊंगा कि अभी हमें इस तरह की ५ पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरत होगी। इस तरह से हम किस तरह से यातायात को बढ़ा सकते हैं। किसी जगह सड़क बनने से केवल चलने का आराम नहीं होता बल्कि उस से देश की सभ्यता और संस्कृति को भी उभरने का मौका मिलता है। यह विभाग तो बहुत से नामों से मशहूर है 'प्लन्डर विध आउट डेंडर' और 'वैस्टेज डिपार्टमेंट' आदि। मेरे मंत्री जी से शिकायत नहीं है वह तो काफी दिलचस्पी से काम करते हैं और गर्मी में नैनीताल जाकर श्रमदान भी करते हैं। तो मैं इन शब्दों के साथ चाहता हूं कि आज प्लानिंग का और पी० डब्लू० डी० का कोआर्डिनेशन होना चाहिये। पी० डब्लू० डी० की कुछ स्कीम्स होती हैं और प्लानिंग से रुपया देर में मिलता है। और "प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट मीन्स आफ कम्युनिकेशन" (Planning is meaningless without means of Comuunication)"। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जहां खाने की प्रमुखता है वहां दूसरा स्थान सड़कों को मिलना चाहिये, लेकिन हमारा सारा प्लानिंग कमीशन इसपर चुप है। मैं चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के एक्सपर्ट्स प्लानिंग कमीशन को लिखें कि प्लानिंग कमीशन यहां के लिये रुपये की मंजूरी जल्दी से जल्दी दे और हमारा जो टारगेट है कि दो मील पर पक्की सड़क और एक मील पर कच्ची सड़क होनी चाहिये, वह तभी हो सकता है जब सारे लोग इसमें दिलचस्पी लें, जो अच्छे अफसरान हैं उनकी तारीफ की जाय और जो गल्ती करें उनकी गल्ती बतलाई जाय। मुझे उम्मीद है कि मंत्री जी इस करप्शन को रूट आउट करने में अगर हमारा साथ चाहेंगे तो हम उसके लिये तैयार हैं।

**श्री सूरतचन्द रमोला** (जिला टेहरी गढ़वाल)—अधिष्ठाता महोदय, यह सार्वजनिक निर्माण के जो अनुदान प्रस्तुत हैं मैं उनका समर्थन करता हूं और जो मेरा कटौती का प्रस्ताव है उसको मैं रेस नहीं करना चाहता हूं, बल्कि मैं उसके संबंध में अपने कुछ सुझाव पेश करना चाहता हूं।

**श्री अधिष्ठाता**—माननीय सदस्य, जिस समय आपका नाम पुकारा था तभी आपको वापस ले लेना चाहिये था। अब बिना हाउस की अनुमति के इस तरह से कटौती का प्रस्ताव वापस नहीं होगा।

**श्री सूरतचन्द रमोला**—तो मैं बाद में वापस ले लूंगा।

यह जो पुस्तक आज बंटी है मैं उसको उत्सुकता से देख रहा था। इसके पहले ही पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि सड़कों का केवल आर्थिक महत्व ही नहीं है बल्कि सामाजिक एवं उसका सांस्कृतिक मूल्य भी कुछ है। इस बात को मद्देनजर रखते हुये मैं यह अर्ज करूंगा कि सार्वजनिक निर्माण विभाग का महत्व प्रदेश के किसी अन्य विभाग से ज्यादा है और जबतक इस तरह का विभाग हमारे यहां अच्छी तरह से फलता फूलता नहीं होगा तब तक हमारे यहां कोई उन्नति संभव नहीं है।

मैं इस संबंध में सिर्फ दो एक सुझाव माननीय मंत्री जी के सामने रखना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि विभाग इस ओर अगर ध्यान दे तो यह अच्छी तरह से कार्य कर सकता है। पहले तो मैं उनके शेड्यूल आफ रेट्स के बारे में अर्ज करूंगा।

**श्री अधिष्ठाता**—रमोला जी, आपका जो कटौती का प्रस्ताव है उसमें केवल "जिला टिहरी-गढ़वाल में ऋषीकेश, नरेंद्रनगर टिहरी, टिहरी–मंसूरी के सड़क के निर्माण की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित करना", यह आपका विषय रहेगा।

**श्री प्रताप सिंह**---मान्यवर, मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं कि जब पहले कटौती का प्रस्ताव रखा गया तो उसके बाद सारे प्रस्ताव रखे हुए माने गये, तो क्या माननीय सदस्य अन्य प्रस्तावों पर नहीं बोल सकते हैं ?

**श्री अधिष्ठाता**---माननीय सदस्य को मालूम है कि इस विषय में व्यवस्था हो चुकी है कि जो माननीय सदस्य कटौती का प्रस्ताव रखेंगे वह उसी के विषय तक सीमित रहेंगे जिस विषय पर उनके नाम का कटौती का प्रस्ताव है और अन्य सदस्य जिनके नाम कोई प्रस्ताव नहीं है वह सभी विषयों पर बोल सकेंगे।

माननीय रमोलाजी अपना भाषण जारी रखें।

**श्री सूरतचन्द रमोला**---पहले तो मैं यह अर्ज करूंगा कि जो वक्त जाया हुआ है वह मुझे दिया जाय और दूसरे, मेरा जो कटौती का प्रस्ताव पेश है उसमें जो मेरे सजेस्शंस हैं उन्हीं के मुताल्लिक मैं कह रहा हूं और उसपर ही नहीं, बल्कि प्रदेश में जो निर्माण कार्य हो रहे हैं उन सब पर वह लागू किया जा सकता है।

तो जो शेड्यूल आफ रेट्स पी० डब्लू० डी० विभाग के हैं वह इतने कम हैं कि अगर माननीय मंत्री जी खुद उन शेडयूल आफ रेंट्स पर काम करवायें तो वह कार्य नहीं हो सकता है। उदाहरण के लिये "आर० आर० मैशीनरी इनलाइन," मेरे खयाल से ४२ रुपया सैकड़ा के हिसाब से है जब कि मैटोरियल कास्ट ४० रुपया सैकड़ा पड़ती है और उसपर भी जब उनके टेंडर्स होते हैं तो वह काफी गिर जाते हैं। इसका नतीजा यह होता है कि काम ठीक ढंग से नहीं हो पाता, स्पेसिफिकेशंस के मुताबिक नहीं होता और उसमें इनफीरियारिटी आ जाती है।

एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि इन्हीं शेडयूल आफ रेंट्स की वजह से हमारे काम का स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है। यह स्टैंडर्ड तभी मेंटेन किया जा सकता है जब हम अपने शेड्यूल आफ रेट्स को ठीक करें।

दूसरे हमारे यहां जो पी० डब्लू० डी० का निरीक्षण कार्य है वह कुछ ठीक नहीं है। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि इसके लिये जो हमारे सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, विधान मंडल के सदस्य हैं, डी० एम० हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के अध्यक्ष हैं, इन सब को मिलाकर एक विजिलेंस कमेटी बनायी जाय।

**श्री अधिष्ठाता**---आप विषयान्तर हो रहे हैं। जो आपका कटौती का प्रस्ताव है आप उसी पर बोलिये।

**श्री सूरतचन्द रमोला**---उसी के संबंध में मैं अर्ज कर रहा हूं, वह तो मैं एक भूमिका सी बांध रहा था। तो यह जो सड़कें बनी हैं या जो इनके हिस्से बने हैं वह इतने कम हैं या खराब हैं कि मैंने अभी पिछले दिनों माननीय मंत्री जी के नाम एक पत्र भेजा था जिसमें इस बात का जिक्र किया था कि ऋषिकेश और टेहरी के बीच में जो सड़क बनी है उसका कुछ हिस्सा मई या जून में पक्का किया गया था और अगस्त के महीने में वह टूट गया। तो जो मैं विजिलेंस कमेटी का जिक्र कर रहा था वह यों कर रहा था कि यदि कोई विजिलेंस कमेटी बनायी जाय तो वह वक्त बेवक्त काम को देख सकती है क्योंकि जैसा मैंने अर्ज किया, टेंडर जब 'लो' हो जाता है तो ठेकेदार कम से कम कीमत में उस काम को कराने की कोशिश करता है। तो यह विजिलेंस कमेटी प्रत्येक जिले में होनी आवश्यक है ताकि काम का स्टैंडर्ड ठीक रहे।

जो सड़कें बनायी जा रही हैं उनके एलाइनमेंट्स एक प्रकार से बिल्कुल आरबिट्रेरी होते हैं। होता यह है कि इंजीनियर महोदय ने अपना मैप खोला और उसकी हाइट्स वगैरह देख कर एक तरह का आरबिट्रेरी एलाइनमेंट कर देते हैं। जब वह एक्चुअल वर्किंग में आता है तब उसको खामियों का पता चलता है। हमें ज्यादा से ज्यादा वहां की पापुलेशन को कंटैक्ट

करना चाहिये और नक्शे को न देख कर मौके पर मेजरमेंट होना चाहिये। जो लम्प सम के एस्टीमेट्स होते हैं वे अक्सर गलत और बिल्कुल आरबिट्रेरी होते हैं जिससे इस विभाग को तो नुकसान होता ही है पर कार्य भी खराब होता है और जो आदमी काम करने वाला होता है वह हमेशा के लिये बड़े भारी नुक्सान में रहता है।

इसके अलावा विजिलेंस कमेटीज के साथ-साथ लेबरर्स कोआपरेटिव सोसाइटीज को सड़कें बनाने का काम देना चाहिये। ऐसा करने से केवल एक आदमी का फायदा न हो कर तमाम मजदूरों का फायदा होगा। मैं मंत्री जी का अनुगृहीत हूं कि उन्होंने इस ओर कुछ कदम उठाया भी है, लेकिन वह अभी हाफ-हार्टेड है। इस ओर अगर मंत्री जी अधिक ध्यान दें तो लोग दिलचस्पी से काम कर सकते हैं।

मैं एक और अर्ज करूंगा। अभी हमारे जिले में दातार साहब, राज्य मंत्री, भारत सरकार, गये थे और उन्होंने सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने अपनी रिपोर्ट इस संबंध में भेजी है और उनका सुझाव जो एक पैरे के रूप में है, उसको मैं आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहता हूं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में सड़कों का ही जिक्र किया है। वह इस प्रकार है कि :

"I may add that most pressing need of this district is the immediate improvement of the means of communication which are inadequate wherever they exist and which require to be augmented at other places. This work requires the highest priority and to the extent that it is possible, the Government of India might consider what financial aid can be rendered in this respect in addition to what is being done already by the Central and State Governments."

**श्री अधिष्ठाता**––इसका संक्षेप में हिन्दी में अनुवाद कर दीजिये।

**श्री सूरतचन्द रमोला**––इसमें तो मेरा समय खत्म हो जायगा। मैं अर्ज करूंगा कि इस पैरे में यही है कि कम्युनिकेशन की इस डिस्ट्रिक्ट में बहुत आवश्यकता है और ज्यादा से ज्यादा रुपया इस जिले की सड़कों पर खर्च किया जाय और सड़कों को प्रायोरिटी दी जाय। हमारे जिले टेहरी-गढ़वाल का कुल एरिया चार हजार पांच सौ स्क्वायर मील है और मेरे निर्वाचन क्षेत्र का एरिया २ हजार स्क्वायर मील है जिसमें से केवल ५० मील सड़क बनी है।

अधिष्ठाता महोदय, मैं एक जिक्र कर दूं कि यदि मैं जिन्दगी भर चलता रहूं तब भी प्रत्येक गांव में नहीं पहुंच सकता। इसीलिये जो दातार साहब ने लिखा है उस पर सरकार ध्यान देगी ऐसी मेरी आशा है।

**श्री अधिष्ठाता**––आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री सूरतचन्द रमोला**––श्रीमन्, केवल एक मिनट में मैं यह कहना चाहता हूं कि इन सुझावों के अलावा मेरे जिले में द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो काम हैं उनका निर्माण भी नहीं हो रहा है। इसके अलावा पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत जो टेहरी का पुल है उस पर भी काम शुरू नहीं किया गया है और वह बहुत ही महत्वपूर्ण पुल है इससे सारे जिले को क्षति हो रही है।

**श्री अधिष्ठाता**––आपका समय समाप्त हो गया।

**श्री देवनारायण भारतीय** (जिला शाहजहांपुर)––अधिष्ठाता महोदय, अनुदान संख्या ३३ और ३४ के संबंध में जो विरोधी पक्ष की ओर से कटौती के प्रस्ताव पेश हुये हैं और विशेषकर सोशलिस्ट पार्टी की ओर से, मैं उनका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं सबसे पहले

[श्री देवनारायण भारतीय]

श्रीमन्, सरकार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयत्न करूंगा कि हमारी सरकार का यह कहना है कि वह समाजवादी व्यवस्था की ओर आगे बढ़ रही है। सार्वजनिक निर्माण की योजनायें और बजट के प्रस्ताव जो माननीय मंत्री जी ने पेश किये हैं और जिन मुख्य कार्यों को वह करने जा रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुये, मैं यह प्रमाणित करने का प्रयत्न करूंगा कि यह अनुदान समाजवादी व्यवस्था की ओर आगे नहीं बढ़ायेंगे, बल्कि हमें उसी एक पूंजीवादी अथवा शहरीवादी व्यवस्था के अन्दर सीमित रक्खेंगे, जो प्रथा पहले से चली आ रही है उसी गोरखधंधे में फंसाये रखने के लिये यह अनुदान और मंत्री जी के सुझाव संकेत कर रहे हैं।

इन अनुदानों को पेश करते हुये मंत्री जी ने बताया कि वह विधान भवन में लाखों रुपया खर्च करके सुधार करने जा रहे हैं, लखनऊ में लाखों रुपया लगाकर स्पोर्ट्स स्टैडियम बना रहे हैं और मैं देखता हूं कि इसी अनुदान में कुछ सीमेंट की और अलकतरा की सड़कों को चौड़ी करने जा रहे हैं और कुछ सीमेंट तथा अलकतरा की नई सड़कें बनाने जा रहे हैं। उन्होंने यह नहीं देखा कि प्रांत का ८० फीसदी भाग जिसमें कच्ची, पक्की, कंकड़ अथवा सीमेंट की कोई भी सड़क नहीं है वहां आवश्यकतानुसार सड़कें बनवाने का अथवा प्रांत का जो बहुत बड़ा भाग आज सांस्कृतिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से और मैं कह सकता हूं कि राजनीतिक दृष्टि से भी पिछड़ा हुआ है उसको समान स्तर पर लाने का इन अनुदानों द्वारा कोई भी प्रयत्न माननीय मंत्री जी ने नहीं किया है। आज सुबह इस विभाग की ओर से एक पुस्तिका वितरित की गयी है। मैंने इस पुस्तिका को आद्योपान्त साधारण तौर से देखने का प्रयत्न किया। इसमें मैंने २८ चित्र पाये, उस चित्र को शामिल करके जो इसके टाइटिल पेज पर है। क्या यह पुस्तिका यह साबित करती है कि यह गरीब देश के नियोजन काल के निर्माण का बजट है? इसमें पृष्ठ १२ पर एक चित्र है जिसकी ओर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिसमें एक इंजन सड़क कूटता दिखलाया गया है। क्या यह भी कोई ऐसी चीज़ थी जिसको इसमें शामिल करने की जरूरत थी? इस से यह प्रमाणित है कि वाह्याडंबर द्वारा सुन्दर-सुन्दर चित्रों द्वारा इस सदन के माननीय सदस्यों को बहकाने की और इस विभाग का ध्यान अधिक है बजाय इसके कि उन ८० फीसदी पिछड़े हुए लोगों को आकर्षित करने के लिये यह सरकार कोई भलाई का ठोस काम करे। इस पुस्तिका में या माननीय मंत्री जी के भाषण में कोई भी ऐसी बात नहीं कही गयी जिससे उन पिछड़े हुये भागों के निवासियों को संतोष हो। अगर माननीय मंत्री जी ने इस बात का प्रयत्न किया होता कि कोई भी गांव पक्की सड़क से ५ मील के फासले से ज्यादा पर न रह जावे और कोई भी गांव कच्ची सड़क से २ मील से ज्यादा फासले पर न रह जावे तो मैं कह सकता था कि यह अनुदान हम को समाजवादी व्यवस्था की ओर ले जाने वाले साबित होंगे। लेकिन मुझे दुख है कि मैं माननीय मंत्री जी से मतभेद रखता हूं और जो प्रस्ताव विरोधी पक्ष की ओर पेश किये गये हैं उनका समर्थन कर रहा हूं।

मैं एक बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान और दिलाना चाहता हूं कि प्रायः इस विभाग की ओर से किये गये सभी कामों के बजट के अनुमानित आंकड़ों से वास्तविक खर्चा ड्योढ़े तक पहुंच जाता है। ३० करोड़ का अनुमान होता है और खर्च हो जाता है ४६ और ५० करोड़। इस में कहीं न कहीं मौलिक भूल है। इस बारे में माननीय मंत्री जी को विशेष सतर्क रहना चाहिये कि यह भूल कहां पर है, यह आंकड़े क्यों बढ़ जाते हैं। इस गरीब देश को महात्मा गांधी की कृपा से हमको स्वाधीनता मिली और हम अपना नियोजन चला रहे हैं तो क्या हमारी योजनायें इस फिजूलखर्ची के साथ चलायी जायं जिसमें जहां दस रुपया खर्च करना चाहिये वहां पर पंद्रह रुपये खर्च हो जायं? इसके अलावा इस विभाग में हर साल कुछ रुपया लैप्स हो जाता है। यह भी बड़े दुख की बात है। जो रुपया हम किसी भले काम के लिये रखते हैं वह काम उस वर्ष में पूरा नहीं हो पाता और धनराशि लैप्स हो जाती है। आगे

इस पर माननीय मंत्री जी ध्यान रखें। मैं यह भी कह देना चाहता हूं, माननीय प्रतापसिंह जी ने मुझसे पहले इस बारे में कहा है कि यह विभाग "वेस्टेज डिपार्टमेंट" कहलाता है, "प्लंडर विधाउट डेंजर" की भावनाओं से विभूषित है। ऐसी सूरत में श्रीमन्, माननीय मन्त्री जी को विशेष सतर्क होने की जरूरत है कि यदि इस विभाग में भ्रष्टाचार होता है तो कहां पर होता है? क्या ऐसा तो नहीं होता कि जो बड़ी-बड़ी धनराशियां रखी जाती हैं उनको ठेकों के जरिये से गलत आदमियों को ठेका दे करके ओवरसियरों और इंजीनियरों द्वारा लम्बा प्रतिशत कमीशन के रूप में वसूल किया जाता है। मान्यवर, आप तो बहुत थोड़ा समय दे रहे हैं, मैं दो चार मिनट और चाहूंगा....

**श्री अधिष्ठाता**---आप के दो मिनट और हैं।

**श्री देवनारायण भारतीय**---उसके अलावा दो मिनट और चाहूंगा।

**श्री अधिष्ठाता**---आप अपना भाषण जारी रखें।

**श्री देवनारायण भारतीय**---वह ठेकेदार और ओवरसियरों के मिल जाने से और कुछ प्रतिशत ओवरसियरों और इंजीनियरों की जेब में पहुंच जाने से उस धनराशि का दुरुपयोग होता है। उसी का यह परिणाम है कि सदन में कल ही जिक्र था कि रिहैंड बांध में दरार आ गई है और दरार के बारे में यद्यपि सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि उससे कोई खतरा नहीं है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उस दरार का आना हमारी सरकार के लिये एक दुख और लज्जा की बात है। आज से तीन, चार सौ वर्ष पहले मुगल काल में बड़ी-बड़ी इमारतें बनाई गईं। तब न इंजीनियरिंग कालेज थे, न लंदन या मास्को से या वाशिंगटन से हमारे देश के इंजीनियर शिक्षा प्राप्त कर के आते थे। उस समय के इंजीनियरों ने जो इमारतें बनाई हैं आज तीन सौ वर्ष के तूफानों के सह लेने के बाद भी उनमें दरारें पैदा नहीं होतीं, लेकिन आज हमारी योजनाओं के अन्तर्गत इमारतें बन कर के पूरी नहीं हो पातीं और उनमें दरारें हो जाती हैं। उस दरार के बारे में माननीय मन्त्री जी जानने का प्रयत्न करें कि उसका कारण क्या है।

अब मैं अपने जिले की दो-एक बातें बहुत संक्षेप में कह के अपनी बात समाप्त कर दूंगा। शाहजहांपुर जिले में पहली पंचवर्षीय योजना में दो सड़कें रखी गयी थीं। एक मैलानी और पुवायां के दरमियान में और दूसरी जलालाबाद और ढाई घाट के दरमियान में। मैं श्रीमन्, आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि अभी तक ये दोनों सड़कें अपूर्ण हैं। इन दोनों के दूसरी पंचवर्षीय योजना में भी पूरा हो जाने की कोई आशा नहीं है। इस प्रगति को देख करके मैं अपना दुख प्रकट करता हूं और इससे अधिक कुछ नहीं कर सकता? दूसरी योजना के लिये जो सड़कें रखी गई थीं उनमें एक तो शाहजहांपुर को पीलीभीत से कनेक्ट करने वाली सड़क है और एक जरीनपुर से उसावा की सड़क है, ये दो सड़कें द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में रखी गई थीं। आज दूसरी योजना के तीन वर्ष बीत चुके हैं। मैं कह सकता हूं श्रीमन्, मैं वहीं का निवासी हूं, कि अभी तक जरीनपुर से उसाला वाली सड़क पर सिवाय मिट्टी पड़ने के, और वह भी श्रमदान से कोई भी अन्य कार्य नहीं हुआ है और न शीघ्र होने की आशा है। मुझे सन्देह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना समाप्त हो जायगी और वे सड़कें नहीं बनायी जायंगी। तीसरी पंचवर्षीय योजना के लिये श्रीमन्, मैंने गत वर्ष भी यह सुझाव दिया था और उसे फिर दोहरा देता हूं कि हमारे जिले की जो सब से आवश्यक सड़क है वह कटरा कस्बे को खुदागंज कस्बे से जोड़ने वाली सड़क है। दोनों व्यापारिक नगर हैं और उनके बीच में सड़क न होने की वजह से हमारे जिले के व्यापार को बहुत बड़ी हानि पहुंच रही है। एक दूसरी सड़क है जो कांठ से मदनापुर को मिलाती है। मैं निवेदन करूंगा कि इन सड़कों को माननीय मंत्री जी

[श्री देवनारायण भारतीय]

तीसरी योजना में लेने की कृपा करेंगे। इतना कह कर मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री काशी प्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---अधिष्ठाता महोदय, माननीय सार्वजनिक निर्माण मन्त्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान के अधीन मांग की धनराशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय।

श्री अधिष्ठाता---आप को कटौती का प्रस्ताव पेश करने की जरूरत नहीं है। वह सब पेश हुए मान लिए जायंगे। आप भाषण दें।

श्री काशी प्रसाद पांडेय---माननीय अधिष्ठाता महोदय, सड़कों का महत्व किसी से छिपा नहीं है। सब से ज्यादा आजकल गांवों का विकास करने में जितना काम सड़कों का है उतना किसी दूसरी चीज का नहीं है। आज हमारी सरकार गांवों का विकास करने के लिए दूसरी नयी-नयी योजनाएं गांवों में पहुंचाना चाहती है, किसानों की उन्नति करना चाहती है, किन्तु बिना सड़कों के हम उन गांवों में पहुंच ही नहीं सकते हैं। सड़कों और पुलों के न होने के कारण गांवों में किसी चीज को पहुंचा नहीं पाते। यहां तक कि गांवों में जब दैवी प्रकोप से बाढ़ आ जाती है तो वहां तक पहुंचने के साधन न होने के कारण कोई सहायता नहीं पहुंचा सकते हैं। नेमपुर घाट पर अभी तक पुल नहीं बना है। यह ऐसी जगह पर स्थित है जहां पर बाढ़ आया करती है। जहां आने-जाने का कोई साधन नहीं है। इसी नेमपुर घाट के आगे मझवाड़ा और दोस्तपुर के पास पीली नदी के बीच में एक स्थान कान्तागंज है, उसके बाद ३०० एकड़ की भूमि पड़ी हुई है जहां पर किसी उद्योग का विकास किया जा सकता है। नेमपुरघाट पर पुल न होने के कारण आज तक वहां कोई पहुंच नहीं पाया है। नेमपुर घाट, दीवारघाट, और कोयरीपुर के पीली नदी के यह तीनों पुल ३ वर्ष से बराबर स्कीम में रखे जाते हैं, किन्तु सरकार का खयाल कुछ नहीं जाता। कोयरीपुर की पीली नदी का पुल बनने के लिये रुपया १९५४-५५ से बराबर बजट में आता है, लेकिन उस पर कोई श्रीगणेश नहीं किया जाता। यह तीन पुल बनने इतने आवश्यक हैं कि जिससे जनता को बहुत सुविधा मिलेगी। कादीपुर-दोस्तपुर सड़क के लिये और कूड़ेभार-मझवाड़ा सड़क के लिये बराबर बजट में रुपया रखा जाता है, लेकिन उस पर काम आरम्भ नहीं किया जाता। श्रीमन्, यह कादीपुर-दोस्तपुर सड़क इतनी आवश्यक है कि अगर यह बन जाय तो इससे आगे के इलाके भी मिल जाते हैं। मझवाड़ा से ४ मील तक इस सड़क को पक्का किया जा सकता है। कूड़ेभार से मझवाड़ा तक अगर सड़क पक्की बन जाय तो उसके आगे हलियापुर तक बढ़ाई जा सकती है, जहां पर विभाग के द्वारा पुल बन रहा है। उस इलाके को पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है। अगर यह पुल बन जाय तो इस इलाके के लिये मार्ग खुल जाता है। यह इलाका ऐसा है कि जहां पर आये दिन कत्ल हुआ करते हैं और बाढ़ आया करती हैं। यहां पर यातायात का साधन न होने के कारण सारा बराज का परगना बहुत ही पिछड़ा पड़ा हुआ है। अगर यहां पर पुख्ता पुल बन जाय तो इससे इस इलाके का उद्धार हो सकता है। जमींदारों के जमाने में कुछ प्रबन्ध पुल का था किन्तु अब ठीक प्रकार से कोई यातायात का साधन न होने के कारण किसी ने उसको देखने की तकलीफ नहीं की। लोग वहां पर वैसे आया करते हैं किन्तु सड़क न होने के कारण पहुंचा नहीं जा सकता है। मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि इस सड़क को जल्दी से जल्दी पक्की करने की कृपा की जाय।

श्रीमन्, सड़कों के विषय में माननीय मन्त्री जी से मेरा निवेदन यह है कि जो सड़क कई जिलों को मिलाती हैं उनको पहले प्रधानता दी जानी चाहिये और उनका प्रदेशीय स्तर पर सर्वे होना चाहिये और उनको भी योजना में लेना चाहिये। ऐसी सड़कों से दूसरे जिलों के लिये यातायात

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का लाभ होने से विकास के सिलसिले में और व्यापार के सिलसिले में बहुत लाभ हो सकता है। श्रीमन्, मेरे जिले में सुल्तानपुर से अकबरपुर जाने वाली सड़क सिमरी बाजार तक पक्की है। उसको श्रमदान के द्वारा बनाया गया था अब उसके आगे वह पक्की बन जाय तो बहुत लाभ इससे हो सकता है। यह सड़क कई जिलों को मिलाती है। इससे आगे का रास्ता खुल जायगा मोतीगरपुर से दोस्तपुर होती हुई मालीपुर–अहरौरा सड़क पक्की है। नेमपुर घाट पर ८ साल से पुल न बनने के कारण यातायात की बड़ी असुविधा है।

श्रीमन्, मैं इन शब्दों के साथ माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करते हुये यह अनुरोध करूंगा कि ऐसी जितनी भी सड़कें प्रदेश में हैं जो एक जिले को दूसरे जिले से मिलाती हैं, वे चाहे नियोजन विभाग द्वारा बनायी जाती हों अथवा सार्वजनिक विभाग द्वारा, उनका सर्वे कराया जाय और उनको प्राथमिकता दी जाय। जिस प्रकार और सदन के दूसरे सदस्यों की राय है, मैं भी अनुरोध करूंगा कि इस बजट में से कोई कटौती न की जाय, क्योंकि ऐसा करने से जो सब से बड़ा काम गांव में होने वाला है वह रुक जाता है। इसके लिये तो बजट में अधिक से अधिक धन दिया जाना चाहिये। जो छोटी-छोटी पुलियां श्रमदान द्वारा पूरी करायी जाती हैं उनको भले ही कम कर दिया जाय, लेकिन बड़े-बड़े पुलों को पूरा करने के लिये धन दिया जाय। अगर धन की कमी पड़ती है और नेमीपुर घाट और दीबारघाट पर पक्के बड़े पुल नहीं बनाये जा सकते तो आप की सड़कों के किनारे जो शीशम के काफी पेड़ लगे हुए हैं उनको इस्तेमाल कर आप नावों का पुल ही बनवा सकते हैं ताकि लोग पैदल तो आ जा सकें। अंत में मैं माननीय मन्त्री महोदय द्वारा प्रस्तुत अनुदान का पूर्ण समर्थन करता हूं।

**श्री राजेन्द्र सिंह** (जिला हरदोई)–– माननीय अधिष्ठाता महोदय, उपस्थित कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राष्ट्र-शरीर में राजमार्ग और सड़कें, माननीय अधिष्ठाता महोदय, धमनियों का कार्य करती हैं और राष्ट्र में मांसपेशी रूपी व्यापार को परिपुष्ट भी करती हैं। लेकिन इस रूपक में माननीय अधिष्ठाता महोदय, चार रोग लग गये हैं और वह ये हैं: १––भ्रष्टाचार, २––विभाग में शिथिलता, ३––फिजूल-खर्ची और ४––अदूरदर्शी अपूर्ण योजनायें। पहले रोग के कुछ लक्षण में आप के द्वारा मंत्री जी के अवलोकनार्थ प्रस्तुत करता हूं।

सब से बड़ा रोग भ्रष्टाचार है। उसके कुछ उदाहरण मैं आप की आज्ञा से प्रस्तुत करना चाहता हूं। मुझे विश्वास है अधिष्ठाता महोदय, आप भी समझते होंगे और मंत्री जी भी जानते होंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग के ओवरसियर की मासिक आय ४,००० रुपया है। यदि किसी ओवरसियर के व्यक्तिगत खातों को देखा जाय, उसके रिश्तेदारों के व्यक्तिगत बैलेंस को देखा जाय तो यह बात प्रकट हो जायगी। इस तथ्य को समझते हुये भी माननीय मन्त्री महोदय ने इसका कोई इलाज नहीं निकाला। यह इस रोग का पहला लक्षण है।

एक बात और, जिसके लिये मैं मंत्रियों पर लांछन नहीं लगाता, मैं नहीं समझता कि यह कैसे हो गया कि जितने जिले ऐसे हैं जिनसे हमारे मंत्रिगण आते हैं, यहां पधारते हैं, उन जिलों में सड़कों का निर्माण-कार्य कुछ विशेष हुआ है और ऐसे जिले जिनसे मंत्री महोदय कम आते हैं हैं उनमें कम हुआ है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं लांछन नहीं लगाता, लेकिन जो पुस्तिका हम लोगों को दी गयी है, यदि उसके नक्शे का हम लोग अवलोकन करें तो यह बात स्पष्ट हो जाती है।

दूसरा लक्षण सुनिये। वह तीर्थ स्थान जो ऐसे क्षेत्रों में पड़ते हैं जहां से मंत्री महोदय पधारते हैं,उनकी विशेष मरम्मत यह विभाग करता है। देखिये मणिकर्णिका घाट और काशी के अन्य घाट बराबर मरम्मत होते जा रहे हैं और मेरे क्षेत्र का हत्याहरण तीर्थ, जो सारे तीर्थों में

[श्री राजेन्द्र सिंह]

प्रमुख माना जाता है, उस पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता। यह बनारस में इसलिये होता है कि वहां से कई मंत्री प्रान्त में और केन्द्र में पधारते हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, हरदोई जिले में स्वतंत्रता के पश्चात् केवल ५४ मील सड़क बनी है। ११ वर्ष में ५४ मील! एक वर्ष में ५ मील सड़क का औसत पड़ता है। माननीय मन्त्री जी बतायें कि कहां तक सुन्दर प्रगति है। मैंने राष्ट्र शरीर के प्रथम रोग के यह कुछ लक्षण बताये।

अब दूसरे रोग के लक्षण प्रस्तुत करता हूं। विभाग में शिथिलता, इसके लक्षण सुनिये। माननीय मन्त्री जी ने जो पुस्तिका प्रकाशित की है उसके "ख" पृष्ठ पर लिखा है "इससे स्पष्ट है कि सड़कों का विकास देश के आर्थिक विकास को देखते हुये बहुत पीछे हैं"। उन्होंने स्वयं इस बात को मान लिया है, यह मुझे खुशी है। इसके आगे पृष्ठ ११ पर लिखा है "इन कार्यों में पहले दो सालों में प्रगति कम रही, क्योंकि काम को प्रारम्भ करने के पहले बहुत समय आगणनों को तैयार करने और स्वीकृति में लग गया।" यानी एस्टीमेट्स तैयार करने में समय लग गया। माननीय मन्त्री जी जान नहीं पाये। सारी प्रगति समाप्त हो रही है और यह आप की पुस्तक स्वयं कह रही है। मैं आप के द्वारा कहना चाहता हूं कि उन्होंने पुस्तिका प्रकाशित कर के जो सही तथ्य हम लोगों के सामने प्रस्तुत किये उसके लिये वे धन्यवाद के पात्र हैं। लेकिन उनको चाहिये कि इनको दूर करने की भी कोशिश करें। फिर आगे लिखा है "भारतवर्ष में निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक होने की आशा है"। यानी केवल आशा है और वह भी संतोषजनक। माननीय अधिष्ठाता महोदय, १९५७–५८ में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई, यह नक्शों को देखने से प्रतीत होता है।

अधिष्ठाता महोदय, आज शहरों की ओर ही ध्यान दिया जा रहा है लेकिन देहातों की ओर उपेक्षा की जा रही है। आप विधान सभा के सिलसिले में अक्सर लखनऊ आया करते हैं इसलिये आप लखनऊ में ही देख सकते हैं कि यहां पर हर साल एक न एक सड़क बन जाया करती है, लेकिन देहातों की ओर ध्यान नहीं जाता है, और कुछ ऐसे भी कार्य होते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं है, उसकी चर्चा में तीसरे रोग के लक्षण में करूंगा। आपको याद होगा कि माननीय मन्त्री जी ने इसी सदन में सन् १९४७ में वायदा किया था कि हाथरस और जलेसर की सड़क अवश्य बन जायगी। जलेसर और हाथरस दोनों प्रमुख व्यापार मंडियां हैं। मन्त्री जी ने १९४७ में आश्वासन दिया था और आश्वासन समिति ने भी पूछा, लेकिन मन्त्री जी को ध्यान नहीं रहता। उनको चाहिये कि वे अपने वायदे को स्मरण करें और जिनके लिये प्राविज़न कर चुके हैं उनको पूरा करें और अगर प्राविज़न न किया हो तो प्राविज़न करें। मेरे क्षेत्र की एक सड़क भड़ावन –संडीला है उसके लिये मैंने प्रार्थना की थी, लेकिन यह कह दिया जाता है कि धनाभाव है। मैं कहना चाहता हूं कि जो आवश्यक सड़कें हैं, राज मार्ग या जो अन्य सड़कें आपकी दृष्टि में हैं उनके लिये आप अनुदान मांगते क्यों नहीं। केवल यह कह देना कि धन नहीं है कार्यशिथिलता का उदाहरण है।

अब तीसरा रोग फिज़ूल खर्चों का आप के सामने रखता हूं। यहां लखनऊ में १४ लाख का संग्रहालय (अजायबघर) बना है। इसकी क्या जरूरत थी जब कि हाई कोर्ट के सामने पहले से ही इमारत मौजूद थी? इसके अतिरिक्त एक ११ लाख का शहीद स्मारक बना दिया गया गोमती के तट पर, न मालूम किस शहीद का स्मारक है? तो यह ११ लाख रुपया फिजूल खर्च करने की क्या आवश्यकता थी। इस ११ लाख रुपये को अगर देहात में खर्च कर दिया जाता तो उससे जनता को फायदा पहुंच सकता था। इसके अलावा दो लाख रुपये का एक प्रगति संग्रहालय बना दिया गया, मैं पूछता हूं कि उसकी क्या आवश्यकता थी? चूंकि समय कम रह गया है इसलिये मैं कुछ सुझाव आप के द्वारा रखना चाहता हूं।

पहला सुझाव यह है कि ठेकेदारों को ठेके न दिये जांय। ओवरसियर की बेइमानी की इनकम को कम करने के लिये और इसके लिये एक मार्ग निर्माण सेना तैयार की जाय। आज

बहुत से लोग शहर और देहात में बेकार हैं उनकी बेकारी को दूर करने के लिये यह आवश्यक है कि इस प्रदेश में एक मार्ग निर्माण सेना तैयार की जाय जो कि सड़कों का निर्माण करे। इससे दो उद्देश्य पूरे होंगे, एक तो उनकी बेकारी दूर हो जायगी और सड़कें भी बन जांयगी। दूसरा सुझाव यह है कि नागपुर योजना, जो प्रथम पृष्ठ पर दी हुई है, उसको पूरा करने का प्रयत्न किया जाय और यदि उसके लिये रुपये की कमी हो तो प्रदेश से या केन्द्र से अनुदान की मांग की जाय। एक मेरा सुझाव यह है कि श्रमदान से जो सड़कें बनाई जाती हैं वे दो, तीन बरसात के बाद समाप्त हो जाती हैं इसलिये ऐसी सभी सड़कों को यह विभाग अपने पास ले ले, नहीं तो श्रमदान की बनी हुई सभी सड़कें खत्म हो जांयगी। इससे श्रमदान को भी प्रोत्साहन मिलेगा।

पांचवां मेरा सुझाव है कि तीर्थ-स्थान किसी न किसी राज मार्ग या अन्य सड़कों से मिला दिये जावें जिससे हमें अधिक से अधिक आमदनी हो। फिजूल खर्ची के रोग में इस विभाग के सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर्स को समाप्त कर देने से काफी बचत होगी। वे चीफ इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के बीच में केवल डाकिये का काम करने के सिवाय और कोई काम नहीं करते हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह एक कुशल वैद्य हो कर इस राष्ट्रीय शरीर की रक्षा करें।

*श्री रामेश्वरप्रसाद (जिला रायबरेली)––अधिष्ठाता महोदय, इसमें सन्देह नहीं है कि प्रस्तुत अनुदान का चारों ओर से स्वागत हो रहा है और उस की अहमियत में मैं भी अपनी राय मिलाता हूं। यह प्रत्यक्ष है कि इस बजट के द्वारा प्रदेश में जो काम होंगे उनसे राष्ट्र-निर्माण में काफ़ी सहारा मिलता है। इस बजट में कमी सभी सदस्यों को और मैं समझता हूं कि हमारी सरकार को भी खटकती है, लेकिन इसी जगह पर एक बात साफ कर लेनी चाहिये। अभी कई माननीय सदस्यों के भाषणों से कुछ ऐसा प्रतीत हुआ कि सरकार ने जानबूझ कर इस मद में कमी की है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब बनी तो प्लानिंग कमीशन ने जितने रुपये के लिये कहा था उतना देने में बाद में अपने को असमर्थ पाया और हमारे प्रदेश में ही नहीं बल्कि सारे देश में योजनाओं में कमी करने का आदेश हुआ। उसके तहत में इस विभाग को और मन्त्री जी को मजबूरन अपने रखे हुए लक्ष्य के रुपये में कमी करनी पड़ी। साथ ही हम यह मांग भी जरूर करना चाहते हैं कि केन्द्रीय सरकार जब कभी ऐसे आदेश दे तो हमें कोई शक नहीं होना चाहिये क्योंकि जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी कहा है, देश के तमाम सड़क के विषय को जानने वाले विशेषज्ञों की राय है कि सड़क बनाना सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिये। इस बात का खयाल करते हुये केन्द्रीय सरकार को हमें विशेष मदद देनी चाहिये। वैसे तो, जहां तक सड़कों के बनाने की बात है, हम सभी इस बात को महसूस करते हैं कि जिस प्रगति से सड़कें बन रही हैं वह कम है। पहले नागपुर योजना के तरीके पर सड़कें बन रही थीं, लेकिन उसके बाद भारतीय अभियंता परिषद् ने ग़ौर करके एक लक्ष्य निर्धारित किया है और कहा है कि २० साल में इस प्रकार से देश में और प्रदेश में सड़कें बननी चाहियें कि विकसित क्षेत्रों में प्रत्यक गांव १.५ मील की दूरी पर हो और अर्ध-विकसित क्षेत्रों में प्रत्येक गांव ३.५ मील की दूरी पर हो। इस हिसाब से हमारे प्रदेश की पक्की सड़कों की जरूरत ५८,८७० मील की है और कच्ची सड़कों की जरूरत ३२,९०० मील की है। यह लक्ष्य हमें २० साल में पूरा करना है। तब जा कर हम इस योग्य होंगे कि हम जनता से पूरे तौर से यह कह सकेंगे कि हम उसे लक्ष्य के अनुसार सुविधा दे रहे हैं। साथ ही साथ अपने सीमित साधनों में इस विभाग ने जिस तेजी और स्फूर्ति के साथ कार्य किया है और कर रहा है और अपने लक्ष्य को पूरा करने की तरफ बढ़ रहा है, वह सराहनीय है।

कुछ साथियों ने, जैसे कुंवर श्रीपालसिंह जी और देवनारायण जी भारतीय हैं, यह कहा कि पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा बनी सड़कों में कहीं भी दबे या पिछड़े इलाकों का स्थान नहीं है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामेश्वरप्रसाद]

और गांव में रहने वाली जनता के सुख का कोई ध्यान नहीं रखा गया है।* यदि हम इस दृष्टिकोण के बिना कि कौन किस पार्टी का है देखने का प्रयत्न करें तो मालूम होगा कि जितने भी प्रदेश में सड़क बनने के कार्य हो रहे हैं वे वास्तव में गांव की तरफ ही तो हो रहे हैं। शहरों की सड़कें तो म्युनिसिपैलिटी बनाती हैं और उन्हें लोकल सैल्फ गवर्नमेंट विभाग की ओर से ग्रान्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि लखनऊ के अमीनाबाद में कोई पुल बने पुल नाव के हों या जैसे भी हों, सभी देहाती जनता के लिये बनते हैं और सड़कें भी वहां बनती हैं। भारतीय जी शाहजहांपुर से आते हैं। उन्होंने कहा कि इस विभाग में समाजवादी व्यवस्था की ओर कोई तवज्जह नहीं है। मैं तो कहता हूं कि अगर बारीकी से देखें तो समाजवाद की ओर काफ़ी रुझान इस विभाग का है। आखिर जितने पुल, पुलिया, सड़कें, भवन इत्यादि बनत हैं, चाहे वे थानेदार के लिये बनें, स्टेडियम बने या प्रदर्शनी गृह बने, सभी तो जनता के प्रयोग के लिये हैं। श्रमिकों की बस्तियां, चीनी मिलों के क्षेत्र में क्वार्टर्स और वहां की सड़कें क्या उस गन्ना लाने वाले किसान के लिये नहीं बनती हैं? इस प्रकार बेकारों को भी इस विभाग द्वारा जीविका मिलती है। क्या यह उस समाजवादी नक्शे की पूर्ति नहीं करता है जिसका कांग्रेस सरकार ने वायदा किया है? जब भारतीय जी जैसे पढ़े-लिखे और सुलझे हुये व्यक्ति ऐसी बात कहते हैं तो मुझे तकलीफ होती है। जितने भी इस विभाग के सीमित साधन हैं उनमें और दूसरी कठिनाइयों में रहते हुये इस विभाग को काम करना पड़ता है।

कुछ मित्रों ने कहा कि अनुमान शुरू में कुछ और थे और बनाने के बाद और हो गये, यानी बढ़ गय ऐसा उनका मतलब था। इनकी इच्छा की पूर्ति तो शायद भगवान ही कर सकता है। मनुष्य के बनाये हुये अनुमान के अनुसार पूरा होते-होते मजदूरी और चीजों की क़ीमतें बढ़ गईं तो खर्चा भी बढ़ना लाजिमी है। इस फल्कचुएशन का असर पड़े बिना रह नहीं सकता। इसलिये जो आलोचना है वह केवल आलोचना की दृष्टि से न करके बल्कि जिससे मंत्री जी को बल मिले और जिस छिपी आवाज़ से पूरा सदन उनका समर्थन कर रहा है उसका स्पष्ट तौर से समर्थन करना चाहिये। मैं समझता हूं जहां तक भ्रष्टाचार का सवाल है माननीय राजेन्द्रसिंह जी ने कहा कि एक एक ओवरसियर ४ हजार रुपया महीना कमाता है। जबान तो मेरी रुकी नहीं है मैं १६ हजार भी कह सकता हूं, लेकिन बात ऐसी कहनी चाहिये जो किसी हद तक ठीक तो हो। मैं कहता हूं कि उसका इलाज भी क्या है? उसका इलाज तो हम को और राजेन्द्रसिंह को ही करना होगा यहां बैठ कर गालियां देने से काम नहीं चल सकता।

**श्री रघुवीरराम** ( जिला गाजीपुर )—अधिष्ठाता महोदय, माननीय कुंवर श्रीपाल सिंह जी की तरफ से जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। आज सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुदान पेश है। माननीय सदस्यों ने इस सम्बन्ध में बहुत सी बातें कहीं। उत्तर प्रदेश के पूर्वी जिले बाढ़ से प्रति वर्ष तबाह होते जा रहे हैं। जब बाढ़ आ जाती है तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना और मुलाकात करना मुश्किल हो जाता है। नदियों पर पुल न होने से यातायात बिलकुल बंद हो जाता है। आजमगढ़ जिले में मऊ के पास टोंस नदी का पुल वर्षों से टूटा पड़ा है, लेकिन अभी तक वह नहीं बनाया गया। इसी प्रकार से दोहरीघाट में भी है। इसी प्रकार से गाजीपुर जिले में गंगा नदी पर पक्का पुल बनाये जाने के लिये वर्षों से मांग की जा रही है, लेकिन मंत्री जी ने कोई ध्यान अभी तक नहीं दिया। मोहम्मदाबाद से एक सड़क हाटा को जाती है, उसका पुल बर्षों से टूटा पड़ा है, लेकिन नहीं बन पाया। इसी प्रकार से ईशूपुर से कासमाबाद होती हुई मऊ तक जाने वाली सड़क को मंत्री जी ने १९५७–५८ में मंजूर किया था, लेकिन अभी तक नहीं बनी। कासमाबाद से बहादुरगंज के बीच में जो नदी भैंसई है उस पर भी पुल बनाने की आवश्यकता है। हमारे जिले में बरसात के दिनों में कर्मचारी भी जनता की देख-रेख बाढ़ के कारण नहीं कर पाते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से मांग करूंगा कि वे इन पुल और सड़कों की तरफ ध्यान दें। टेस्ट वर्क्स के द्वारा कच्ची सड़कें बनायी जाती हैं, लेकिन

उनका पैसा अपव्यय हो जाता है, क्योंकि बरसात के महीनों में वहां की मिट्टी धुल जाती है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जिन सड़कों को पक्की करने की योजना हो उन्हीं पर मिट्टी डाली जाया करे वर्ना नहीं डाली जाय। बरसात के महीने में उन सड़कों की मिट्टी बिलकुल धुल जाती है और वे सड़कें नाले की तरह हो जाती हैं तथा जगह-जगह टूट भी जाती हैं। इस-लिये मैं आप के द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उन सड़कों पर मिट्टी पड़े जिन सड़कों को पक्की बनाना है। टेस्ट वर्क पर जो मजदूर काम करते हैं उनकी मजदूरी की दर बहुत कम रखी गई है। वे चाहे ३, ४ या ५ फर्लांग की दूरी से मिट्टी काट कर ले जायं लेकिन उनको मजदूरी वही ८ आने, ९ आने के हिसाब से दी जाती है।

मान्यवर, इन सड़कों के ऊपर जो गाड़ियां, इक्के, तांगे या रिक्शे चलते हैं, उन पर भी टैक्स लगाया जाता है। मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि इन पर से टैक्स हटाया जाय। सरकार द्वारा जो पुल बनवाये गये हैं उन पर टौल टैक्स भी लगाया जाता है। तो अधिष्ठाता महोदय, आप के द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से नम्र निवेदन करूंगा और उनके सामने इस चीज को रखूंगा कि उस टौल टैक्स को खत्म किया जाय।

गाजीपुर जिले की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान ११ वर्ष के अन्दर नहीं गया है तो मैं आपके द्वारा यह अनुरोध करूंगा कि वे उन सड़कों और पुलों के ऊपर कृपा कर के ध्यान दें और देखें कि उस जिले की जनता को यातायात के लिये कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो पदयात्रा कर के अपने मुकदमें की पैरवी नहीं कर पाते हैं और वक्त पर गाजीपुर न पहुंचने की वजह से उनके मुकदमें खारिज हो जाया करते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे जिले में जब कोई ऐसी विपदा आती है, कोई ऐसा समय आता है और जिले के उच्चाधिकारियों से मिला जाता है तो वे यह कहते हैं कि आप के यहां पहुंचने के लिये तो कोई रास्ता ही नहीं है, हम कैसे वहां चलें, हमारी गाड़ी वहां नहीं जा सकती है, इसके लिये कोई साधन नहीं है। तो मैं आप के द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं कि इन सड़कों और पुलों पर आप ध्यान नहीं देते हैं तो जैसे आप ने १२ वर्ष के जनतंत्र के अन्दर भी गाजीपुर में कोई सार्वजनिक काम नहीं किया है और न अब कर रहे हैं तो वहां की जनता सरकार से क्षुब्ध होती जाती है।

**एक सदस्य**––इसकी फिक्र आपको क्यों हो रही है ?

**श्री रघुवीरराम**––फिक्र मुझे क्यों हो, वह तो आपको होनी चाहिये। आप तो सत्तारूढ़ दल के हैं, आपके भाषण को मैंने एक रोज सुना.....

**श्री अधिष्ठाता**––माननीय सदस्य "आप" के स्थान पर माननीय मंत्री जी या सरकार कहें। यहां "आप" शब्द से चेयर का ही बोध होता है।

**श्री रघुवीरराम**––श्रीमन्, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से यह बार-बार अनु-रोध करता हूं कि टेस्ट वर्क के मजदूरों की मजदूरी बढ़ायें, जहां नदियों पर पुल नहीं हैं उन पर पुल बनवाने की ओर ध्यान दें और जिन सड़कों पर मिट्टी फेंकी जाती है और बरसात में धुल जाती है, उन सड़कों को पक्का बनवाने की तरफ ध्यान दें।

**श्रीमती विद्यावती वाजपेयी** (जिला हरदोई)––अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं। हमारे देश में राष्ट्र निर्माण के लिये यह बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। सड़कें सिर्फ यातायात का ही साधन नहीं हैं बल्कि उनसे हमारी आर्थिक समस्या भी बहुत कुछ हल होती है और हमारे देश में १०, ११ सालों में बहुत कुछ उन्नति भी हुई है। १०, ११ साल पहले हरदोई जिले को देखते हुए आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि हमने बहुत कुछ प्रगति इस ओर की है।

[श्रीमती विद्यावती वाजपेयी]

सार्वजनिक निर्माण के सम्बन्ध में जो यह हमें पुस्तिका मिली है इसमें हम देखते हैं कि बड़े-बड़े नाले, पुल और सड़कें बनायी गयी हैं। यद्यपि बहुत धीमी प्रगति है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छी और काफी है।

इस पुस्तिका के प्रारम्भ में लिखा हुआ है उसे मैं जो आपकी आज्ञा से पढ़ देना चाहती हूं। अगर इस तरह अधिक कार्य हो जाय तो हमारे देश का बहुत कुछ सुधार बहुत जल्दी हो जाय—"सड़क प्रणाली में इस प्रकार हमारा लक्ष्य होना चाहिये कि सुदूर स्थित गांव ही नहीं वरन् प्रत्येक घर व झोपड़ी भी सड़क की पहुंच में आ जाय"। इस तरफ मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि हम शहरों की उन्नति में तो बहुत कुछ कर चुके हैं, लेकिन अभी देहात तक हमारी यह योजना बहुत कम पहुंची है। गांवों की हालत सुधारने के लिये जब तक हम कम से कम बड़े-बड़े गांव, कस्बे व तहसीलों को सड़कों द्वारा नहीं मिलायेंगे तब तक उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी होना मुश्किल होगी। जितनी पैदावार होती है वह उनको गांव के बाहर ले जानी पड़ती है। शिक्षा के लिये भी लड़कों को गांव से तहसीलों में या कस्बों में जाना पड़ता है। विद्यार्थी सड़कें न होने के कारण बड़ी परेशानी में पड़ते हैं। ४–५ महीने जब बाढ़ें आती हैं तो एक गांव से दूसरे गांव में जाना बिलकुल नामुमकिन हो जाता है। इसलिये इस योजना को यदि धीरे-धीरे गांव की ओर अधिक ले जाया जाय तो इससे जो हमारी सरकार का ध्येय है कि गांवों का विकास हो उसमें ज्यादा उन्नति होगी।

अस्पताल सब कस्बों में हैं। मरीज बहुत से ऐसे होते हैं कि जब तक शहर तक पहुंचते हैं रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, तो इसलिये गांव की तरफ अधिक ध्यान दना चाहिये। मैंने माननीय मंत्री जी का अपने क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाया था उसी को कहने के लिये इस समय मैं खड़ी हुई हूं।

मेरे क्षेत्र में थोड़ी-सी सड़कें हैं जो बहुत छोटी हैं, बहुत लम्बी नहीं हैं और उनके लिये मैंने कई दफा कहा कि उन्हें ले लिया जाय, लेकिन वही धन की कमी के कारण वे सड़कें अभी तक बन नहीं सकीं और पता नहीं कितने दिनों में बन पायेंगी। इन सड़कों के लिये मैं इसलिये प्रार्थना करना चाहती हूं कि मेरे क्षेत्र शाहाबाद में २०–२१ गांव ऐसे हैं जहां बाढ़ के कारण हम जाना चाहें तो हमारा पहुंचना नामुमकिन हो जाता है और किसी तरह की चीज हम वहां नहीं ले जा सकते। न पुल हैं, न सड़कें हैं। यह छोटी-छोटी सड़कें हैं। बहुत धन भी खर्च नहीं होना है, थोड़े में ही वे बन जायंगी। एक सड़क छूट गई शाहाबाद से पाली तक। इसलिये मैं उनसे निवेदन करना चाहती हूं कि शाहाबाद से शिरोमणि नगर ४, ५ मील की सड़क है दूसरी शाहाबाद से पिहानी और एक शाहाबाद से वासित नगर की सड़कें हैं जो जरूरी हैं, जिनके न होने से जनता को बहुत परेशानियां होती हैं। मेरे पास कई दफा लोग आये हैं, दस्तखत करा के प्रार्थना-पत्र दिये हैं और मैं समझती हूं कि मंत्री जी इस साल की योजना में इनको अवश्य रखने का प्रयत्न करेंगे।

इसके अलावा मैं स्कूलों के बारे में भी कहना चाहती हूं। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड द्वारा जो स्कूल बनते हैं उनमें कहीं बच्चों के बैठने तक का प्रबन्ध नहीं है। यों तो बड़े-बड़े शहरों में बड़े-बड़े कालेजेज और स्कूल बनते हैं और बनाये गये हैं, लेकिन देहात में अभी सारे स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड पर ही निर्भर करते हैं और स्कूलों की समस्या वहां की हल नहीं है। इमारतें इतनी खराब हैं कि किसी की छत फटी है, किसी की दीवार में दरार है। तो अगर बड़ी-बड़ी योजनाओं को कम कर के इन छोटी-छोटी चीजों पर, गांवों की ओर ध्यान दिया जाय तो अच्छा होगा, क्योंकि हमारे देश में गांवों की संख्या शहरों से हजारों गुनी है। विकास के लिये भी सब से ज्यादा आवश्यक यह है कि गांवों में सड़कें बनायी जायं और गांव से गांव को और गांव से कस्बे को मिला दिया जाय, जिससे गांव वालों की समस्यायें हल हो सकें,

वे जो कुछ पैदा करें, कुटीर उद्योग खोलना चाहें, अपना सामान लाना, ले जाना या बेचना चाहें उसमें सुविधा प्राप्त हो। इस तरह से इन गांवों की सड़कों का बनना आवश्यक है ।

सड़कों के अनुदान में पिछले साल कटौती की गई। मैं इसका वास्तव में विरोध करती हूं, क्योंकि यह कटौती इस अनुदान में नहीं होनी चाहिये । यह बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है और इसी से हमारे राष्ट्र निर्माण का बहुत भारी काम होता है और असर पड़ता है । पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसी पुस्तिका में लिखा हुआ है और वे इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें उच्चतम प्राथमिकता सड़कों को देनी चाहिये । तो यदि प्रधान मंत्री तक का यह विचार है तो फिर पता नहीं अनुदान में कटौती किस तरह से की गई, किस कारण से की गई, यह विचारणीय प्रश्न है। मैं आशा करती हूं कि इस अनुदान में कटौती न करके इसमें और ज्यादा रुपया देकर हमारी सरकार इस ओर अधिक ध्यान देगी ।

**श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—अधिष्ठाता महोदय, जो कटौती का प्रस्ताव माननीय कुंवर श्रीपालसिंह जी ने पेश किया है मैं उसका समर्थन करता हूं । मान्यवर, यह निर्विवाद बात है कि यातायात के साधन देश और प्रदेश में जितने बढ़ते जायंगे उतना ही अधिक विकास का काम और देश की तरक्की बराबर होती चली जायगी । विकास की जो योजना है उससे इसका कोई सम्बन्ध खासतौर से नहीं जोड़ा जा रहा है । विकास के कामों के लिये जिन खास चीजों की क्षेत्रों में जरूरत पड़ती है, यातायात के साधन ठीक तरीके से उपलब्ध न होने के कारण वह चीजें वहां पर नहीं पहुंचाई जा सकतीं और विकास का काम बहुत पीछे रह जाता है । इस प्रदेश के वह इलाके जहां पर विकास की जरूरत है, जो बहुत पिछड़े हुए हैं, उन इलाकों में अगर यातायात के साधन उत्पन्न न किये गये तो वहां पर एन० ई० एस० ब्लाक या ऐसे अन्य ब्लाक खोलकर जो तरक्की के साधन हैं वह नहीं पहुंच पाएंगे । उन इलाकों की कोई तरक्की नहीं हो पाएगी । इसलिये इस बात की सख्त जरूरत है और मैं आपके जरिये से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि सूबे के उन पिछड़े हुए इलाकों की तरफ खासतौर से ध्यान दें जहां पर पक्की सड़क तो क्या कच्ची सड़क भी नहीं है ।

मान्यवर, अभी हाल में पिछले दिसम्बर में हमारे माननीय उपमंत्री महोदय मेरे जिले फर्रुखाबाद में मेरे क्षेत्र में गये थे । जब से यह सरकार कायम हुई तब से आज तक उस इलाके में जहां माननीय मंत्री महोदय गये थे कोई भी मंत्री वहां पर पहुंचा नहीं था। उन्होंने इस बात को महसूस किया होगा कि वह इलाका कितना ऊबड़-खाबड़ है । जिस वक्त माननीय मंत्री जी गये थे तब तो पहुंचना सरल था, लेकिन बरसात में पहुंचना होता तो शायद उनकी मोटर तिरवा से आगे न पहुंच सकी होती । मंत्री जी से मैं उम्मीद करूंगा कि जो बहुत पिछड़ा हुआ इलाका है, जहां पर १२ मील आस-पास कोई सड़क नहीं दिखाई पड़ती है, वहां की जनता ने उनसे विशेष आशा की है कि वह इस संबंध में ऐसी योजना बनायेंगे, ऐसा कोई बजट में पैसा मंजूर करेंगे कि उस इलाके में जहां पर वह गये थे कोई सड़क बन सके और वहां के रहने वालों को राहत मिल सके ।

मान्यवर, मैं आपके द्वारा मंत्री जी से यह भी कहना चाहता हूं कि जो सड़कें या जो रास्ते योजनाओं के अन्दर लिये जाते हैं और फिर जब कोई दूसरी जगह के लिये दबाव पड़ता है मंत्री जी के ऊपर तो उन जगहों को ले लिया जाता है और जहां जरूरत थी उनको छोड़ दिया जाता है, किन्हीं खास व्यक्तियों के कहने पर, यह नहीं होना चाहिए। मान्यवर, छिबरामऊ-तालग्राम, तिरवा-ठठिया-मखनपुर ऐसा रास्ता है जो फर्रुखाबाद जिले में बहुत पुराना रास्ता है । कई टाउन एरियाज हैं और कई बड़े-बड़े बाजार लगते हैं । इस रास्ते पर पुल बिगड़ रहे हैं । पुल बीच में खड़ा हुआ है, उसके आस-पास बड़े-बड़े कटाव हो गये

[श्री होरीलाल यादव]

हैं और जो पुल हैं उनके भी गिरने का खतरा है। मैं आपके जरिये मंत्री महोदय से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात की तरफ ध्यान दें कि अगर उस सड़क को पक्का न करा सकें तो कम से कम इस लायक तो बना दें ताकि उन पुलों की रक्षा तो हो सके और वह बरसात में न गिर सकें। नया पुल तो उस इलाके में बनना मुश्किल है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में उसी सड़क के एक टुकड़े पर बहुत पैसा खर्च करके मिट्टी डाली गई। वह बह गई और सारा पैसा बरबाद हो गया। अब वहां पर ऐसा हो सकता है कि मंत्री जी अगर कुछ थोड़ा सा पैसा मंजूर कर दें तो जो चार-छः मील पर मिट्टी डाली गई वह रास्ता पक्का कर दिया जाय। इससे बहुत बड़ी राहत उस इलाके को मिल सकती है और वहां की जनता को अपने कच्चे माल को भेजने में सहूलियत हो सकती है और रक्षा का भी साधन हो सकता है। मैं एक बात यह भी कहूंगा कि इस विभाग में जो ठेकेदारी का तरीका है उस तरीके से भी काम के होने में बहुत बड़ी देर होती है। मिसाल के तौर पर मैं कहूंगा कि पिछले साल फर्रुखाबाद जिले में फर्रुखाबाद–घटिया घाट सड़क और कायमगंज–कम्पिल सड़क बनना चाहिये थी, लेकिन उनके बनाने में ठेकेदारों ने इतनी देर की कि काम ठीक समय पर नहीं हुआ और आज भी काम अधूरा पड़ा हुआ है। फर्रुखाबाद–घटियाघाट रोड पर तो अभी काम भी शुरू नहीं हो सका है। अगर इसी काम को विभाग अपने इंतजाम से, अपना लेबर लगा कर और अपना पैसा लगा कर करे तो काम भी अच्छा होगा और मजदूरों को जो तकलीफ ठेकेदारों के द्वारा पैसा वक्त पर न देने से होती है वह भी न होगी और वह लोग जो सामान कम इस्तेमाल करते हैं वह दिक्कत भी न होगी। ओवरसियर को जो दस परसेंट चला जाता है वह भी बचेगा। यदि इस तरह से ठेकेदारी सिस्टम को खत्म करके विभाग अपने द्वारा ही काम कराये तो काम जल्दी हो सकता है और अच्छा हो सकता है।

मैं निवेदन करूंगा कि अगर मंत्री जी विभाग में जो दस, ग्यारह प्रतिशत की कटौती चलती है, जो ठेकेदार को देनी पड़ती है, अगर उसको बचाने का कोई रास्ता निकाल लें तो कम से कम ६–७ करोड़ के बजट में ६–७ लाख रुपया तो बच ही सकता है, जिससे ५,६ मील की पक्की सड़क बड़ी आसानी से हर साल सूबे में बन सकती है। इसके अलावा बहुत सा पैसा जो कि ठीक तरह से समय के अन्दर इस्तेमाल नहीं हो पाता वह सब काम में आ सकता है। साल के अन्तिम मास मार्च में, आखिरी दिनों में जो खर्च निकलता है वह शायद साल के दूसरे महीनों के औसत से अधिक होता है, इससे नुकसान यह होता है कि काम ठीक से नहीं हो पाता और यही ध्यान रखा जाता है कि किसी तरह से पैसा खर्च हो जाय ताकि कहने को हो जाय कि जो रुपया विभाग को दिया गया था वह खर्च हो गया, लेकिन इस तरह से काम सुन्दर और टिकाऊ नहीं हो पाता और बहुत दिनों तक नहीं कायम रह पाता। इसके अलावा जो सड़कें बनें उनकी देखभाल का काम भी मुस्तैदी से होना चाहिये। जिस वक्त कि सड़कों की कुटाई होती है और उन पर कंकड़ पड़ता है तो कंकड़ बहुत ही कम और खराब क्वालिटी का डाला जाता है और नतीजा यह होता है कि कुछ दिनों के बाद ही सड़क अपनी पहली हालत में आ जाती है। मिसाल के तौर पर मैं बताऊं कि कानपुर जिले की अरौल–मनकपुर सड़क बनी है, उसको बने ३ मास ही हुये हैं, लेकिन अगर माननीय मंत्री जी वहां जायं और देखें तो सड़क की वही हालत हो गई है जो ३ मास बनने से पहले थी, गड्ढे पड़ गये हैं और कंकड़ धूल बनकर उड़ने लगे हैं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि जो आश्वासन मंत्री जी ने दिये थे उनको वह पूरा करने की कोशिश करें और जनता की आशाओं को पूरा करने की कोशिश करें। इन शब्दों के साथ मैं इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

**श्री रामप्रसाद नौटियाल** (जिला गढ़वाल)---माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जब आज के वैज्ञानिक युग में बर्षों और महीनों का रास्ता घंटों में तय होने

लगा है और घंटों का मार्ग मिनटों में तय होने लगा है; तब भी हम पर्वतीय लोग आज भेड़ों और बकरियों पर ही सामान लादकर चलते हैं। आप कहेंगे कि बहुत से काम तो गढ़वाल में भी हुये हैं और पर्वतीय इलाके में भी हुये हैं। इसमें शक नहीं कि बजट को देखते हुए यह विदित होता है कि बहुत सी सड़कों का निर्माण गढ़वाल में भी हुआ है और प्रदेश के दूसरे जिलों में भी हुआ है, लेकिन खास करके मुझे गढ़वाल की तरफ आपके द्वारा माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना है। कोटद्वार से बदरीनाथ की जो रोड है वह आमतौर से सारे भारत की रोड है और इसमें समस्त देश के ही यात्री आते जाते हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है कि जहां बद्री का श्रम जैसे आश्रम से हमारे जिलों को अनेक लाभ हो सकते थे वहां लाभ की अपेक्षा हानि होती है, क्योंकि हमारे जिले के लिए जितना भी प्रदेशीय सरकार में पी० डब्ल्यू० डी० का बजट होता है वह इसी मोटर मार्ग पर खर्च कर दिया जाता है जो हरद्वार से बदरीनाथ या कोटद्वार से बदरीनाथ को जाती है। इसी पर पुल और झूले भी बनते हैं और विभाग के अफसर, मंत्री, उपमंत्री, पार्लियामेंटरी सेक्रेटरी जितने भी सरकारी लोग हैं ये सब दौरा यहां का ही किया करते हैं और इसलिए जिले के एग्जिक्यूटिव इंजीनियर और दूसरे स्टाफ को भी इसी सड़क का ध्यान रखना पड़ता है और जिले की दूसरी सड़कें चौपट रहती हैं। मेरा निवेदन है कि दूसरी सड़कों पर भी ध्यान रखें। आज के युग में जबकि संसार बहुत आगे बढ़ गया है यह एक ताज्जुब की बात होगी सुनकर कि आज भी हम ३–३, ४–४ दिन में घर नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे जैसा आदमी भी जब घर जाना चाहता है तो १०–१५ सेर सामान कंधे पर लेकर जाना होता है और बड़ी मुश्किल से तीसरे चौथे दिन घर मैं पहुंच पाता हूं, जबकि १०–१५ मील रोज चलूं। ऐसी हालत में आप हमारी कठिनाइयों का अनुमान लगा सकते हैं।

इतने बड़े प्रदेश में हमारा जिला हाथी के पेट में एक फूल डाल देने के समान है, क्योंकि इसमें बहुत से विभागों के बजट निकल चुके हैं और हमने यह देखा है कि हमको अपने विचारों के प्रकट करने का बहुत कम अवसर दिया जाता है, जबकि प्रदेश के दूसरे भू-भाग से हम लोगों की भौगोलिक स्थिति भिन्न है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम पर्वतीय लोगों को भी ऐसा मौका दिया जाय जिससे हम अपनी कठिनाइयों का वर्णन इस सदन में कर सकें।

आप विश्वास करें कि डिफेंस, यानी सुरक्षा या धार्मिक महत्व की सड़कों में से यह भरचुला से बैजरो वाली सड़क हमने बनायी है जन-सर्विस से। वहां जब डेवलपमेंट कमिश्नर श्री बैजनाथ सिंह और दूसरे अधिकारी पहुंचे तो उनका कहना यह था कि जब उन्होंने देखा कि वहां पर ३–४ हजार स्त्री, पुरुष, बच्चे काम कर रहे हैं तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि साइबेरियन रेलवे और चीन की सड़कों के निर्माण की बात इतिहास में पढ़ी थी, लेकिन यह सड़क आंखों से देखी है जो भारत के लिए एक उदाहरण होगी। परन्तु जितनी प्रगति हम चाहते थे उतनी वह सड़क में नहीं हो पायी है। धुवां कोट तक वह बन पायी है, लेकिन आगे बैजरो तक पहुंचने के लिए कोई विशेष प्राविधान नहीं है। वह एक ऐसी सड़क है जो कालांतर में कर्णप्रयाग तक जायगी।

दूसरी सड़क है दूधातोली के समीप, जिस दूधातोली पर्वत से ३ नदियां निकलती हैं, रामगंगा, पूर्वी नयार, पश्चिमी नयार उसकी तलहटी में गरैसेन बसा हुआ है। ऐटकिंसन ने लिखा है कि यह भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही सुन्दर स्थान है और यहां की जलवायु भी बहुत सुन्दर है। यह उन्होंने ऐटकिंसन गजेटीयर में लिखा है। वह लिखते हैं कि अगर यहां कुमायूं की राजधानी रखते हैं तो हमको गढ़वाली सोल्जर नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसके लिए दूधातोली का विकास करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने उठा करके वहां से

[श्री रामप्रसाद नौटियाल]

नैनीताल में कुमायूं की राजधानी को रखा है। यह बात मैं आपसे सन् १८६२ की कह रहा हूं। दूधातोली पर्वत ऐसा है जहां तांबा, लोहा, अबरख आदि बड़े बहुमूल्य पदार्थ छिपे हुये हैं। अगर वहां पर यह सड़क चली जाती है तो केवल हमको ही लाभ नहीं होगा बल्कि देश को और सरकार को भी लाभ होगा। वहां एक फलों का बगीचा बनने जा रहा है जो एशिया में सबसे बड़ा बगीचा होगा और वहां पर एक इतना बड़ा झरना है कि बरसात के दिनों में वहां ऐसा मालूम होता है कि बिजली चमकती रहती है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस सड़क का निर्माण हो जाय तो उससे जनता और सरकार दोनों को लाभ होगा। अक्सर यह होता है कि जिस सड़क पर १० लाख रुपये खर्च होते हैं वहां की जनता पर १५ लाख रुपये का भार पड़ता है, जिससे जनता को कोई लाभ नहीं हो पाता।

मुझे यही निवेदन करना है कि सरकार केवल हरद्वार से बदरीनाथ और कोटद्वार से बदरीनाथ जाने वाली सड़कों की ही देखभाल न किया करे बल्कि और सड़कों का भी खयाल रखे। पिछले बजट में मैंने देखा कि जो सड़कें रखी गयी थीं उनमें से बहुतों पर कुछ काम ही नहीं हुआ और इस साल तो उनमें से बहुत सी लापता हैं। इसके अलावा हमसे बहुत से पुल और दूसरे सुझाव मांगे गये हैं। मैं दो साल से जिले की एलाइनमेंट कमेटी का प्रेसीडेंट हूं, लेकिन मुझे दुःख है कि इस बीच एक बार भी उस कमेटी की मीटिंग एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने नहीं बुलायी। ऐसी हालत में कथनी और करनी में बड़ा अन्तर हो जाता है। मेरा निवेदन है कि हमारी कथनी और करनी में कोई भेद नहीं होना चाहिये। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कोई अफसर किसी काम को करवा रहा है और बीच में उसका तबादला हो जाता है। जो दूसरा अफसर उसकी जगह पर आता है वह उस जिम्मेदारी को समझता नहीं और बजट लैप्स हो जाता है।

दूसरी बात एक और है कि बहुत सी सड़कें जिनको हमने जन श्रम से बनाया है उनको सरकार ने अभी तक नहीं लिया है, जैसे चवनकोट से लक्ष्मणझूला सड़क, धूवांकोट-मैराणी डांडा सड़क जो धुवांकोट तक जाती है, इन सड़कों को अभी तक नहीं लिया है। इससे भी जनता में अविश्वास पैदा होता है।

इसके अलावा सरकार का यह नारा है कि हम देश में समाजवाद ला रहे हैं, श्रमिकों को उचित मजदूरी मिलेगी और श्रमिकों की समितियां बननी चाहियें। हमने उनकी समितियों का बहुत सी जगह रजिस्ट्रेशन भी करवाया है, लेकिन जब हम एक्जीक्यूटिव इंजीनियर या डी० एफ० ओ० आदि के यहां मजदूरों को भेजते हैं तो उनको यों ही टाल दिया जाता है।

(इस समय २ बज कर ३९ मिनट पर उपाध्यक्ष श्री रामनारायण त्रिपाठी पीठासीन हुये।)

*श्री तेजा सिंह (जिला मेरठ)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो अनुदान सदन के सामने उपस्थित है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। इस विभाग की तरफ से बहुत से निर्माण के कार्य होते हैं और उनमें से कई ऐसे हैं जिनके मुताल्लिक यह नहीं कहा जा सकता है कि आया वह देहाती क्षेत्रों के लिये हैं या शहरी इलाके के लिये हैं। जैसे यहां लखनऊ में मेडिकल कालेज बना है और उस पर रुपया खर्च होता है तो उसके लिये सही तौर पर यह कहना कि यह शहरी आबादी के लिये हैं या देहाती आबादी के लिये है, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें देहात से आकर विद्यार्थी पढ़ते हैं। ऐसे ही यदि किसी दरिया पर पुल बनता है तो यह निश्चय करना कि यह किस आबादी को सेवा करता है बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कई काम ऐसे हैं जिन के मुताल्लिक साफ तौर पर कहा जा सकता है कि यह शहर के लिये हैं और यह देहात के लिये हैं।

मुझे इस अनुदान में थोड़ा-सा एतराज है और मैं भी महसूस करता हूं कि इसमें ज्यादातर काम शहरी आबादी के लिये किये गये हैं। पक्की सड़कों पर करीब तीन करोड़ रुपया खर्च हो रहा है

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसमें मैं यह नहीं कहता कि मंत्री जी का दोष है । हमारा प्लानिंग दो तरह से हो सकता है--एक तो यह कि बड़े बड़े शहरों से पक्की सड़कें बनाना शुरू करें, फिर जिलों में पहुंचें, फिर तहसीलों में पहुंचें और इसके बाद गांवों में पहुंचें । इससे साफ जाहिर है कि शहरों को प्रायारिटी दे रहे हैं ।

दूसरा तरीका यह हो सकता है कि देहात के कच्चे दगड़ों को कांकरीट या कंकड़ के बनायें फिर तहसील में पहुंचें, फिर जिलों में पहुंचें और इसके बाद बड़े बड़े शहरों को लें और लखनऊ तक पहुंचें । इस समय के प्लानिंग के अनुसार हम शहरों से देहात की तरफ जा रहे हैं । मैं एक मिसाल देता हूं कि हमारे यहां मोदीनगर मिल एरिया में एक सात मील का टुकड़ा पड़ता है । मोदी, सरकार और केन्द्रीय सरकार की मदद से तीन मील का टुकड़ा तो पक्का हो गया है, लेकिन ४ मील का टुकड़ा रह गया है उसके लिये हमने मंत्री जी तथा इंजीनियरों से कहा, लेकिन कुछ नहीं हो सका और वह कहते हैं कि यह प्लान में नहीं आता है, इसलिये कुछ नहीं किया जा सकता है । मैंने देखा कि विधान भवन के सामने पक्की सड़क बन रही है जिस पर १,६०,००० रुपया खर्च हो रहा है मैं नहीं समझ सकता कि अगर यह २ साल बाद बन जाय तो क्या हर्ज है ? मैं यह नहीं कहता कि पक्की न बनाई जाय, अगर रुपया हो तो संगमरमर की बना दी जाय । हमें देखना यह है कि प्रिफ्रेन्स किसे दिया जाय ।

मेरा खयाल है कि मंत्री जी ने पदयात्रा की होगी और उनके देखने में आया होगा कि देहात के दगड़ों की हालत बहुत खराब है । हम श्रमदान करते हैं, लेकिन बहुत सी चीजें जैसे नाली तथा कल्वर्ट बनाना, इसमें पैसा खर्च होता है और देहाती लोग इन चीजों को नहीं बना सकते । श्रमदान से कुछ काम किये जाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसको खराब कर देते हैं और अपने खेतों में मिला लेते हैं । अगर पहले गांव के दगड़ों को ठीक करके फिर लखनऊ पहुंचें तो यह दोष नहीं लगाया जा सकता है कि हम देहात का खयाल नहीं कर रहे हैं और शहर वालों के लिये ही कर रहे हैं। वह अनुदान आज नहीं है कल पेश हो रहा है । उसमें भी इस चीज की झलक आती है ।

हमारी गवर्नमेंट की यह योजना है कि हमारे अधिकारियों के लिये भवन बनाये जाते हैं, जैसे विधायकों, मिनिस्टर्स, डिप्टी मिनिस्टर्स के लिये भवन बन रहे हैं, अफसरों के लिये बन रहे हैं । उसमें ४८ लाख रुपया खर्च होने जा रहा है, जिसमें से २८ लाख रुपया सिर्फ लखनऊ में ही खर्च हो रहा है और उसमें मैंने देखा कि एक पैसा भी किसी गांव में इस अनुदान से नहीं खर्च हो रहा है। या तो जिलों में भवन बन रहे हैं या तहसीलों में। मैं यहनहीं कहता कि विधायकों, मिनिस्टरों, डिप्टी मिनिस्टरों और अफसरों के लिये भवन नहीं बनने चाहिये । बनने चाहिये, लेकिन उसके साथ यह देखना चाहिये कि देहात में भी गवर्नमेंट के अधिकारी हैं--पंचायत सेक्रेटरी हैं, पतरौल हैं, लेखपाल हैं उनके रहने के लिये भी जगह होनी चाहिये । यहां तो किराये पर भी मकान मिल जाते हैं, लेकिन देहात में उन गरीबों को किराये पर भी नहीं मिल सकते । मुझे खुद अनुभव है । मेरे क्षेत्र के सेक्रेटरी अपने बाल बच्चों को साथ नहीं रख सकते जिसका असर यह होता है कि उनको किसी देहाती के घर में खाना पड़ता है और उनको कुछ न कुछ लिहाज करना पड़ता है जिससे वह अपने काम में गड़बड़ करते हैं । अगर ऐसा हो कि दो, तीन साल तक लखनऊ में भवन न बना कर देहात में अधिकारियों के लिये भवन बनायें तो मेरा खयाल है कि फिर शायद किसी को गुंजायश न रहे कहने की कि हमारा ध्यान शहर की तरफ है ।

इसी तरह से एक सड़क नूनी की बन रही है उसमें चार साल से प्राविजन हो रहा है, लेकिन अभी तक सड़क मुकम्मल नहीं हुई । गाजियाबाद से नूनी तक का फासला सिर्फ सात मील का है । कई साल तक यही नहीं तय हुआ कि वह सड़क एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट को कब जायगी । पिछले तीन साल से पी० डब्ल्यू० डी० के पास है । रुपये का प्राविजन हर साल होता है लेकिन पता नहीं क्यों मुकम्मिल नहीं हो रही है ।

[श्री तेजसिंह]

ऐसे ही इंडस्ट्रियल क्वार्टर्स का मामला है । गाजियाबाद का कुछ अजीब इतिहास है । सन् १९५४ में पहली दफा वहां लेबर क्वार्टर्स बनाने के लिये बजट में प्राविजन किया गया । ६ जगह अलग-अलग जमीन को अक्वायर करने के लिये नकशे बनाये गये । एक जगह जमीन अक्वायर करने का फैसला किया गया, लेकिन उस जमीन को एक अमीर आदमी सस्ते दामों पर यह कह कर खरीद लेता है कि तुम्हारी जमीन अक्वायर हो रही है मुझे बेच दो । वह जमीन एक अमीर आदमी खरीद लेता है । वह नक्शा रद्द कर दिया जाता है और दूसरी जगह का नक्शा बनाया जाता है । इस प्रकार चार जगहों के नक्शे बने हैं । अब भी तीन जगह की फाइल चल रही है, लेकिन, फिर भी क्वार्टर्स नहीं बन रहे हैं । पहले पांच सौ क्वार्टर्स थे अब ढाई सौ हैं, लेकिन चार साल से एक भी क्वार्टर नहीं बना है और न जमीन ही अक्वायर हो सकी है । अगर जमीन को जल्दी अक्वायर करने की व्यवस्था की जाय तो क्वार्टर बन जांय । इसी तरह से नैनी में इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाने का प्राविजन है । उसके लिये तीन साल से रुपया चल रहा है, लेकिन अभी तक यह भी तय नहीं हुआ कि वह इस्टेट कहां बने । वाराणसी और देवबन्द की इस्टेट्स अपना काम कर रही हैं, लेकिन वहां अभी जमीन के लिये भी तय नहीं हुआ है ।

**श्री उपाध्यक्ष**---आपका समय समाप्त हो गया ।

**श्री अब्दुल रऊफ लारी** (जिला गोरखपुर)---श्रीमान् उपाध्यक्ष महोदय, आज जो माननीय मंत्री जी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिये अनुदान संख्या ३३ और ३४ पेश की है उसके खिलाफ विरोधी दलों से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । श्रीमन्, यह अनुदान ऐसे महत्वपूर्ण विषय के लिये है जिस पर जितनी भी बात कही जाय वह कम है। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी ने जो कहा है वह चीज सरकार की तरफ से जो पुस्तिका बंटती है उसमें प्रस्तुत है । उन्होंने इस चीज को माना है कि सड़क का निर्माण देश की उन्नति के लिए बहुत जरूरी है । हमारी समझ में यह नहीं आता कि यह चीज केवल कागज ही तक क्यों सीमित रहती है । नागपुर की कान्फ्रेंस में कांग्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया था कि हर गांव की दूरी सड़क से नजदीक से नजदीक कर दी जायगी । आज ११ वर्ष का जमाना गुजर गया इस कांग्रेसी सरकार को राज्य करते लेकिन अब भी बहुत से गांव ऐसी जगहों पर हैं जो सड़क से बीस, बीस, पच्चीस, पच्चीस मील की दूरी पर पड़ते हैं । हमारी समझ में नहीं आता कि केवल कागज पर कह देने से ही क्या फायदा होगा ? इस सरकार की कथनी और करनी में कोई मिलाव है ही नहीं । केवल लोगों को देहात के रहने वालों को, गरीब किसानों को जिनसे वोट लेना होता है कागज के जरिये उनको आश्वासन दे दिया जाता है । रोते हुये बच्चे को जिस तरह लोला पकड़ा कर मातायें खुश कर दिया करती हैं उसी तरह हमारी सरकार देहात के रहने वालों को खुश करना चाहती है ।

श्रीमन्, आप देखें कि बजट का जो आंकड़ा हमारे सामने है उसमें ज्यादा से ज्यादा रुपया शहरी मद में खर्च होने के लिये है, देहात के लोग वैसे ही कोरे के कोरे रख दिये गये हैं । मकान निर्माण का सबसे ज्यादा रुपया आपके लखनऊ शहर में खर्च हो रहा है जो एम० एल० ए०, मिनिस्टर, डिप्टी मिनिस्टर की रिहायश पर खर्च होगा । श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार जो अपने को समाजवादी सरकार कहती है इसे यह फिक्र नहीं है कि ११ साल के इसके राज्य के बाद भी आज प्रान्त में कितने ऐसे लोग पड़े हुये हैं जिनको रात को सोने के लिये छप्पर भी नसीब नहीं होता है । पेड़ों के नीचे दिन बिताते हैं । सड़कों की पटरियों पर रात को सोते हैं । ओले में, बारिश में भीगते हैं, बीमार होते और मर जाते हैं । इनको अपनी मिनिस्ट्री के लिये भव्य भवन बनाने की फिक्र पड़ी हुई है, ऊंची-ऊंची अट्टालिका बनाने की फिक्र पड़ी हुई है । कंकड़ की सड़कों को पिच रोड बनाने की और पिच रोड को सीमेंट की बनाने की फिक्र पड़ी हुई है । सरकार की ऐसी मंशा है कि उस पर से मंत्रियों की कारें गुजरें, बाहर से लोग आकर देखें और तारीफ करें। तो यह कहां तक कल्याणकारी राज्य हो सकता है ?

हमारे प्रदेश के ८० प्रतिशत लोग जो देहातों में बसते हैं उनका कोई खयाल नहीं रखा गया है । जितने भी मकान बनने वाले हैं उन में देहात के लोगों के लिये एक भी नहीं है । जब कभी किसी पुल का हम जिक्र करते हैं तो मंत्री जी कहते हैं कि धनाभाव के कारण नहीं बन सकता, जब कि एक-एक जगह जहां पुराने डाक बंगले मौजूद थे वहां नये डाक बंगले बनाये जा रहे हैं । अंग्रेज जो भारत को गुलाम बनाये हुये थे और बाहर से आये थे जिन्हें विलासिता करने का अधिकार था वह जिन बंगलों में गुजर कर गये उनमें अब हमारे यहां के मंत्री लोग गुजर नहीं कर सकते । हमारे अधिकारी जो एक समाजवादी देश के अधिकारी हैं वह उनमें गुजर नहीं कर सकते । उनके लिये नया बंगला बन रहा है उसी जगह पर जहां पहले से बंगला मौजूद है । फर्क इतना है कि गुसल खाने, पाखाने सीमेंटेड नहीं है, मोजैक नहीं है, उसमें पांव फिसलने वाली पालिश नहीं है । उसके लिये नये डाक बंगले बन रहे हैं । उसके लिये इनके पास पैसा आ जाता है । यह सही है कि हमारे अधिकारी शहर को रिप्रिजेंट करते हैं, वह अभागे देहाती जो अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, इंजीनियर और आफिसर बना देते हैं, लेकिन जब वह पढ़ लिख कर आफिसर हो जाता है तो वह भी शहर में ही बस जाता है और भूल जाता है देहात को । मैं मानता हूं कि प्रकृति के मुताबिक वह ऐसा करता है, लेकिन मंत्री जी अपने को क्यों भुला देते हैं कि देहात से चुने हुये एम० एल० ए० से वह बने हुये हैं, और बनने के बाद फिर भूल जाते हैं देहात को । उन्हीं अधिकारियों के बनाये हुये कागजात पर दस्तखत करने को तैयार हो जाते हैं ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह कहूंगा कि वह इस रवैइये को बदलें और देहात की तरफ ध्यान दें, सिमेंन्ट की सड़क बनाना कम करें और देहात में कच्ची पक्की सड़क बनाना शुरू कर दें जहा ६ महीनें तक सड़कों के अभाव से लोग नहीं पहुंच पाते और बरसात के दिनों में कचेहरी नहीं आ सकते । मंत्री जी कचहरी की रिपोर्ट को देखें कि जिसमें चपरासी यह कहता है कि पानी भरा होने की वजह से फलां गांव में नहीं जा सका इसलिये समन तामील नहीं हो सका । ऐसे हजारों दृष्टान्त मिलेंगे । यह कितने शर्म की बात हमारे देश के लिये है । हमको स्वराज्य प्राप्त किये ११ वर्ष हो गये और कांग्रेस को समाजवाद कायम किये हो गये । ये लम्बे-चौड़े दावे करते हैं किन्तु इस तरह की सड़क अभी नहीं बनाई जा सकीं जिनसे गांवों में आसानी से आ जा सकें । पं० जवाहरलाल जी कहते हैं कि जो हमारा लक्ष्य था उस तरफ बढ़ोत्तरी नहीं हुई है और देहातों की उन्नति नहीं हुई और उस ढंग से देहातों में सड़कों का निर्माण नहीं हो रहा है । कैसे निर्माण होगा जब कि हमारी करनी और कथनी में अन्तर है ? कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । मैं कहूंगा कि मंत्री जी इस रवैइये को बदलें और थोड़ा देहात का भी खयाल रखें ।

श्रीमन्, १-२ मिसाल मैं आपके सामने दूं । मेरे यहां गोरखपुर के उत्तरी हिस्से में करीब ५०० गांव ऐसे हैं जो सड़क से २०-२५ मील की दूरी पर पड़ते हैं । बड़ी मुश्किल के बाद आज ८ साल से प्रोग्राम बनते-बनते वह २५ मील की कच्ची सड़क नवतनवां-ठठीवारी बन पाई है । जो हमारे भूतपूर्व निर्माण मंत्री विचित्र नारायण जी शर्मा थे वह उनके जमाने में बनना शुरू हुई लेकिन वह कागज में रह गई । मैं नये मंत्री जी को बधाई दूंगा कि उनके मन्त्रित्व के जमाने में वह बनी, लेकिन उसका बनना न बनना बराबर है । उस २० मील के लम्बे टुकड़े में चार नदी पड़ती हैं उन नदियों पर पुल गायब हैं । मैंने मंत्री जी से कहा कि इस २, २॥ लाख रुपये के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं । वहां पर मिट्टी डाली गई और उसके लिये इतना रुपया व्यय किया गया है लेकिन वह पुल नहीं बना । उन्होंने कहा कि अभी रुपया नहीं है । ४८ हजार रुपये से फरेन्दा में एक डाक बंगला बन गया है । वहां पर पहले से डाक बंगला था लेकिन उसमें मोजैक का काम नहीं था, वह चिकना नहीं था इसलिये ४८ हजार रुपये को खर्च करके उस बंगले को बनाया गया है । मैं समझता हूं कि ४८ हजार रुपये से चारों पुल उस सड़क पर बनाये जा सकते थे, लेकिन उनको नहीं बनाया गया जिसकी वजह से वह सड़क बेकार है । वहां के इंजीनियर ने भी लिखा कि यह सड़क बेकार है, इस पर पुल नहीं है । यदि हमें लकड़ी का पुल बनाने की

[श्री अब्दुल रऊफ लारी]

इजाजत दी जाय तो काम चल सकता है, लेकिन मंत्री जी को यह गवारा नहीं हुआ । कहा यह जाता है कि किसी गांव को ५ मील से दूर सड़क से नहीं रखा जायगा, लेकिन हमारे यहां २५ मील दूर तक के गांव पड़े हुये हैं । तराई के इलाके में लोग ४–४ महीने घिर जाते हैं । कचहरी में पहुंच नहीं पाते हैं । वहां मुकदमे खारिज हो जाते हैं । सैकड़ों आदमी डूबकर मर जाते हैं ।

मैं अपने जिले की बात बताऊं कि गोरखपुर–नौतनवां सड़क के लिये मैंने मंत्री जी से कहा कि एक पुल १५ वें मील पर वहां बना दिया जाय क्योंकि वहां पर पूरा पानी उस पुल से निकल नहीं पाता है, जो वहां है । अभी वहां पर पारसाल कई आदमी सड़क कटने के कारण डूब कर मर गये थे । उसके लिये खयाल यह था कि कांग्रेस सरकार इतने आदमियों की आहुति लेकर इस पुल को जरूर बनवा देगी और कहा भी गया था कि बना दिया जायगा, लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बावजूद इसके कि मुझे आश्वासन मिल गया और मुझे मालूम भी हुआ था कि मन्जूरी हो चुकी है, लेकिन वह पुल आज तक नहीं बन सका । मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान उस पिछड़े हुये अपने क्षेत्र की तरफ आकर्षित करूंगा कि २।। लाख रुपया खर्च करके जो मिट्टी का काम कराया गया है उस नौतनवां–ठूठीबाड़ी सड़क को पक्की करें वरना वह फिर बरबाद हो जायगी । बरसात के पानी से वह सब मिट्टी बह जायगी । वहां की मिट्टी ऐसी होती है कि पानी में घुल जाती है और जल्दी बह जाती है । वह करीब-करीब आधी बह चुकी है और साल दो साल में वह सारी मिट्टी बरबाद हो जायगी और सारा रुपया बरबाद हो जायगा । इस तरह जहां पर पहले थे वहीं पर रह जायेंगे । सार्वजनिक निर्माण विभाग ने जिन जमीनों को लिया है उन किसानों को उसने एक पैसा भी नहीं दिया है । कितने दुख की बात है । किसानों से जबरदस्ती लगान वसूल होता है और जबरदस्ती जमीन छीनकर सड़क में डाल देते हैं, लेकिन उनके लगान को नहीं छुड़ाया जाता, मुआवजे की रकम बाद में दी जातीं, लेकिन उनके नाम के खेतों को तो कटवा देना चाहिये था ताकि वे लगान देने से बच जाते । मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि इस तरफ भी वे ध्यान दें ।

**श्री वासुदेव दीक्षित** (जिला फतेहपुर)—आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बहुत ही अनुगृहीत हूं कि आपने मुझे ४, ५ दिन की उठा-बैठी के बाद यह थोड़ा-सा अवसर दिया ।

मान्यवर, मैं उस पिछड़े हुये जिले का रहने वाला हूं कि जो इलाहाबाद और कानपुर दोनों के बीच में स्थित है । वहां पर सड़कों की संख्या बहुत ही कम है । वहां जी० टी० रोड ही सब से प्रमुख सड़क है और वहां पर दो, तीन छोटी-छोटी सड़कें हैं और मैं इस मौके पर मान्यवर, मंत्री जी का भी आभार प्रदर्शित करता हूं कि उन्होंने साढ़े चार मील की एक सड़क बनाने की योजना अपने इस अनुदान में रखी है । यह योजना एक वर्ष पहले से ही उन्होंने स्वीकार कर दी थी । मैं उनका बहुत ही अनुगृहीत हूं किन्तु यह अवश्य चाहता हूं कि उस पर कार्य आरम्भ भी हो जाना चाहिये । यह इस पुस्तिका में लिखी हुई ही न रह जाय और ऐसा न हो कि द्वितीय नहीं बल्कि तृतीय योजना में यह पूरी न हो ।

वैसे तो मेरा जिला श्रम प्रधान जिला है, लेकिन बहुत पिछड़ा हुआ जिला है । मैं एक छोटा-सा वाकया आपके सामने रखना चाहता हूं । ३ फरवरी को श्रीमन्, श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने पैदल यात्रा मेरे क्षेत्र में की थी । जिस ओर उनको जाना था साढ़े ५ मील की लम्बी सड़क वहां के हजारों नर-नारी, बाल-युवा और वृद्ध ने मिलकर बना कर तैयार कर दी और उन्हीं के द्वारा उसका उद्घाटन कराया गया । मैं यह प्रार्थना करूंगा कि इसकी यादगार स्वरूप माननीय मंत्री महोदय इस सड़क को पक्की नहीं तो कच्ची सड़कों में ही शामिल कर लें ताकि कुछ दिनों तक श्रमदान द्वारा तैयार की हुई सड़क की यादगार ताजी रह सके ।

दूसरी बात मैं यह बता देना चाहता हूं और मैंने जैसा पिछले वर्ष अनुदान के समय उसका जिक्र किया था कि फतेहपुर जिले में सबसे बड़ा राजमार्ग जो था उसको जब जी० टी० रोड बनायीं गयी थी तो काट दिया गया और वह बिलन्दा और कड़ा के बीच में पड़ता है और हथगांव से १८ मील पूर्व रह जाता है जिसमें साढ़े ४ मील सड़क का कार्य इस वर्तमान योजना में ले लिया गया है ।

तो उपाध्यक्ष महोदय, वह पुरानी मुगल रोड है जो कि प्रान्त के अन्य जिलों से आगरा और सिकन्दरा से हो कर आती है और जिले के पश्चिमी भाग में वह बनी है और पूर्वी भाग में शेष है । बहेरा जहां से नयी सड़क का निर्माण हो रहा है वहां से ८ मील रह जाता है और उसे पूरा कर देने से वह बनारस, इलाहाबाद और कलकत्ता तक पूर्ण हो जाती है और पूर्व के बाद पश्चिमी में विलन्दा से पुरानी जी० टी० रोड खत्म हो जाती है और वहां से हथगांव सिर्फ १४ मील शेष रह जाता है । हंसवा ब्लाक ने उसे बनाने के लिये प्रस्ताव भी भेजा है जो १ लाख २० हजार रुपये का है । एक और पुरानी सड़क है जो रायबरेली जिले से मिलाती है फतेहपुर जिले को । यह हसनगंज–हथगांव रोड है जिसके लिये पिठौरा ब्लाक में बेला तक ८ मील और हथगांव ब्लाक में हथगांव ब्लाक से ८ मील तक बनाने का प्रस्ताव दिया है ।

इन योजनाओं में उनको शामिल कर लिया जाय तो एक बड़े केन्द्र का और एक बड़े से पिछड़े क्षेत्र का प्रतिनिधित्व होगा । एक बात मैं और भी अर्ज करूं कि मेरा जिला बड़ा पिछड़ा हुआ है । वहां पर अन्य जिलों से और खास कर बांदा से अन्न पहुंचाना यदि सुलभ न हो और यदि बांदा में पैदावार न हो तो मेरे जिले में भुखमरी हो जाती है । हमारा जिला न तो पूरब में है और न पश्चिम में है बल्कि बीच में एक त्रिशंकु सा लटका हुआ है । इन योजनाओं के अन्तर्गत मैं प्रार्थना करता हूं कि इसको शामिल कर लिया जाय । बांदा में वैसे जमुना जी से, किशनपुर और नौबस्ता रोड के अलावा ठीक उत्तर, गंगा जी तक कोई सड़क नहीं है जिसमें १५ या १४ मील का रास्ता रह जाता है और उसमें एक पुल पड़ता है । उसके लिये जरूरी है कि वहां पर कुछ प्रबन्ध किया जाय क्योंकि उस नदी में हर साल दो, एक जानें चली जाती हैं । डाक ले जाने का भी वही रास्ता है । बाढ़ जब आती है तब उसका बड़ा भयंकर प्रकोप होता है । उसमें मटकियों की घन्नई लगाकर उसको पार किया जाता है और कभी मटके में अगर छेद हुआ तो डाक भी बह गई और आदमी भी बह गया । उसको बनाने की बड़ी आवश्यकता है । अगनई से सेमरहा के बीच में गऊघाट का पुल होगा, उसको शामिल कर लिया जाय । एक बात और कह देना चाहता हूं कि खागा से दक्षिण की ओर जो सड़क जमुना किनारे तक जाती है, मौजा कोटा तक जाती है, वह मेरे क्षेत्र में ९-१० मील पड़ती है, वह बहुत उपयोगी सड़क है और उस पर यातायात बहुत अधिक रहता है और जमुना पार से इलाहाबाद तक जी० टी० रोड से मिल जायगी । उसको शामिल करने की कृपा की जाय ।

**श्री उपाध्यक्ष**—बजट में कुछ रुपया तो बाकी भी रहने दीजिये । (हंसी)

**श्री वासुदेव दीक्षित**—श्रीमन, वैसा तो होता नहीं है । अगर थोड़ा बहुत भी हिस्से में आ जायगा तो खुशकिस्मती समझूंगा । जनता के काम में जो भी धन आ जाय, एक पैसा भी लग जाय वह भी बहुत है । इन थोड़े से शब्दों के साथ मंत्री महोदय ने जो अनुदान आज सदन के सामने प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं ।

**श्री जंगबहादुर वर्मा** (जिला बाराबंकी)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में जितनी सड़कें पहले बनी हुई थीं आज इन ११-१२ सालों में, इस कांग्रेसी राज्य में वह सड़कें खराब हो गई है और आज सड़कों पर बड़े-बड़े गड्ढे और तालाब तक हो गये हैं । और मैंने बाराबंकी में देखा है कि सड़कों के ऊपर धान उगता है । सरकार कहती है कि निर्माण के कार्य पर बहुत-सा रुपया खर्च किया जा रहा है, लेकिन इन ११-१२ सालों में सरकार की तरफ से जितना रुपया निर्माण की ओर खर्च किया गया है वह देहात की तरफ नहीं किया गया है बल्कि दिल्ली, कलकत्ता और बड़े-बड़े शहरों के सजाने के लिये या लखनऊ, बनारस, कानपुर, बरेली, इन बड़े-बड़े शहरों में सारा का सारा रुपया खर्च किया गया है या ओवरसियर, इंजीनियर और बड़े-बड़े अफसरों के मकान बनाने और सजाने पर खर्च किया गया है ।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

लेकिन देहात की तरफ, जहां से तमाम कर लगाकर यह सरकार चलती है, वहां पर एक पैसा भी निर्माण-कार्य में खर्च नहीं किया जाता है । अगर सड़कों के साधन अच्छे होते तो अवश्य ही गांव का स्तर ऊंचा हो जाता । विकास की ओर देखिये तो आपको मालूम होगा कि गांवों में तनिक भी विकास नहीं है, है भी तो शहरों में है । यदि विकास की योजनायें खोली भी गयी है तो वहां तक सरकारी अधिकारी पहुंच भी नहीं पाते हैं और न गांवों की जनता जिला सरकारी अफसरों तक पहुंच पाती है ।

सड़कों के साधन न होने के कारण ही देश में अराजकता, भ्रष्टाचार, कत्ल, डकैती, चोरियां दिन-दिन बढ़ती जा रही हैं । अधिकतर थानों तक यातायात के साधन न होने के कारण सवारियां नहीं मिलती हैं । न जनता ही थानों तक पहुंच पाती हैं और न थानेदार ही घटनास्थल तक पहुंच पाते हैं, इसी कारण सुरक्षा भी नहीं हो पाती । लोगों के स्वास्थ्य का सुधार भी नहीं हो पाता है । डाक्टर गांवों तक नहीं पहुंच पाते हैं और न गांव वाले डाक्टरों तक ही पहुंच पाते हैं । अगर पहुंचते भी है तो बहुत कठिनाई के साथ पहुंचते हैं ।

सड़कों के न होने के कारण दूसरी समस्याओं पर भी इसका बहुत असर पड़ता है। सैलाब आता है, लेकिन सरकारी अधिकारी नहीं पहुंच पाते हैं और न जनता ही अपनी खबर पहुंचा पाती है । अदालत में न्याय के लिये भी नहीं पहुंच पाते हैं । मुकदमे खारिज हो जाते है और लोगों का बहुत-सा पैसा व्यर्थ जाता है । किसान खाद, पांस और बीज का इन्तजाम नहीं कर पाता है । लेकिन सरकार बरेली, बनारस, कानपुर और लखनऊ में मकान बनवा रही है। मंत्रियों के बंगले, एम० एल० एज के बंगले और कानपुर में पूंजीपतियों के इस्तेमाल के लिये बड़ी-बड़ी सड़कें और बनारस में मंत्री के रास्तों को सजाने के लिये सड़कें बनायी जा रही हैं । अगर सरकार ने गांवों में ऐसा किया होता तो गांवों की इकाई ऊंची हुई होती । सरकार कर तो गांवों पर लगाती है और शहरों को ऊंचा उठाती है। कहीं अमेरिका की नकल की जाती है और कहीं इंगलैंड की नकल की जाती है ।

कच्ची सड़कों को बनाने में ५ हजार रुपया प्रति मील लगता है, कंकड़ की सड़क को बनाने में १० हजार, अलकतरे की सड़क बनाने में ५० हजार और सीमेंट की सड़क को बनाने में ३ लाख रुपया लगता है । लेकिन ये सड़कें कहां बनती हैं ? अगर देश को ऊंचा उठाना है, अपनी योजनाओं को पूरा करना है, समाजवाद लाना है तो पहले आपको गांवों के स्तर को ऊंचा करना होगा, वहां की सड़कों को बनाना होगा । सीमेंट और डामर की सड़कों को छोड़कर पहले आपको कंकड़ की सड़कों को बनाना होगा। लेकिन सरकार तो अमेरिका और इंगलैंड की नकल करती है और वहां के मंत्रियों को दिखाने के लिये शहरों को सुजज्जित करती हैं, सड़कों के किनारे गमले और खरंजे लगाये जाते हैं, लेकिन गांवों के स्तर को ऊंचा करने के लिये कुछ किया नहीं जाता है । गांव घूर हो रहे हैं, लेकिन सरकार उधर ध्यान नहीं दे रही है ।

बाराबंकी जिला इतना बड़ा जिला है, लेकिन उसमें केवल चार सड़कें अच्छी है उन पर भी आने-जाने के साधन नहीं हैं । उन पर रोडवेज की सवारियां नहीं है । जो प्राइवेट लारियां चलती हैं उन पर इतने टैक्स लगा दिये गये हैं कि जनता उनको बरदाश्त नहीं कर पाती है । अगर सरकार जनता को आराम पहुंचाना चाहती है तो उन लारियों, तांगे और इक्के वालों पर से टैक्स कम करे । लेकिन सरकार इस ओर नहीं है । हम आपको यहां तक बतलावें कि जितना पैसा सरकार की ओर से खर्च हो रहा है वह सब बर्बाद ही होता है । अगर उन रुपयों से कम से कम कंकड़ की सड़कें ही बना दी जायं तो जनता को कुछ सहूलियत हो सकती है । आजकल कंकड़ की जो सड़कें बनायी जाती हैं उनकी हालत यह है कि पहले कंकड़ विछा दिये जाते हैं और फिर उनके ऊपर मिट्टी छोड़ कर पाट कर बराबर कर दिया जाता है । जब उसके ऊपर गाड़ी या मोटर चलती हैं

तो कंकड़ उखड़ जाते हैं । कंकड़ की जो सड़कें पुराने जमाने की बनी हुई हैं वे आज भी उन नयी सड़कों से काफी मजबूत हैं जो कि आज नयी बन रही हैं । दूसरी तरफ इंजीनियर लोग ठेके के एकाउंट में से अब १२ प्रतिशत से बढ़ाकर १७ प्रतिशत तक लेने लगे हैं । नैपुरा घाट पर जो पुल बना है उसके सम्बन्ध में मैं आपको बतलाऊं कि उसका ऐस्टीमेट पहले ६ लाख रुपये का था जो कि बढ़ते-बढ़ते करीब ८ लाख रुपये का हो गया । उसका कारण यह है कि इंजीनियरों और ठेकेदारों ने मिल कर, आपस में सांठ-गांठ करके उसके ऐस्टीमेट को बढ़ा दिया और वहां के गरीब मजदूरों की मजदूरी १०,००० रु० तक बाकी है, लेकिन उसकी तरफ सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया । जब माननीय निर्माण मंत्री श्री गिरधारी लाल जी उस नैपुरा घाट पुल का उद्घाटन करने गये थे तो मैं भी उस उद्-घाटन समारोह में सम्मिलित हुआ था । उद्घाटन करने के बाद उस पुल को इंजीनियर और जिलाधीश ने देख कर कहा कि ठीक है । मैंने उस पुल को पहले ही देखा था कि उसका एक पैरापिट चल गया है जिसे मैंने निर्माण मंत्री को दिखलाया । लेकिन वहां के अधि-कारियों ने उसकी लीपापोती कर दी और उनका ही विश्वास माननीय मंत्री जी ने कर लिया । उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी । इंजीनियर ने उस पैरापिट का थोड़ा-सा हिस्सा खोदवाकर और बाद में फिर उसे बराबर करवा दिया । लेकिन मैं तो वहीं का रहने वाला हूं, मेरा गांव उसके निकट ही है, मेरा रोज का आना-जाना होता है । वह पैरापिट फिर चल गया । तीन बार मैंने माननीय निर्माण मंत्री को पत्र लिखा, जिलाधीश को भी पत्र लिखा, कम्पलेंट बुक में भी लिखा, लेकिन आज तक निर्माण मंत्री जी ने इंजीनियर को छोड़ रखा है और उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की । फिर नैपुरा घाट के पुल का एस्टीमेट जो पहले ६ लाख का था वह बढ़ कर ८ लाख क्यों हो गया, इसके लिये उनसे आज तक नहीं पूछा गया, आखिर इसका कारण क्या है ? उस पार आने-जाने के साधन बिलकुल बन्द हो गये हैं । सरकारी कर्मचारियों, नौकरों और चप-रासियों को तो उतराई नहीं देनी पड़ती है और पहले विधायकों को भी उतराई नहीं देनी पड़ती थी, लेकिन अब सरकार ने एक कानून बनाया है जिसके अनुसार विधायकों को उतराई देनी पड़ेगी । वह क्षेत्र दो हिस्सों में बंटा हुआ है और उस क्षेत्र की जनता के सुख-दुख की जानकारी करने के लिये मुझको बार-बार जाना पड़ता है और अगर हम मोटर से या मोटर साइकिल से जाना चाहें तो फिर बार-बार उतराई देनी पड़ेगी । इसलिये सरकार को इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है ।

इस विभाग में भ्रष्टाचार बहुत फैला हुआ है । मैं आपको बतलाऊं कि लखनऊ के एक चीफ इंजीनियर ने अपने पद का इतना दुरुपयोग किया है कि एक बार सोशलिस्ट पार्टी ने इस सवाल को यहां उठाया भी था कि उन्होंने अपना एक मकान बनवाया और सीमेंट आदि तमाम सामान लगाया, खरीदा नहीं है । मैं कहता हूं क्या जांच की ? लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्यवाही नहीं हुई . . . .

**श्री उपाध्यक्ष**--यह बहुत पुराना सवाल है, किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं है ।

**श्री जंगबहादुर वर्मा**--अयोध्या में जो पुल बन रहा है उसका कितना हिस्सा अब तक बन चुका है और उसमें कितना खर्च हुआ है उसका कोई विवरण माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में नहीं दिया है । इसका कारण यह है कि इंजीनियर और ठेकेदार मिल कर बाद में एस्टीमेट बढ़ा लेंगे, इसीलिये उसके बारे में इस समय कोई सूचना सदन को नहीं दी गयी । जो सड़कें बन रही हैं इनमें भी बहुत-सी भूमि निकल रही है जिसका असर अन्न के उत्पादन पर भी पड़ेगा । इसलिये सरकार को चाहिये कि वह नहरों के किनारे की जितनी सड़कें हैं उनको पक्का बनवा कर सार्वजनिक जनता के लिये खोल दे ।

[श्री जंगबहादुर वर्मा]

इससे एक लाभ यह होगा कि दूसरी सड़कों के बनाने में जो पैसा बर्बाद हो रहा है वह बच जायेगा तथा अन्न उत्पादन की समस्या भी हल हो सकेगी ।

**कुमारी कमलकुमारी गोइंदी** (जिला इलाहाबाद)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं उपस्थित अनुदान संस्था ३३-३४ का समर्थन करने के लिये खड़ी हुई हूं । अभी जितने सज्जन यहां बोले हैं उन्हीं की डिमांड पर अगर अन्दाजा लगा लिया जाय तो जितना बजट उपस्थित हुआ है उससे कई गुना ज्यादा हमको चाहिये और जो लोग नहीं बोले हैं उनका चुपके से अन्दाजा लगा लिया जाय तो उससे शायद सौ गुना हमको अधिक बजट चाहिये । इसलिये कटौती का सवाल उत्पन्न नहीं होता । पता नहीं कैसे कटौती रख दी गयी है ?

मैं अपनी सरकार का एक खास चीज की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं । वह यह कि इस विभाग की देखरेख में ढीलापन नहीं होना चाहिये । कहीं-कहीं ऐसे टेंडर सब्मिट होते हैं जिनके लिये कामनसेन्स यह बतलाता है कि इतने में यह चीज नहीं हो सकती और अगर कोई उतने में बना देगा तो अवश्य ही बेईमानी करेगा, तो ऐसे टेंडर्स सब्मिट करने वाले कांट्रेक्टर्स से डीलिंग फौरन बन्द कर देना चाहिये । आपने अनुमान लगा लिया कि इतने में सड़क बन जायगी एक मील उससे कम टेंडर आता हैं तो वह अपना प्राफिट कहां से लेता है ?

दूसरे भ्रष्टाचार के सिलसिले में कडापन आना चाहिये । यह सवाल नहीं है कि हम उस कार्य को बन्द कर दें, लेकिन आज भी इसके अन्दर जो भ्रष्टाचार होता है उसे कड़ेपन से डील किया जाय ।

मैं दो मिनट में अब अपने क्षेत्र की ओर माननीय मंत्री का ध्यान दिलाना चाहती हूं । मैं जिले इलाहाबाद, क्षेत्र करछना की नुमाइंदा हूं । १० वर्ष के अन्दर यह जो क्षेत्र है पी० डब्ल्यू० डी० के नक्शे के अन्तर्गत नहीं आया । इस जिले में कुछ मील कच्ची-पक्की सड़के बन कर तैयार हुई भी, लेकिन १ फर्लांग भी इस क्षेत्र के अन्दर सड़क नहीं बनी है । इलाहाबाद जिला काफी एडवांस्ड है, लेकिन इस क्षेत्र को शायद माननीय मंत्री भूल गये हैं । मैं फिर याद दिलाती हूं कि इसकी ओर ध्यान दिया जाय ।

इस क्षेत्र में घुरपुर से लेकर कोहारघाट तक एक सड़क है जिस पर श्रमदान से ५ वर्ष तक बहुत कार्य हुआ है । सैकड़ों ही गांव इस पर पड़ते हैं जो बरसात के दिनों में कट कर अलग हो जाते हैं और वहां पर काम करना बिलकुल असुविधाजनक हो जाता है । इसलिये इस सड़क को प्रायारिटी देकर बनवा दिया जाय । आशा है माननीय मंत्री इस पर ध्यान देंगे ।

दूसरी सड़क घुरपुर से लेकर लालापुर तक है । घुरपुर से भीटा तक डेढ़ मील की सड़क बीच में ऐसी पड़ती है जो पत्थर की क्वेरी पर पड़ती है । अगर यह टुकड़ा बन जाय और इसी साल बन जाय तो हजारों आदमियों को, वहां के रहने वालों को पत्थर की क्वेरी पर अधिक काम मिल सकेगा । ट्रक्स पत्थर को सुविधापूर्वक उठा सकेंगे । इस तरह से इस क्षेत्र के हजारों आदमियों को काम मिल सकता है जिससे उन तक अनाज, कपड़ा, रोटी पहुंच सकेगी । बाकी सभ्यता तो सड़कों के साथ पहुंचती ही है ।

तीसरे घोड़ेडीह से लेकर कनासा तक एक सड़क फ्लड रिलीफ कमेटी ने ४ वर्ष पहले से ले रखी है, लेकिन आज तक यह ज्ञात नहीं हो सका कि यह कब तक बन सकेगी । जब भी विभाग वालों से मैं पूछती हूं तो कह दिया जाता है कि पता करके बतला दिया जायगा । इतना ढीलापन है कि पता ही नहीं चलता कि क्या हो रहा है सिवा इसके कि पता करके बतला दिया जायगा । यह केवल ४ मील की सड़क है । अगर यह भी इस वर्ष बना दी जाय तो बहुत अच्छा होगा क्योंकि इस सड़क के बनने से बीसियों गांव पक्की सड़क से मिल जाते हैं । इसलिये इसकी ओर ध्यान दिया जाय ।

एक बात सार्वजनिक यह भी है कि आजकल गांव के अन्दर सब लोग जानते हैं कि लोग रास्ता काट कर अपने खेत को बढ़ा लेते हैं या रास्ते को छोटा कर देते हैं। इसलिये जहां-जहां सड़क बननी हों वहां पहले डिमार्केशन हो जाय और रास्ते में जिन छोटे-छोटे पुलों की आवश्यकता पड़े उनको बना दिया जाय। सबसे पहले इस चीज को महत्व दिया जाय।

मुझे आशा है कि माननीय मंत्री जी पूरी तवज्जह से इसे करेंगे और निराश मुझे नहीं लौटायेंगे। मैं फिर एक बार अनुदान संख्या ३३ व ३४ का समर्थन करती हूं। अगर हो सके तो बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स के फण्ड से काट कर इस जगह पर लगा दिया जाय तो मैं बड़ी अनुग्रहीत हूंगी।

**श्री भगवतीसिंह विशारद** (जिला उन्नाव)--उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के संक्षिप्त तथा भविष्य के लिये अर्थहीन भाषण को मैंने सुना और उनके द्वारा प्रस्तुत की गई बोझदार किन्तु आन्तरिक मूल्य से रहित रिपोर्ट को भी पढ़ा। मुझे उस रिपोर्ट में बसन्त पंचमी के दिन प्रयाग में घटने वाली दुर्घटना के भविष्य में न घटने के सम्बन्ध में आश्वासन मिला और न वैसी घटनाओं की घटनाओं की पुनरावृत्ति न होने देने का दृढ़ संकल्प। इसलियें जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है उसका समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं।

मान्यवर, प्रदेश के औद्योगिक विकास के लिये और इस प्रदेश को उन्नतिशील बनाने के लिये सार्वजनिक निर्माण विभाग का बहुत बड़ा दायित्व है। अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग यातायात के साधन उपलब्ध नहीं कर सकता तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि हमारे प्रदेश का भविष्य उज्जवल नहीं रहेगा और वह इसलिये कि जिस समय हम नियोजन काल से गुजर रहे हैं और हमारी पंचवर्षीय योजना बनी हुई हो, उस समय हमें अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिये। लेकिन माननीय मंत्री जी ने जो भविष्य के आंकड़े बतलाये कि इतने समय तक इन-इन कामों को पूरा कर दिया जायगा उनके पूरा होने की कोई संभावना नहीं दिखाई देती, क्योंकि योजना के ३ साल समाप्त हो रहे हैं, चौथे वर्ष में हम पदार्पण कर रहे हैं। माननीय मंत्री ने बतलाया कि केवल ५५ पुलों का निर्माण हुआ और ४० पुलों के निर्माण-कार्य की प्रगति बतलाई है। अगर इस तरह से कार्य चलता रहा तो हम अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते और अगर लक्ष्य तक नहीं पहुंचते हैं तो कोई कारण नहीं है कि हम इस बात को न कहें कि यह विभाग अपनी कार्यक्षमता में अधूरा है।

इस वभाग की एक सबसे बड़ी खराबी है और वह यह कि जिस समय कार्य शुरू होता है उस वर्ष योजनायें प्रस्तुत कर दी जाती हैं, लेकिन वर्ष का जब अन्त होता है तो उसके बाद हम सब लोगों को यह बतलाया जाता है कि कार्य में कटौती कर दी गयी है।

मैं इसके सम्बन्ध में केवल एक ही उदाहरण देना चाहता हूं। उन्नाव जिले के सम्बन्ध में एक सड़क थी भगवन्तनगर---ऊंचगांव सड़क का निर्माण। सम्भवतः पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित होकर उसका ऐस्टीमेट बन गया था। १९५७-५८ में इस सड़क के निर्माण पर २,२५६ रु० खर्च किया गया। इस सड़क के लिये १,००,००० रु० जरूर स्वीकार किया गया होगा। लेकिन १,००,००० रु० की स्वीकृति के बाद और केवल २,२५६ रु० खर्च करके और फिर चुपचाप बैठने का अर्थ मैं अब तक नहीं समझ पाया। मान्यवर, जहां १५,३०,००० रुपया भवनों के मरम्मत के लिये स्वीकार किया गया है, सर्किट हाउसेज के परिवर्तन और परिवर्धन की बात कही गई, कुछ तहसीलों, "कलेक्टरियों और कचेहरियों" की मरम्मत की बात कही गई वहीं पर मैं कोई कारण नहीं पाता कि

[श्री भगवतीसिंह विशारद]

इन स्कूलों की, जिनकी देखभाल सार्वजनिक निर्माण विभाग से होती है, उनकी मरम्मत के सम्बन्ध में इस मद से क्यों रुपया नहीं खर्च किया जा रहा है ? आज इस बात की क्या आवश्यकता है कि सर्किट हाउसेज का परिवर्तन और परिवर्धन किया जाय ? क्या हमारे अफ़सर वर्ग के लोगों में कुछ नई तरह की प्रवृत्तियां पैदा हो गई हैं जो सर्किट हाउसेज १०, १५ साल से उनके प्रयोग में आ रहे थे उनमें ऐसी कौन-सी कठिनाई बढ़ गई जिसके कारण इस तरह की आवश्यकता पड़ गई कि उनमें फिर से परिवर्तन और परिवर्धन करने की कोशिश करें ? मान्यवर, गत वर्ष भी मैंने कहा था अगर ड्रेनेज का काम यह विभाग अपने ही हाथ में ले तो प्रदेश का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है । मुझे गत वर्ष भी निराशा हुई थी और इस वर्ष भी मालूम होता है कि सार्वजनिक निर्माण मंत्री इस भार का वहन नहीं करना चाहते हैं । उनके डिपार्टमेंट में अभी तक पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी था, लेकिन अब तो डिप्टी मिनिस्टर की वृद्धि हुई है । मैं आशा करता हूं कि वे अपने विभाग में कुछ इस तरह की ऐफीशियेंसी जरूर दिखायेंगे जिससे लोगों को विशेष शिकायत करने का अवसर न मिले ।

मैं अपने निर्वाचन-क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि मेरे यहां दो विशेष रूप से ऐसी सड़कें हैं जिनमें से एक को सरकार ने स्वीकार कर लिया है और दूसरी के स्वीकार होने की बात सुनाई पड़ रही है । पहली भगवन्तनगर-ऊंचगांव की सड़क जिसको सरकार ने स्वीकार किया है १३ मील लम्बी है । पता नहीं उसको स्वीकार करने के बाद और उसी पर २,२५६ रु० खर्च करने के बाद अब तक उसका काम क्यों ढीला पड़ा हुआ है । इसी तरह से दूसरी सड़क विक्रमपुर-रूझिहई-वक्सर की है । जिसका सम्बन्ध बाढ़ पीड़ित इलाके से है । जिस समय बाढ़ आती है अगर इस क्षेत्र में इस सड़क का निर्माण नहीं स्वीकार किया गया तो उस इलाके के बाढ़ पीड़ित लोगों को महान कठिनाई उठानी पड़ती रही हैं और भविष्य में भी रहेगी । बाढ़ के समय किसी तरह की उक्त क्षेत्र को सहायता पहुंचाना असम्भव रहता है । इसलिये मैं आशा करता हूं कि भविष्य में इस क्षेत्र के लोगों को उस कठिनाई का सामना न करना पड़ेगा । मैंने पिछली बाढ़ में स्वयं अनुभव किया है ? इसलिये मेरा अनुरोध है कि बिक्रमपुर-रुझिहई-वक्सर को जो सड़क जाती है, अगर बाढ़ पीड़ित लोगों की सहायता करना मंत्री जी अपना कर्त्तव्य समझते हैं तो इस सड़क को बनवायेंगे । जब तक वे कोई सक्रिय कदम नहीं उठाते तब तक बाढ़ पीड़ित लोगों को कोई लाभ नहीं पहुंच सकता । इस वर्ष जब भयंकर बाढ़ आयी थी उस समय राशन वगैरह पहुंचाने में अधिकारियों को और स्वयं मैं भी उस कार्य में सक्रिय था, उसका मुझे अनुभव है, कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा कह नहीं सकता । तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस क्षेत्र में जो भगवन्तनगर-ऊंचगांव और विक्रमपूर-रुझिहई-वक्सर वाली यह दो सड़कें हैं इनको मंत्री जी विशेष रूप से बनवाने की कृपा करेंगे । इन सड़कों पर बरसात के दिनों में, लखनऊ से दिल्ली जाने में जितना वक्त और पैसा लगता है उससे ज्यादा समय और पैसा समीप के रेलवे स्टेशन से आसपास के गांवों में आने जाने में लग जाता है । इसीलिये यदि धनाभाव का कारण बताकर मंत्री जी जनता की भावनाओं का आदर नहीं करेंगे तो मैं समझता हूं कि जनता के साथ बहुत बड़ी ज्यादती होगी ।

**श्री सीताराम शुक्ल** (जिला बस्ती)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ध्यान के साथ विरोधी वृन्द के व्याख्यानों को सुना और फिर भी कटौती का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं । लेकिन उस पर अर्ज करने के पहले माननीय मंत्री महोदय और उनके कर्मचारियों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने मेहनत करके इस अच्छे बजट को पेश किया । किन्तु वे मेहनत भी करते हैं और उनकी शिकायत भी होती है...

**एक सदस्य**—ग्रान्ट पेश है, बजट नहीं ।

**श्री सीताराम शुक्ल**—बजट के अन्दर ही ग्रान्ट है, बाहर नहीं है। मैं अर्ज करता हूं कि हर साल शिकायत होती है, तारीफ बहुत कम लोग करते हैं। शिकायत ज्यादा करत ह। यही नहीं इन लोगों की शिकायत तो श्री राजगोपालाचार्य ने भी की थी कि एनिमी और शत्रु नम्बर वन हैं कम्युनिस्ट, और एनिमी नम्बर टू हैं पी० डब्लू० डी० के कर्मचारी। राजाजी की बात तो गलत नहीं हो सकती। वह ऐसे आदमी नहीं जो गलत कहते हैं। सोचना है कि क्यों शिकायत होती है। बजट आया, पास हुआ, शिकायत हुई। मेजारिटी पास करदे यह काफी नहीं है। कोशिश यह होनी चाहिए कि ऐसा काम हो कि शिकायत न हो सके। मैं मानता हूं कि इस डिपार्टमेंट के द्वारा सड़कें बहुत निकलीं, रास्ते बहुत निकले, पुल बहुत बने, बड़ी मेहनत से काम हुआ। सब कर्मचारी बुरे नहीं हैं जैसे कांग्रेस में अच्छे लोग भी हैं, बुरे लोग भी हैं। विरोधी वृन्द में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। उसी तरह कर्मचारियों में भी हैं। देश में भी हर तरह के लोग हैं। इसलिये गुजारिश यह है कि जब बुरों की शिकायत कीजिये तब अच्छों की तारीफ भी कीजिये। मान लीजिये हमने १० करोड़ रुपया खर्च किया और ९ करोड़ का काम हुआ। तो ९ करोड़ से बहुत से रास्ते, बहुत से पुल और बहुत सी सड़कें बढ़ेंगी, लेकिन शिकायत हो जाएगी। देखना यह है कि जितना खर्च हुआ उतना काम हुआ कि नहीं। १० करोड़ रुपया खर्च किया जाय और १० करोड़ का ही काम हो तो शिकायत नहीं होगी और न तारीफ होगी। १० करोड़ में ११ करोड़ का काम हो तब तारीफ होगी। इसलिये रचनात्मक कामों के प्रशंसकों से मेरी प्रार्थना है कि तारीफ भी करें तो कितना खर्च हुआ है इस पर भी ध्यान दें।

उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आज एक नई बात सुनी। अभी तक कांग्रेसी, गैर-कांग्रेसी सरकारी कर्मचारियों और विरोधी वृन्द का प्रश्न था किन्तु अब एक नया प्रश्न और आया है शहर और देहात का कि सारा काम शहर में होता है, देहात में नहीं होता है। लोग यह भूल जाते हैं कि शहर बसे हैं देहातों से, शहर से ही मनीआर्डर देहात में जाता है। यूनिवर्सिटी में देहातों के लोग भी पढ़ने आते हैं। इसलिये शहर और देहात का सवाल पैदा करना ठीक नहीं है। मेरे दोस्त आंखें दो हैं, एक बांई और एक दाईं। हर आदमी चाहता है कि दोनों अच्छी रहें। न दांई फूटने पावे और न बांई। तो क्या देहात क्या शहर, सरकार दोनों की भलाई चाहती है। आपको मालूम है शहर में क्या तकलीफ ह? सफेद कपड़ों क अन्दर भी परेशानियां हैं। लेकिन वक्त कम है, इस पर विस्तार में न जाकर सुझाव दूंगा कि कैसे यह शिकायत दूर हो। हुजूर वाला, सरकारी कर्मचारी जो हैं यह शासन करना तो जानते हैं, मुकदमे की बहस करना और सुनना जानते हैं, फैसला भी लिखना जानते हैं और हुकूमत करने प्रदेश के नक्शे बनाने भी जानते हैं, लेकिन स्वार्थी को परमार्थी बनाना नहीं जानते। दूसरे की भी कुछ सेवा करो, स्वार्थ न देखो, यह कम लोग जानते हैं। अंग्रेजों ने सरकारी नौकरों को सिखाया कि "रुपया खूब कमाओ, लाओगे चढ़ने को घोड़ा पावोगे" इसलिये दिमाग में यही है कि नौकरी करके सफेद कपड़ा पहनेंगे, आराम से रहेंगे तब उनमें सेवा भाव कहां से आयेगा? फिर आज कल के जमाने में ऊंचे खर्च हैं, सफेदपोशी है और जो कीमत रुपये की थी वह भी कम हो गई। सन् १९४२ में चार आने का जितना सामान मिलता था उतना सामान अब एक रुपये में मिलता है। ऐसी हालत में वह क्या करें। मजबूरन रिशवत लेते हैं इसको दूर करने की एक तरकीब है। कुछ प्रचार किया जाय, उनको बताया जाय कि उनकी भलाई इसी में है कि वह परोपकार की दृष्टि से सेवा करें कि उनकी हुकूमत में कोई दुखी न हो, किसी को परेशानी न हो, दूसरों को उन से आराम मिले। किन्तु यह काम साधारण वक्ता के लेक्चर देने से नहीं चलेगा, यदि आप खुद चरित्रवान नहीं हैं तो कितने ही उपदेश दें कोई लाभ नहीं होगा, एक शराबी शराब पीने को मना करे तो उसका असर नहीं पड़ेगा अगर लोग जानते हैं कि

[श्री सीताराम शुक्ल]

यह नशे में बोल रहा है तो उसकी कोई नहीं मानेगा। इसलिय चरित्रवान वक्ता ही परोपकार के भाव को सेवा के भाव को बढ़ा सकते हैं और लोगों को उस तरफ ले जा सकते हैं।

आराम किसको कहते हैं? आराम केवल बढ़िया कपड़े पहन लेने से, बंगले में रहने से नहीं होता लेकिन जिसका चरित्र अच्छा है जो लोगों की भलाई करता है उसका दिल आराम पाता है लेकिन रिश्वत लेने वाले चाहे अच्छा खा लें, अच्छा कपड़ा पहन लें लेकिन उनके ऊपर लोग उंगली उठाते हैं इससे उनकी आत्मा सन्तुष्ट नहीं हो सकती। जो आत्मा का सुख है वह मोटर, मकान, अच्छा खाने से, बगीचे से नहीं मिलता। आज आप बड़े अफसर हैं हो सकता है कि आपके ४ लड़के हो जायं और फिर उनके भी ४-४ लड़के हो जायं तो १६ भाग हो जायंगे और कोई गारन्टी नहीं है कि सब सरकारी नौकरी में ही रहें, वह खेती भी नहीं कर सकेंगे। इसलिये वह सोचें कि विपत्ति उनके बच्चों पर भी कभी आगे पड़ सकती है। किन्तु जनता में अगर सेवा की भावना रहेगी तो निश्चय ही आप के बच्चे भूखों नहीं मरेंगे। उपाध्यक्ष जी, आपने लाल बत्ती,.....

श्री उपाध्यक्ष—आप के २ मिनट हैं, आप कुछ अपने हल्के की सड़कों के बारे में भी कह लें।

श्री सीताराम शुक्ल—कुछ समय मुझे आप और दे दें.....

श्री उपाध्यक्ष—आज में वक्त की रियायत किसी के साथ नहीं करूंगा। आप अपने समय में ही खत्म कर दें।

श्री सीताराम शुक्ल—आखिरी सुझाव मेरा यह है कि सचरित्र महात्माओं के व्याख्यान कराये जायं, उनके उपदेश से लाभ हो सकता है। महात्मा गांधी ने जब सुन्दर बात कही बिगुल बजाया तो अनेक सरकारी कर्मचारियों ने अंग्रेजों की नौकरियों पर ठोकर मार दी, सचरित्र महात्माओं की और विद्वानों की कमी नहीं है। उनसे कहा जाय कि आप आयें हमारे कर्मचारियों के सामने उपदेश करें, उनमें सेवा और परोपकार की भावना भरें। महानुभाव, स्वामी नारदानन्द जी हैं, बड़े-बड़े महात्मा हैं जो सच्चरित्र हैं, उनके उपदेश का असर पड़ सकता है, लेकिन वे खरीदे नहीं जा सकते। वह पैसे से नहीं मिल सकते, वह सेवा और सम्मान से मिल सकते हैं। उनके उपदेश से सद्भावना पैदा होगी और लोग अच्छे बनेंगे। जब अच्छे बनेंगे तब तो मुल्क की तरक्की होगी और लोगों को सामान सस्ता मिलेगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री मोहनलाल वर्मा, आप ५-७ मिनट में समाप्त कर दें।

श्री मोनहलाल वर्मा (जिला हरदोई)—मैं अपने जिले की बात नहीं कहूंगा, तजुर्बे की बात कहूंगा।

श्री उपाध्यक्ष—५-७ मिनट में बहुत काफी काम की बात हो सकती है।

श्री मोहनलाल वर्मा—उपाध्यक्ष महोदय, मैंने सभी के भाषण सुने और मैं इस सिलसिले में नये निर्माण की बात नहीं करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि इससे मंत्री महोदय और अधिकारीवर्ग इनकार नहीं कर सकता कि जो सारे हेड का रुपया है इसमें केवल ६० फीसदी रुपया सही प्रकार से लगता है और ४० परसेंट खाया जाता है, इसको ठीक प्रकार से इस्तेमाल करने का आयोजन किया जाय। कोई भी कांट्रेक्ट हो उसमें १५ फीसदी तो ठेकेदार समझ लेता है कि इसमें से निकालना है और इस तरह से ८५ फीसदी रह जाता है।

आज यह पुस्तिका जो बंटी है इसमें कुछ फोटो दिये हैं उनसे बिल्डिग की खूबसूरती और मजबूती कोई हमारे सामने नहीं आती है। आपके सामने दारुलशफा की बिल्डिग मौजूद है और जिस जमाने में हम कौंसिल के मेम्बर थे उस जमाने में वह बन रही थी। ३-४ कमरों में हम रहे हैं और आज आप धुलवायें तो पानी का पलो उलटा है, सीधा नहीं है। हमने तो

कमरे धुलाने छोड़ दिये हैं और यहां एग्जिक्यूटिव इंजीनियर, चीफ इंजीनियर वगैरह सब मौजूद हैं। तो यह बिल्डिंग तो हमारे सर पर मौजूद है।

दूसरी बात यह है कि डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर छोड़कर सुपरिन्टेंडिंग इंजीनियर जिस समय दौरा करते हैं—मिनिस्टरों की बात नहीं करता हूं—तो पहले से दौरे का प्रोग्राम छप जाता है। ऐसा न करके सरप्राइज विजिट किया करें। प्रोग्राम चूंकि पहले से छप जाता है तो उनकी मोटर में बैठ कर ही इंजीनियर और ओवरसियर वही काम दिखला देते हैं जो पूरा हो गया होता है। जब वे मुआइना करते हैं तो उनका फर्ज होना चाहिए कि सरप्राइज विजिट करें।

एक चीज यह है कि एक्जिक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर को अधिकार है वर्क ऐग्रीमेंट करने का कि जिस रेट पर चाहे कांट्रेक्ट दे दें। यह खत्म किया जाय। १०,००० रु० से ज्यादा काम का अधिकार उनके हाथ में न रखा जाय। एक्जिक्यूटिव इंजीनियर और सुपरिंटेंडिंग इंजीनियर द्वारा ५०-५० हजार रुपये के काम सेक्शन करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर को अख्तियार दे दिये गये हैं। एक लाख का काम हुआ तो ४०-४० हजार का अलग-अलग लोगों को दे दिया अपनी मरजी के मुताबिक। टेंडर तक नहीं लेते, बल्कि अपने कुछ पेट ठेकेदार होते हैं और हर एक के २-४ पेट ठेकेदार होते हैं उनको ही वह काम दे देते हैं। यह प्रथा खत्म कर दी जाय। बड़ी सड़कों पर तो मैं कहने को तैयार हूं कि आधे से ज्यादा काम करने वाले फर्जी होते हैं। दो-चार इंजीनियर के यहां, दो-चार ओवरसियर के यहां काम करते हैं। अगर मौके पर जाकर सरप्राइज विजिट की जाय तो मस्टर रोल से हाजरी लेने पर मालूम हो जायगा कि कितने फर्जी भरे हुए हैं। तो इस रुपये के दुरुपयोग को रोका जाय। मेरा सुझाव यह है कि जिस प्रकार इरिगेशन डिपार्टमेंट में हाई रैंक आफिश्यल करप्शन को चेक करने के लिए रखा गया है जिससे वह विभाग आज थर्रा रहा है, इसी प्रकार से पी० डब्लू० डी० में भी हाई रैंक का आफिश्यल हो और वह भी कम्पलेंट्स के ऊपर ऐक्शन लेना शुरू करे। ठेकेदार की यह हिम्मत नहीं होती कि वह ओवरसियर या इंजीनियर के खिलाफ दरख्वास्त दे और अगर ए नानिमस दरख्वास्त जाती है तो उन्हीं के जरिये इन्क्वायरी होती है, वह भी पूरी नहीं हो पाती है। तो जितना रुपया वेस्ट होता है वह इसी प्रकार से बचाया जा सकता है कि अगर कोई प्रान्त का हाई रैंकिंग अफसर मुकर्रर हो।

मैं एक अपने जिले की मिसाल देता हूं। हमारे यहां बिलग्राम में सड़क बनी, सोलिंग हुई, इंजीनियर साहब ने सर्टिफिकेट दे दिया कि फर्स्ट क्लास ईंट लगी है। कुछ लोगों ने शिकायत की कि यह फर्स्ट क्लास ईंट नहीं है, दूसरे इंजीनियर को दिखलाया जाय। दूसरे इंजीनियर ने कहा कि यह थर्ड क्लास ईंट है। दोनों इंजीनियरों में झगड़ा हुआ और ८ महीने से हमारे डिप्टी कमिश्नर महोदय फैसला नहीं कर पाते हैं। जो डिवीजन के कमिश्नर महोदय हैं उनके नोटिस में मामला लाया गया, हमने भी लिखा, लेकिन आज तक उसका निर्णय नहीं हुआ। इसी तरह पिछले साल एक ढाई लाख रुपये की लागत का पुल सई नदी पर बना। वह इसलिये बनाया गया कि बरसात में रास्ता जारी रहे। बरसात में सड़क कट गयी और डाइवर्जन बनाया गया। पुल ऐसी जगह बना है कि पलो उधर नहीं है। फिर यह हुआ कि नया कल्वर्ट बनाया जाय। उसको भी इंजीनियर साहब ने मंजूर नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि ढाई लाख का पुल बनने के बाद भी वह रास्ता बरसात में खुला नहीं रह सकेगा। इसी तरह हमारे जिले में एक पुलिस स्टेशन अतरौला है। चार साल से वहां ईंटें पड़ी हैं। पता नहीं इंजीनियर साहब की क्या मंशा है कि आज तक वहां का न तो कंट्रेक्ट हुआ है न कुछ। इमारत टपकती है। जब बार बार कहा जाता है तो कहते हैं कि कोई ठेकेदार नहीं मिलता है।

[श्री मोहनलाल वर्मा]

मेरे कहने का मतलब यह है कि जो अनुदान मंजूर होता है उसका अगर ८५ प्रतिशत ही, क्योंकि १५ प्रतिशत तो आप रोक नहीं सकते जो ओवरसियर और इंजीनियर का कमीशन होता है, लेकिन अगर ८५ प्रतिशत ही सही, सही उपयोग हो जाय तो प्रान्त का काफी लाभ हो सकता है। अनुदान बढ़ाने के लिये आर्थिक कठिनाई जरूर है लेकिन जितना अनुदान मिलता है उतना भी अगर ठीक प्रकार से इस्तेमाल किया जाय तो बहुत कुछ काम हो सकता है।

**श्री उपाध्यक्ष**—माननीय मोहिले जी, आपको उसी समय में से ३ मिनट मैं दे रहा हूं।

***श्री बुलाकीराम** (जिला हरदोई)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि आज दो वर्ष हो गये मैं निरन्तर खड़ा होता हूं लेकिन आपने कभी मुझे बोलने का मौका आज तक नहीं दिया। इसलिये मैं आपकी पक्षपातपूर्ण नीति के विरोध में सदन का त्याग करता हूं।

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि चेयर के प्रति कुछ कहना मुनासिब नहीं है। वे सदन स्वयं ही छोड़ रहे हैं नहीं तो मैं उन्हें सदन से बाहर जाने को कहता। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि वे इन शब्दों को वापस लें।

**श्री बुलाकीराम**—मैं वापस लेता हूं।

**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। क्या माननीय सदस्य को यह अधिकार है कि चेयर के विरुद्ध इस प्रकार का आरोप लगायें?

(श्री बुलाकीराम सदन से चले गये।)

**श्री उपाध्यक्ष**—चूंकि उन्होंने वापस ले लिया इसलिये अब कोई प्रश्न नहीं उठता।

***श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे आपने समय दिया है इसलिये मैं आपका कृतज्ञ हूं। श्रीमन्, इस पी० डब्लू० डी० बजट पर मुझे कोई लम्बा चौड़ा व्याख्यान नहीं देना है क्योंकि मैं जानता हूं कि इस विभाग की बुराइयों के सम्बन्ध में हर शहर में जिक्र होता है। मैं तो आपको थोड़े से शब्दों में अपने यहां की बात बताना चाहता हूं। हमारे यहां पैन्टून ब्रिज है जिस पर प्रत्येक वर्ष लाखों रुपया व्यय होता है। वहां के नागरिकों ने सरकार को कई बार बताया कि उस पुल को अगर लोहे का बनवा दिया जाय तो बहुत सुन्दर होगा। जो घटना इस साल वहां घटी है उसका जिक्र न करके मैं इतना ही कहूंगा कि अगर वह पुल लोहे का बन गया होता तो सैकड़ों आदमियों की जान न गयी होती। इसके सम्बन्ध में मैंने प्रधान मंत्री से भी जिक्र किया और उन्होंने भी मेरी बात सुनी और मुझे आश्वासन दिया है कि पुल बनवाने में वह सहायक होंगे।

दूसरी बात यह है कि हमारे यहां अर्द्धकुम्भी आने वाली है और उसमें पी० डब्लू० डी० का प्रबन्ध रहता है। मैं आशा करूंगा कि जिस प्रकार से पिछली दफा प्रबन्ध किया गया था उस तरह से न करें और ठीक से प्रबन्ध करें क्योंकि उसमें बहुत घपला होता है और काफी डकैतियां होती हैं। इसलिये श्रीमन्, मैं चाहूंगा कि आने वाली अर्द्धकुम्भी में जनता का भी सहयोग लिया जाय।

***श्री चन्द्रसिंह रावत** (जिला गढ़वाल)—श्रीमन्, मैं समय के लिये प्रार्थना करना चाहता था क्योंकि हम लाचार हैं उपाध्यक्ष महोदय, और मैं समझता हूं कि...

**श्री उपाध्यक्ष**—मैं माननीय सदस्यों की सूचना के लिये बता दूं कि मेरे पास एक खाता है और इस बजट के बाद विवाद में श्री चन्द्र सिंह जी रावत दो मर्तबा हिस्सा ले चुके हैं और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बहुत से ऐसे सदस्य मौजूद हैं कि उन्होंने जबान तक नहीं खोली और सदस्य इस तरह से चेयर पर लांछन लगाते हैं। यह मुनासिब नहीं है कि किसी को मैं कृपा पात्र समझूं और किसी को नहीं।

**श्री रामकृष्ण सारस्वत** (जिला फर्रुखाबाद)––उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बजट सेशन में तथा पिछली दफा भी बोलने का अवसर नहीं मिला है।

**श्री उपाध्यक्ष**––मैं एक सदस्य को बुला चुका हूं कृपया उन्हें बोल लेने दीजिये।

**श्री चन्द्रसिंह रावत**––उपाध्यक्ष महोदय, यह आपकी कृपा है कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत से लोग पब्लिसिटी के लिये बोलते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम सदन में बोलते हैं तो मजबूर होकर बताना पड़ता है कि हमारे साथ पक्षपात किया जाता है, स्टेप सन जैसा व्यवहार हमारे साथ किया जाता है और हम मजबूरी से यहां पर बोलने के लिये खड़े होते हैं। मुझे कोई पब्लीसिटी का शौक नहीं है और न मुझे भाषण देने का ही शौक है।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि दो सड़कें पी० डब्लू० डी० के कंट्रोल में हैं––(१) बांघाट से पौड़ी तक, और (२) पौड़ी से देवप्रयाग तक। इन सड़कों के लिये दो साल हो गये हैं और हमने बराबर दरख्वास्तें कीं, खुशामदें कीं और १६ चिट्ठियां लिखीं और माननीय मिनिस्टर साहब पौड़ी तशरीफ ले गये थे तो हमने उनको दरख्वास्त दी और बंगले पर भी गया हूं लेकिन कोई नतीजा नहीं निकल सका है।

हमारी जनता ने श्रमदान किया और ६ फीट चौड़ी सड़क को कहीं १६ फ़ीट, कहीं २० फीट चौड़ी किया। पहाड़ तोड़े और मिट्टी काटी, हमारी माताओं और बहिनों ने श्रमदान किया और १७ मील लम्बी एक सड़क बनाई और १० मील लम्बी दूसरी बनाई। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार इस काम को संभालने के लिये तैयार नहीं है। इसके मुताल्लिक एक पत्र मैंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को लिखा कि इस पर गौर होना चाहिये। उन्होंने डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी को लिखा कि इस पर गौर होना चाहिये। डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी की चिट्ठी मिली कि पी० डब्लू० डी० मिनिस्टर साहब को लिख दिया गया है और वह इन सड़कों के लिये सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन आज तक इन दोनों सड़कों के लिये कोई प्राविजन नहीं किया गया है।

मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि मेरा जो क्षेत्र है वह डेफीसिट एरिया है जहां ६ मील के लिये खच्चर का ६ रुपया भाड़ा देना पड़ता है। इस महंगाई के जमाने में अनाज का हमारे यहां क्या भाव होगा इसका अन्दाजा लगाया जा सकता है। कोटद्वार से तीन पौने तीन रुपये ही लगते हैं और ६ रुपया इन स्थानों का किराया देना पड़ता है तो किस भाव से अनाज जनता को बेचा जाता है इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। यह हमारी मुसीबत है और हम समझते हैं कि अगर हमारी सरकार हमारा प्रबन्ध नहीं कर सकती है तो हम लोगों को छोड़ दे, हमको जवाब दे दे। बड़े अदब के साथ मैं दरख्वास्त करूंगा माननीय मंत्री जी से कि क्या कारण है कि उन लोगों के लिए कुछ व्यवस्था नहीं की जाती। ८०–८०, ७०–७० मील लोगों को खच्चर पर अनाज लाद कर ले जाना पड़ता है। २५–३० रुपया फी खच्चर का पड़ा। ऐसे स्थान की जनता जिसका तीन चौथाई शरीर नग्न है, उनके लिए मैंने दरख्वास्त की थी कि यहां सड़क होनी चाहिए। लेकिन सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। मुझे बड़ा दुख होता है। जिन सड़कों का कहीं कोई प्रश्न नहीं था रात को प्रपोजल होता है सुबह सड़क मंजूर हो जाती है। बजट मंजूर होता है पीछे और काम शुरू हो जाता है। रोलर चला कर मजबूत सड़क बनायी जाती है। क्या इसी तरीके से, इसी न्याय से हम इस उत्तर

[श्री चन्द्रसिंह रावत]

प्रदेश को विकास की मंजिल पर पहुंचानेवाले हैं। इसका मुझे महान् खेद है। हमारे देश में जितने पढ़े लिखे लोग हैं वह उतने ही बदतर और अन्याय करने वाले लोग हैं। इसका हमें बड़ा खेद है। (व्यवधान)

हम समझते हैं आपकी बात को और आपके पक्षपात को। हमें पता है आप बहुत न बोलिए। हम इस सदन में खुले आम बता देंगे कि आप किस तरह से चल रहे हैं। आप ईमानदारी का बरताव मुल्क के साथ नहीं करना चाहते हैं। आखिर इस मुल्क को अपने हाथ में क्यों लिया है, अगर आप से हुकूमत नहीं हो सकती, अगर आप से काम नहीं चल सकता तो आप हमारे गढ़वाल को छोड़ दीजिये। हम अपना इंतजाम खुद ब खुद कर सकते हैं। मैं निहायत अदब से दरख्वास्त करूंगा कि मेरी इस आवाज को नेहरू जी तक पहुंचाया जाय। हमें कई बार छुट्टी लेकर दिल्ली जाना पड़ता है नेहरू जी के पास, पानी के लिए, सड़क के लिए। हर किस्म की बात के लिए नेहरू जी को लिखना पड़ता है। इस लखनऊ की हुकूमत का क्या काम है? आखिर असेम्बली लखनऊ में है। एम० एल० ए० उसमें बैठते हैं और इस माननीय सदन से दरख्वास्त करते हैं, सरकार से दरख्वास्त करते हैं। यह सरकार किस लिए है? वरना इस सरकार से आप हमको अलग कर दीजिये। हम अपना इन्तजाम कर सकते हैं। हम मुसीबतों में रहना पसन्द करेंगे।

**श्री अयोध्याप्रसाद आर्य** (जिला देवरिया)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप का हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण अनुदान पर मुझे आपने बोलने का अवसर दिया है। श्रीमन्, जनपद देवरिया उत्तर प्रदेश का सब से पिछड़ा हुआ जनपद है। उसमें सलेमपुर पूर्वी जो हमारा क्षेत्र है, वह जिले में सबसे पिछड़ा हुआ है। यहां पर चारों तरफ से नदियां नाले अधिक होने के कारण गमनागमन एवं आदान-प्रदान आदि की सुविधाएं नष्ट हैं। श्रीमन्, सलेमपुर के पास ही नदावरघाट जो छोटी गंडक पर है, वहां पर पुल न होने से वहां का मार्ग अवरुद्ध हो गया है। कई वर्ष पहले सिंचाई विभाग की तरफ से उसका निर्माण हुआ था लेकिन बरसात के दिनों में उस पुल के ऊपर से पानी बहता है, और जो खम्भे लगे हुए हैं उसके दोनों तरफ बरसात के दिनों में मिट्टी कट जाने से प्रतिवर्ष सरकार का ५ हजार या १० हजार रुपया व्यय होता है। श्रीमन्, उन स्थानों पर मैं चाहता हूं कि आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करूं। वह हमारे पिछड़े क्षेत्र की तरफ ध्यान दें क्योंकि हमारी सरकार की यह नीति है। शहरों की ओर से हमें गांवों के विकास की तरफ जाना भी है और हमारा क्षेत्र ऐसा है जहां पर सड़कों के न होने की वजह से, नदी-नालों पर आवश्यक पुल, पुलिया न होने की वजह से गमनागमन एवं आदान प्रदान रुका हुआ है। बरसात के दिनों में अगर वहां सड़कें होतीं तो किसानों का माल तेज बिकता लेकिन सड़क न होने की वजह से वह सस्ता बिकता है। बरसात में वहां कभी कभी सामुद्रिक दृश्य उपस्थित हो जाता है। मैंने तो देखा कि जहां खाद्य संकट पड़ा हुआ था वहां हमारी सरकार की तरफ से कई एक स्थानों पर सस्ते गल्ले की दूकानें होते हुए भी नदी के उतार चढ़ाव की वजह से उन स्थानों पर हम गल्ला न पहुंचा सके जिससे हमारे क्षेत्र के रहने वाले व्यक्तियों को बहुत कष्ट हुआ। इसलिए मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा अपने चुनाव क्षेत्र के कुछ स्थानों का जिक्र करना चाहता हूं जहां कुछ सड़कों और कुछ पुलों की आवश्यकता है। आशा है कि इस योजना में या अगली योजना में उसको वह सम्मिलित करने की कृपा करेंगे ताकि वह हमारे पिछड़े हुए क्षेत्र आगे बढ़ सकें। श्रीमन्, नदावरघाट पुल ऐसा होना चाहिए जहां कि सिंचाई विभाग की ओर से जो पुल बना हुआ है उसके अन्दर कुछ थोड़े से खम्भे बढ़ा दिये जायं और कुछ थोड़ा सा ऊंचा कर दिया जाय तो उससे बहुत काफी लाभ हो सकता है। वह एक अन्तर्प्रान्तीय मार्ग है। वहां से बिहार और बंगाल आदि का मार्ग खुला हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूं कि नदावरघाट पुल का निर्माण करा दिया जाय। इसके साथ ही साथ श्रीमन्,

एक भटनीघाट पर पुल होना चाहिए। उधर का जो हमारा क्षेत्र है उसको वहां के निवासी नोआखाली कहते हैं क्योंकि विकास का कोई कार्य वहां आज तक नहीं हुआ है। छाया ब्लाक भी खुला हुआ है, लेकिन वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ है। खैराट के पास एक पुल की बहुत ही आवश्यकता है। सिआही पर एक पुल की आवश्यकता है। मैं उधर आपका ध्यान आकर्षित करूं कि वहां पुल न होने की वजह से दिन दहाड़े चोरियां और डकैतियां होती हैं जिससे वहां के लोगों को बहुत कष्ट पहुंचता है।

अब मैं कुछ सड़कों के बनवाने की तरफ आपके द्वारा माननीय मन्त्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सलेमपुर से मझौली ३ मील सड़क है, मझौली से बहियारी-सोहनपुर-रामपुर बुजुर्ग होते हुए बिहार सीमा तक लगभग १० मील की सड़क है, तीसरी सड़क भटनी से रामपुर खोरीबारी घाटी होते हुए भिगारी बाजार की है। श्रीमन्, चौथी सड़क भिगारी से भवानी छापर की है। एक और निवेदन करूं कि सोहनपार से टीकमपार होते हुए रामपुर मिल तक की सड़क। श्रीमन्, इनके लिए मैं आपसे इसलिए विशेष करके आग्रह करता हूं कि यह क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, बहुत बैकवर्ड है। इसलिए मैं आपसे बहुत विनम्र शब्दों में कहता हूं कि इधर आप ध्यान दें ताकि कुछ इनका कल्याण हो। सड़कों के न होने की वजह से सरकारी या गैरसरकारी व्यक्तियों को वहां पहुंचने में बड़ी कठिनाई होती है। इस वजह से वहां का कार्य रुका हुआ है।

**श्री उपाध्यक्ष**––श्री ऊदल। माननीय सदस्य अब दो दो, तीन तीन मिनट वक्त लें तो ज्यादा अच्छा है।

***श्री ऊदल** (जिला वाराणसी)––माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज माननीय मंत्री जी ने जो ग्रान्ट पेश की है मैं उसके सम्बन्ध में जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मैं एक बात जरूर कहता हूं जैसा कि माननीय मन्त्री जी ने गिनाया इस विभाग ने बहुत अच्छे काम भी किये हैं। उनमें से मैंने २, ३ को देखा है। चोपन और कर्मनासा का पुल के लिये बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी बहुत से काम हो रहे हैं और कुछ कामों की योजना मन्त्री जी को स्थगित करनी पड़ी है। मैं इस बात को मानता हूं कि माननीय मन्त्री का विभाग बहुत गरीब है और वह स्वयं भी गरीब हैं लेकिन उनको कैबिनेट से रुपया और लेने के लिये लड़ना चाहिये क्योंकि इस विभाग की पूरी जिम्मेदारी उनके ऊपर हैं।

मैं आपके जरिये से यह निवेदन करना चाहता हूं कि चोपन और कर्मनासा पुलों को बनाकर बिहार से जोड़ा गया है यह तो ठीक है लेकिन इक्का और रिक्शावालों पर वहां टैक्स लगा दिया गया है। मेरी गुजारिश यह है कि इन इक्केवालों और रिक्शावालों पर टैक्स नहीं लगना चाहिये और यह टैक्स उनके लिये माफ होना चाहिये।

माननीय मन्त्री जी ने बनारस के घाटों का जिक्र किया। शीतलाघाट पर लाखों रुपया खर्च किया गया। वहां पर पत्थर की पट्टियां लगा दी गई हैं। दशाश्वमेधघाट ढाई वर्ष से बन रहा है और उसके ऊपर लाखों रुपया खर्च हो रहा है। उसमें जितनी प्रगति होनी चाहिये वह नहीं हो रही है। जैन घाट आधा टूट गया और आधा भी टूटने वाला है। उसकी तरफ ध्यान दिया जाना चाहिये।

अब मैं कर्मचारियों के बारे में थोड़ा निवेदन कर दूं। आप देखेंगे कि पूर्व में ३५ रुपया मेट को दिया जाता है, ३० रुपया बेलदार को और २५ रुपया कुली को मिलता है लेकिन पश्चिम

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री ऊदल]

में ४५ रुपया मेट को और ३५ रुपया बेलदार को और ३० रुपया कुली को दिया जाता है। यह असमानता दूर होनी चाहिये। जो कर्मचारी दिन रात काम करते हैं उनको बरसात के दिनों में छाता मिलना चाहिये और मेट को साइकिल अलाउन्स मिलना चाहिये।

सड़क के बारे में निवेदन यह करना चाहता हूं कि पंचक्रोशी सड़क अच्छी बननी चाहिये। उस पर देश-विदेश के लोग आते हैं। तमाचाबाग से बड़ागांव की सड़क बनाई जाय। बाबतपुर से जमालपुर और भोजूवीर से केराकत सड़क बननी चाहिये। इनके लिये मन्त्री जी से मैंने पहले निवेदन किया था।

श्री उग्रसेन---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री जी के अनुदान पर जो कटौती का प्रस्ताव है उसके समर्थन में एक-दो निवेदन करना चाहता हूं। पहला निवेदन यह है कि जो सड़क प्लानिंग विभाग से बनती हैं उन सड़कों का कोई पुरसांहाल नहीं है। मेरा निवेदन यह है कि अगर सही मायने में माननीय मन्त्री का विभाग कोई सड़कों के माइलेज में वृद्धि करना चाहता है तो जिन सड़कों को विकास विभाग ने बनाया है, वे बिलकुल बरबाद हो रही हैं, उनको जो कुछ कायदे कानून हों, उनके अनुसार पी० डब्ल्यू० डी० को ट्रान्सफर करना चाहिये। अगर पी० डब्ल्यू० डी० इनको ले ले तो वह विभाग इन सड़कों के माइलेज में वृद्धि कर सकता है। उसमें नेशनल हाई वे और दूसरी सड़कों के माइलेज में बढ़ोत्तरी हो सकती है।

दूसरी बात यह है कि मुझे माननीय मन्त्री जी के विभाग के नाम से एतराज है। सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम से पता नहीं चलता कि कौन-सी सड़क, कहां किसने मरम्मत की। उदाहरण देना चाहता हूं कि इसी पुस्तक में दिया हुआ है कि १९५५-५६ में ९,२३७ मील, १९५६-५७ में १०,५५५ मील और १९५७-५८ में १०,९३६ मील सड़कें बनीं। अगर औसत लगाया जाय तो पी० डब्ल्यू० डी० ने करोड़ों रुपया खर्च करके एक जिले में ३।। मील और अधिक से अधिक ३।।। मील के लगभग औसत आता है।

इस संबंध में एक निवेदन करना चाहता हूं। आप जानते हैं कि पूर्वी जिले भुखमरी के जिले हैं जहां ३०० आदमी भूखे मर गये और कोई पुरसांहाल नहीं। एक स्कीम थी पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा पूर्वी जिलों में कुछ सड़कों के निर्माण की जिससे वहां के लोगों को रोजी और रोटी मिलेगी। श्रीमन्, मेरा एतराज है कि इस विभाग ने जो वायदा किया था पंचवर्षीय योजना में सड़क बनाने का और जो इस विभाग द्वारा बांटी गयी पुस्तिका के पन्ने ५८ पर १२ मील की सड़क बरहज से लार रोड तक दी हुई है उस पर मिट्टी भी नहीं पड़ी। पारसाल इंजीनियरों ने कुछ ठेका दिया था, उसके लिये बोली भी हो गयी, लेकिन काम नहीं शुरू हुआ और पी० डब्ल्यू० डी० द्वारा जितनी सड़कें पूर्वी जिलों में बनायी जाने वाली हैं उन पर काम नहीं शुरू हुआ। मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी जल्दी से जल्दी इस काम को शुरू करायें।

इसके अलावा राप्ती और घाघरा पर पुल बनाने का भी प्रस्ताव है। दो, तीन साल से छानबीन चल रही है। मेरा निवेदन है कि कहीं यह टाल न दिया जाय। पूर्वी जिले गरीब हैं और उनकी गरीबी का खयाल रखते हुए इस बात की आप जांच करायें कि जिन योजनाओं को पी० डब्ल्यू० डी० ने लिया था उनको पूरा क्यों नहीं किया और इसके लिये जो जिम्मेदार हैं उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये, यही मेरा मंत्री जी से निवेदन है।

श्री कन्हैयालाल वाल्मीकि (जिला हरदोई)---माननीय उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत अनुदान पर मैं माननीय निर्माण मंत्री जी को अपने जिले की बाबत सुझाव देने की कोशिश करूंगा। मेरे जिले की एक माननीया सदस्या श्रीमती विद्यावती वाजपेयी जी ने कुछ सड़कों की बाबत कहा। उन्होंने शाहाबाद से सिरोमन नगर व शाहाबाद से पिहानी की सड़कों की बात कही जो सही है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सन् १९५१ में जब हम एलेक्शन के दौरान में शाहाबाद की तरफ गये थे तो शाहाबाद और पाली मार्ग के लिये

वहां के नागरिक ने हजारहों की संख्या में यह मांग की थी कि वाल्मीकि जी, अगर आप विधान सभा के सदस्य हो जायं तो विधान सभा में यह आवाज जरूर उठाइयेगा । मेरा अपना खयाल है कि इस मांग को हम बराबर माननीय निर्माण मंत्री जी के पास पहुंचाते आ रहे हैं । कई बार मेरे हरदोई जिले के और विधान सभा के कई माननीय सदस्यों ने भी मिल कर उनकी सेवा में प्रार्थना की । इस सड़क के न बनने का कोई भी कारण हो, वह तो माननीय मंत्री जी स्वयं जानते होंगे लेकिन मैं उनकी सेवा में यह प्रार्थना आवश्य करूंगा कि भविष्य में या इसी वर्ष जो स्कीम वहां की सड़कों के लिये है, उसमें शाहाबाद-पाली सड़क को प्राथमिकता देने की अवश्य कृपा करें ।

दूसरी बात यह कि पिहानी के पास एक चपरतला रोड है । कई वर्षों से उसका काम चल रहा है । वह केवल ९ मील की सड़क है और आज भी अधूरी पड़ी है और इसमें ३ मील का टुकड़ा ऐसा है कि जो छआ तक नहीं गया, बिलकुल छोड़ दिया गया है । यह ऐसी चीज है कि जो सरकारी आलोचना करने वालों को प्रोत्साहन देती है । इस पर मंत्री जी को अवश्य ध्यान देना चाहिये ।

तीसरी बात यह कि पाली कस्बे में हम लोगों ने बड़ी-बड़ी मीटिंगें कीं तो कई बार हमको शाहजहांपुर होकर जाना पड़ा । बरसात में गर्रा नदी के बढ़ जाने से वहां गर्रा नदी पर पुल बनाने के लिये भी लोगों ने काफी मांग की है । सुकेता नाले पर भी पुल बनाने के लिये वहां के नागरिकों ने काफी मांग की । बरसात में यह नाला शाहपुर भिगावां के पास ऐसा उमड़ आता है कि सैकड़ों गांवों का कटाव हो जाता है और अगर कोई दुर्घटना हो जाय तो थाने में रिपोर्ट देने के लिये या शहर में आकर बात करने के लिये वे लोग असमर्थ रहते हैं और अगर उस नाले को घड़ों पर बैठकर पार करने की कोशिश करते हैं तो कई बार ऐसा मौका हुआ कि कुछ लोग उसमें डूब गये । तो मैं आपके द्वारा निर्माण मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि वर्मा जी ने जो कहा है हरदोई जिले के बारे में और जो दो, तीन पुलों की स्कीम है उसके लिये मैं उनका शुक्रिया अदा करूंगा, लेकिन जो बातें मैंने आपके द्वारा उनके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है उन पर वे अवश्य विचार करने की कृपा करें ।

**श्री उपाध्यक्ष**—(कुंवर श्रीपाल सिंह से) आप ५ मिनट का समय लें ।

**श्री गोविन्द सिंह बिष्ट** (जिला अल्मोड़ा)—उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी तो शायद ज्यादा समय नहीं लेंगे । अभी और भी सदस्य बोल सकते हैं ।

**श्री उपाध्यक्ष**—कल भी यही विषय चलेगा, आप कल बोल लीजियेगा ।

**कुंवर श्रीपाल सिंह**—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो कुछ निवेदन करना था उसका अधिक भाग सुबह ही निकल गया है और जो थोड़ी-सी बातें उस समय रह गई थी उन्हीं को कहना चाहूंगा । श्रीमन्, हमारी सरकार इस विभाग की तरफ क्यों नहीं ध्यान देती है, इसका एक मात्र कारण जो हमारी समझ में आता है वह यह है कि इस विभाग से सरकार को नफा नहीं है । इस सरकार को अब सरकार कहना भी अनुचित है । इसको अब दुकानदार ही कहना चाहिये जैसे दुकान लगी हुई है, पचासों किस्म की चीजें रखी हुई हैं, वह बिक रही हैं और खरीदी जा रही हैं लेकिन जनता के लिये जिसके लिये सरकार बनी है उसकी तरफ जो भी विभाग ध्यान देने वाला है, उस ओर सरकार का ध्यान नहीं है । रोडवेज को देखिये, उसमें बढ़ोत्तरी होगी, नहरों और नलकूपों में बढ़ोत्तरी होगी, जहां सरकार को पैसा मिलता है वहां पर ज्यादा खर्च किया जायगा मगर सड़कों पर जिसके जरिये

[कुंवर श्रीपाल सिंह]

से जनता को लाभ होता है सरकार का कोई ध्यान नहीं है । अगर एक हजार मील एक सड़क बना दी जाय तो जनता की आय १० करोड़ रुपये बढ़ जाती है मुख्तलिफ तरीकों से । जैसे कोई सामान शहर में ४ पैसे का मिलता है उसका भाव देहात में बढ़ जाता है इसलिये अगर देहातों में पहुंचने के लिये अच्छे रास्ते हों तो वहां भी दाम कम हो सकते हैं । इन तरीकों से अगर देखा जाय जिससे जनता को लाभ पहुंचता है, सरकार का कतई कोई ध्यान नहीं है । मैं मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके लिये लड़ें और प्रयत्न करें, हम लोग भी पूरी तरह से उनके साथ हैं और वे अपने सड़क के विभाग के लिये अधिक से अधिक जितना ले सकें लें और उसको सड़कों पर खर्च करें ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उधर से एक माननीय सदस्य ने, नाम मैं भूल गया हूं, उन्होंने अपनी स्पीच में बताया कि सड़कें जो बनी हैं वे गांव में से ही होकर जाती हैं । तो मेरा खयाल है कि शायद उनका गांव रायबरेली से इलाहाबाद जाने वाली रोड पर होगा तभी उनको यह सूझा होगा । मैं यह निवेदन कर सकता हूं कि सावन के महीने में जो अंधा होता है उसको हमेशा हरियाली ही नजर आती है ।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुये ।)

मैं एक चीज और निवेदन करना चाहता हूं कि यदि उनका इसी प्रकार का कार्य रहा तो बहुत जल्द उन्हें कोई न कोई विभूषण रूपी आभूषण से भूषित जरूर कर दिया जायेगा । रायबहादुर का टाइटिल तो मिल नहीं सकता क्योंकि वह खत्म हो गया है । इसके अतिरिक्त मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मिस्टर राय द्वारा लिखित अभिमन्यु नाटक है उसमें रायबहादुर से अगर उनकी उपमा दी जाय तो अतिशयोक्ति नहीं होगी । उन राय बहादुर साहब ने स्पष्ट कहा है कि अगर महाराज दिन को रात कहें तो चांद और तारे चमका दूं और अगर रात को दिन कहें तो सूरज दिखला दूं । माननीय सदस्य उसी में के हैं । उनका काम हां में हां मिलाना है । वरना जितने सदस्य, चाहे इधर के या उधर के बोले उन्होंने एक स्वर से कहा कि सरकार का ध्यान सड़कों की ओर नहीं है । मैं उन सब सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने हिम्मत करके या हृदय की प्रेरणा से सत्य को सामने रखा और उनका भी आभारी हूं जो डर के मारे दूसरी चीज कह गये । अन्त में मैं मन्त्री जी का आभार प्रकट करता हूं लेकिन उसे अभी रिजर्व में रख रहा हूं और अगर मन्त्री जी इन बातों को देखकर सड़कों पर थोड़ा-सा ध्यान देंगे, उन सड़कों पर जो आज बिल्कुल वैसी पड़ी हुई हैं या जो डिस्ट्रिक्ट बोर्डों के जिम्मे पड़ी हैं, अगर उनको लेने की कृपा करेंगे तो मैं बासूद अपना आभार उनके लिये प्रकट करूंगा ।

**श्री गिरधारीलाल**---अध्यक्ष महोदय, मैं पूरे सदन का और अपने दोस्त कुंवर श्रीपालसिंह जी का आभारी हूं कि उन्होंने मेरा ध्यान इस विभाग की खामियों की ओर खींचा है और सुझाव दिये हैं ।

अलग-अलग जिलों की बहुत-सी सड़कों की मांगें रखी गईं जो मैंने और मेरे साथी कर्मचारियों ने नोट कर ली है । उनमें जो-जो इस प्लान में होंगी जो इन २ वर्षों में खत्म होने जा रहा है, इसमें बनेंगी, नहीं तो तीसरे प्लान में उन पर जरूर विचार किया जायगा ।

डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की २,५०० मील सड़कें इस विभाग ने ली हैं और इस योजना के अन्तर्गत ३२४ मील सड़कें और ली जा रही हैं । अभी एक दोस्त ने कहा था कि डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और श्रमदान की सड़कें ५६,००० मील होती हैं । आजकल के समय में इसके लिये २ अरब रुपया चाहिये ।

**एक सदस्य**---४०,००० मील कहा था ।

**श्री गिरधारीलाल**--४०,००० मील के लिये भी २ अरब नहीं तो पौने दो अरब रुपया चाहिये। हमारी शक्ति इतनी न होने से प्रायोरिटी का प्रश्न आ जाता है।

मुझे खेद है कि यह भी कहा गया कि हमारे प्रान्त में अनियोजित ढंग से काम हो रहा है। मैं किसी दूसरे विभाग के बारे में तो नहीं कहना चाहता हूं परन्तु इस विभाग के लिये कह सकता हूं कि जितना यहां नियोजित ढंग से काम हो रहा है उतना कहीं नहीं हो रहा है। यह प्लानिंग का युग है लेकिन इस विभाग में पहले भी प्लान से ही काम होता था, सड़कों का अन्दाजा लिया जाता था, सर्वे होता था, डिटेल्ड सर्वे होता था, फिर वह ऊपर से मंजूर होता था। एक साहेब ने कहा कि हमारे बजट का सिस्टम गलत है, इसलिये उसमें देर लगती थी। ऐसी बात भी नहीं है।

शहर और गांव का सवाल उठाया गया। मैं अपने मित्रों को बता देना चाहता हूं कि इस विभाग में ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। अगर एक सड़क हमने यहां से सीतापुर तक बनाई तो क्या रास्ते के गांवों को छोड़कर वह सड़क आसमान से थोड़े ही जायेगी। दूरी के गांवों के लिये फीडर रोड और लिन्क रोड बनती हैं और बनेंगी। अगर हमारे जरिये से नहीं तो गांव पंचायत के जरिये से, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के या अन्तरिम जिला परिषद् के जरिये से बनेंगी। यह सब बात शक्ति पर निर्भर करती है। अगर डेढ़ या दो अरब रुपया हो तो मैं समझता हूं कि ४०, ५० हजार मील लम्बी सड़कें हम दे देंगे। लेकिन फिर भी सड़कों की मांग और बढ़ेगी। यातायात की समस्या हमारी तरक्की की सूचक है। तो जितना हम आगे बढ़ेंगे उतनी ही हमारी उन चीजों की मांग बढ़ जायगी। मेरी इच्छा है और मैं समझता हूं कि जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनायी जायं लेकिन यह सब धन की उपलब्धि के ऊपर निर्भर करता है।

लैप्सेज के बारे में एक बात कही गयी। जहां तक सड़कों का संबंध है, कोई अधिक रुपया लैप्स नहीं होता है। कम से कम दो वर्षों से तो मैं जानता हूं कोई अधिक रुपया लैप्स नहीं हुआ है। पहले वर्ष जो सड़क रखी जाती है, उस वर्ष उसका सर्वे होता है, डिटेल्ड ऐस्टीमेट्स तैयार किये जाते हैं, फिर उसका एप्रूवल होता है, इसमें काफी समय लग जाता है। फिर जाकर सड़क पर काम शुरू होता है। कभी-कभी गलती से किसी सड़क के लिये ज्यादा रुपया रख दिया जाता है जो उस पर खर्च नहीं हो पाता। तो यह उसको बचाने की बात नहीं, बहुत सी ऐसी सड़कें भी होती हैं जिन पर ज्यादा रुपया भी खर्च हो जाता है। इसलिये ऐसी बात नहीं है कि बचत के खयाल से उसको बचा लिया जाता है।

यह भी कहा गया कि कामों में देरी होती है। प्रतापसिंह जी ने कहा कि बहुत देरी लग जाती है। जैसा कि मैंने अभी बताया कि पहले तो हम नक्शा देखते हैं, फिर सर्वे होता है, उसमें भी काफी पैसा खर्च होता है। उसके लिये अन्दाज के तौर पर प्रतीक ग्रान्ट हम रख देते हैं। इसके बाद डिटेल्ड ऐस्टीमेट तैयार किये जाते हैं, सर्वे होती है, फिर उसका ऐडमिनिस्ट्रेटिव एप्रूवल होता है। इसमें अक्सर ६-७ महीने लग जाते हैं। उसके बाद काम शुरू होता है और फिर जारी ही रहता है।

इस सिलसिले में मैं ज्यादा न कह कर एक बात यह बता देना चाहता हूं कि सरकार का ध्यान पिछड़े हुये इलाकों की तरफ विशेष रूप से है। सड़कों की बात ही नहीं, सरकार हर तरीके से पिछड़े हुये इलाकों की जनता की सेवा करना चाहती है, और आगे बढ़े हुये इलाकों के बराबर उनको लाना चाहती है और सब काम वहां पर किये जा रहे हैं। सड़कों की भी यही बात है। मेरी खुद ख्वाहिश है कि वहां सड़कें बनें। चकरौता की तरफ आप चले जाइये, वहां सड़कों की बहुत ज्यादा जरूरत है। वहां के रहन-सहन, खाने-पीने और बोलचाल में आपको

[श्री गिरधारी लाल]

बहुत फर्क मिलेगा और उसको देखकर आप कहेंगे कि यहां की आवश्यकतायें बहुत ज्यादा हैं लेकिन जैसा मैंने कहा यह सब चीज धन की उपलब्धि पर निर्भर करती है । लेकिन थोड़ा-बहुत उन पिछड़े इलाकों में भी काम हुआ है ।

लखनऊ शहर की बाबत भी बहुत कुछ कहा गया है। कौंसिल हाउस क सिलसिले म जो कुछ कहा गया उसके बारे में सदस्यों की इत्तला के लिये मैं यह बता देना चाहता हूं। अव्वल तो यहां के कौंसिल हाउस के सिलसिले में जो कुछ भी आपने इस बजट साहित्य में देखा उसका सम्बन्ध हमारी सरकार से और केन्द्रीय सरकार से है । हमारे मुल्क से एक डेलिगेशन बाहर के मुल्कों में गया जिसने समाजवादी देशों को भी देखा और दूसरे मुल्कों को भी देखा और वहां के जितने गवर्नमेंट हाउस तथा कौंसिल हाउस हैं उन सबको देखा। वहां पर जो पेंटिंग और स्टेच्यू आदि को उन लोगों ने देखा उससे उस मुल्क की आजादी की पूरी हिस्ट्री जाहिर होती थी। उन तस्वीरों और पेंटिंग को देखने के बाद जो हमारा पार्लियामेंट हाउस व कौंसिल हाउस है, उसके सिलसिले में केन्द्रीय सरकार ने सारे स्टेटों को उस डेलिगेशन की सिफारिश के बारे में लिखा कि हम इस चीज को करना चाहते हैं। तो उसको मान कर उसी के हिसाब से यहां काम किया जा रहा है। मैं समझता हूं कि जहां हमारे प्रदेश का एक डेढ़ अरब रुपये का बजट हो वहां ५,६ लाख रुपया इस काम के लिये भी खर्च कर दिया जाय तो उसका बजट पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा और इतना पैसा हमारे इस सदन को हर हालत में खुशी से मंजूर करना चाहिये।

इसी तरह से लखनऊ की एक छोटी सी सड़क के बारे में जिक्र किया गया जिसको बनाया जा रहा है । मैं समझता हूं कि इस पर कोई ज्यादा खर्च नहीं है और इस छोटी सी सड़क को बना देने से अगर वहां के रहने वालों को ज्यादा सहूलियत हो जाती है तो उस पर भी इस सदन के किसी सदस्य को एतराज नहीं होना चाहिये ।

श्री प्रताप सिंह---५० लाख की कटौती के बारे में भी कहें ।

श्री गिरधारी लाल---जहां तक ५० लाख की कटौती की बात है, इसमें भी मैं समझता हूं कि थोड़ी-सी गलतफहमी है । बात यह है कि जिस वक्त प्लान बना तो कुछ काम को आगे बढ़ाने के लिये यह तय हुआ कि हर विभाग में कुछ न कुछ कटौती करनी होगी और इस विभाग के लिये भी प्लानिंग विभाग की तरफ से लिख कर आया कि आपको भी कुछ खर्च कम करना होगा । हर विभाग में खर्च कम करने की बात थी, कोई इसी विभाग के लिये यह बात नहीं थी । अन्त में यह तय हुआ कि इस विभाग को ५० लाख रुपया खर्च कम करना होगा, लिहाजा इस विभाग के बजट में से इतना रुपया कम हो गया । इस पर काफी एतराज भी हुआ और कन्द्रीय सरकार से काफी लिखा-पढ़ी और तमाम कोशिशों के बाद इसका बहुत कुछ अंश रुपया रिस्टोर हुआ । इस तरह से दो तीन महीने की देर इस वजह से हो गई लेकिन रुपया कटा नहीं। फिर भी, इसकी वजह से काम में कुछ रुकावट तो पड़ ही गयी । वैसे यह बात ठीक नहीं है कि ५० लाख की कटौती इस विभाग में हो गयी ।

माननीय ऊदल जी ने पुलों के ऊपर टौल टैक्स की बात कही कि वह नहीं लगना चाहिये। लेकिन वे जिस दल के हैं, जिस दल से सम्बन्ध रखते हैं, उस दल को तो विशेषरूप से इस बात का पोषक होना चाहिये कि अप्रत्यक्ष कर लेने के बजाय टोल टैक्स वगैरह जो प्रत्यक्ष कर है उसको वसूल करना चाहिये और अपने काम को आगे बढ़ाना चाहिये। तो इसमें भी कोई एतराज की बात नहीं है ।

श्री ऊदल---मैंने इक्के पर टैक्स न लगाने की बात कही थी ।

श्री गिरधारीलाल---शुरू में हर एक पर चाहे वह पैदल वाला हो या साइकिल वाला हो, चाहे रिक्शे वाला, इक्के वाला या मोटर वाला हो, सब के ऊपर ही टोल टैक्स लगता था, लेकिन बाद में बहुत सोच समझ कर यह तय हुआ कि पैदल और साइकिल वालों को इस टैक्स से मुस्तसना

कर देना चाहिये, लेकिन बाकी जितने भी हैं जो रिक्शे वगैरह चलाते हैं और उससे पैसा कमा रहे ह, अगर वे दो चार पैसे दे दें तो इसमें कोई एतराज नहीं होना चाहिये और यह उनके लिये कोई मुश्किल बात नहीं होगी ।

एक बात यह कही गयी कि काम करने का जो तरीका है उसमें परिवर्तन होना चाहिये । जो आजकल टेंडर वगैरह मांगे जाते हैं और दिये जाते हैं और फिर ठेकेदारों को काम दिया जाता है तो ठेकेदारों को काम देने के बजाय सरकार को चाहिये कि वह कोआपरेटिव सोसाइटीज बनायें या सरकार खुद उन कामों को करे । मुझे थोड़ा सा तजुर्बा भी है । आज से १५, २० साल पहले मैंने कुछ कोआपरेटिव सोसाइटीज का अनुभव किया है और आजकल भी बहुत-सी बातें सुन रहा हूं । उन तमाम बातों को देखते हुये, मुझे खास लगाव है कोआपरेशन से, इसलिये मैं यह नहीं चाहता कि उस काम को इतनी छूट दे दूं कि वह काम फल को बदनाम होने लगे । मैंने सरकारी कर्मचारियों को इस बात की हिदायतें दी हैं कि थोड़ी सोसाइटीज बनें, थोड़ा-सा उनको काम दिया जाय लेकिन पूरे तौर पर वह काम सफल होना चाहिये । जब काम सफल होगा काम और आगे बढ़ेगा । २,००० रु० तक के काम कुछ इलाकों में कोआपरेटिव सोसाइटीज को दे देने की हिदायत है लेकिन वे सोसाइटीज जेनुइन होनी चाहिये । मैं नहीं कहना चाहता, हमारे तमाम सदस्य जानते हैं आजकल कोआपरेटिव सोसाइटीज के नाम से बहुत-सी गड़बड़ियां होती हैं जिससे हमारे कोआपरेशन मूवमेंट की बदनामी होती है । तो मेरी इच्छा है कि कोआपरेटिव सफल हो और वह उसी वक्त होगा जैसा कि वातावरण है उसके माफिक हम जितना उपयुक्त समझें उतना उसको हम आगे बढ़ाते हुये चलें ।

सरकारी इंतजाम के सिलसिले में कहा गया कि कांट्रेक्ट सिस्टम हटाकर सरकारी तौर पर काम किया जाय । मैंने इस पर विचार किया है और कहीं पहले किसी दूसरे विभाग में इसका तजुर्बा भी किया है । मैं समझता हूं कि वह तरीका आज की वर्तमान स्थिति में सस्ता तरीका नहीं पड़ेगा । हमारे टैक्स पेयर का पैसा गलत तरीके से खर्च होने का खतरा है । इसलिये इन तमाम बातों को देखते हुये जो लेसर इविल समझा गया वही किया जा रहा है ।

करप्शन को बाबत कहा गया है । मैं दो बातें इस सिलसिले में कहना चाहता हूं । पहली बात तो यह है कि इस वक्त मैं समझता हूं कि जहां तक सार्वजनिक निर्माण विभाग का सम्बन्ध है पहले के मुकाबले दिन पर दिन इस विभाग के अन्दर काफी ऐफीशियेंसी आयी है, करप्शन भी कम हुआ है । वैसे ब्लैक शीप्स हर जगह होती हैं फिर आजकल का जैसा समाज है उसमें यह नहीं कहा जा सकता कि करप्शन नहीं होगा । लेकिन, फिर भी मैं बतलाऊं यह बहुत कुछ कंट्रोल में है । साथ ही आपने जैसा अनुपूरक मांग में पास किया था एक टेक्निकल सेल बनाने का विचार है जो कि गवर्नमेंट के लेविल पर रहेगा वह प्रान्त भर के तमाम कामों को देखेगा, तमाम हिसाब एकाउन्टिंग वगैरह पर चेक रहेगा और भी जो गड़बड़ियां होती हों उन पर उसका चेक रहेगा। मैं समझता हूं उससे और भी ज्यादा अच्छा नियंत्रण होगा और हम आशा करते हैं कि उससे हम करप्शन के दूर करने में भी सफल होंगे ।

मैंने जैसा शुरू में कहा, जहां तक अलग-अलग सड़कों की बातें कही गईं वे नोट कर ली गई हैं और उनके अलावा जो और बहुत सी खामियां है उसके ऊपर सरकार विचार करेगी ।

लेबर के सिलसिले में कुछ कहा गया कि पूर्व में कुछ और रेट्स हैं और पश्चिम में कुछ और हैं । जैसे मार्केट्स में अलग-अलग प्राइसेज होती हैं जो इंडेक्स आफ लिविंग होता है, उसी तरह से वहां के वेजेज की रेट्स उसी हिसाब से अलग-अलग स्थान पर अलग-अलग मजदूरों को गैंगों में दी जाती है । पूरब में कुछ कम है, पश्चिम में कुछ ज्यादा हैं । जहां तक यह है कि

[श्री गिरधारी लाल]

उनको वेतन देर से मिलता है, इस प्रश्न को मैं दखूंगा और देखकर मालूम करूंगा कि इसका खास कारण क्या है । मैं समझता हूं कि इतनी देर में नहीं मिलना चाहिये । कोई इलाज निकाला जाना चाहिये ।

एक बात और कही गई, समाजवाद और हमारे नेशनल स्टेडियम और काउन्सिल हाउस का संबंध जोड़ा गया । मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इसमें कौन-सा काम व्यक्तिगत रूप से हो रहा है । काउन्सिल हाउस है, ज्यों-ज्यों समाजवाद की ओर हम बढ़ेंगे जो मजदूर हैं वे मालिक बनेंगे । हमारा स्टेडियम जो बन रहा है, बजाय इसके कि कोई मिल मालिक अपने कंपाउंड के अन्दर स्टेडियम बनाता और उसके बच्चे कहते कि हम मालिक हैं, कौन घुसे और कौन न घुसे यह उस पर निर्भर करता है, हमने स्पोर्टस् स्टेडियम टैक्सपेयर के पैसे से लखनऊ में बनवा दिया जिसमें हर कारीगर को हर खेतिहर मजदूर को कहने का हक है कि बड़े-बड़ों का और मालदारों का जितना हक है उतना ही मेरा है । यह सोशलिज्म नहीं तो क्या है ? मेरी समझ में यह बात नहीं आई ।

यहां पर हमारे अलग-अलग साथी हैं । ४३० साथियों का यह सदन है । अलग-अलग स्वभाव हैं । कुछ थोड़ी बहुत गर्मी के साथ भी बोल गये । यह अपने स्वभाव की बात है । मैं उनकी भावनाओं की प्रशंसा करता हूं, लेकिन जहां तक इस नुहकमे का संबंध है, किसी जिले में ऐसा हो कैसे सकता है कि इस विभाग का काम न हो ? यह बात ठीक है कि किसी के कहने के मुताबिक कहीं पर सड़क न बनी हो, किसी एक व्यक्ति के मकान पर सड़क न गई हो, उसके गांव में न गई हो, लेकिन हर जिले में जितना भी हो सकता है . . .

**श्री चन्द्रजीत यादव**--हम चैलेंज करते हैं कि एक इंच भी सड़क हमारे इलाके में नहीं बनी ।

**श्री गिरधारी लाल**--मैंने कहा कि यह अपने स्वभाव की बात है । सड़कों का मामला ऐसा नहीं है कि जो कहीं किसी रिजर्व बैंक के अन्दर छिपी हुई चीज हो । यह चीज खुली हुई है । मैं उसको बहस की चीज नहीं मानता हूं । वह जनता की सेवा के लिये है । यह ठीक है और ज्यादा सड़कें बननी चाहियें । अगर धन होगा तो और ज्यादा बनेंगी । मैं इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं और उम्मीद करता हूं कि सदन इस मांग को स्वीकार करेगा ।

**श्री उग्रसेन**--श्रीमन्, लेखा परीक्षा १९५८ की रिपोर्ट में ६,९१,००,६८४ रुपये की धनराशि के संबंध में आपत्तियां थीं, उसका निराकरण नहीं हुआ । इस पर माननीय मंत्री जी का क्या कहना है ?

**श्री अध्यक्ष**--मैं इसकी इजाजत नहीं देता । यह बहुत व्यौरे का सवाल है ।

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :--योजनाओं के अन्तर्गत सार्वजनिक निर्माण विभाग के बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ रहा है । रुपया लैप्स होता है तथा प्रदेश की स्वीकृत यातायातीय आवश्यकतायें पूरी नहीं हो पातीं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री अध्यक्ष**--प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य--नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है :--अनुत्पादक व्यय पर अधिक ध्यान देने की नीति से असहमति प्रकट करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:---ठेकेदारों द्वारा कार्य करने की प्रथा का निषेध ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:---जनोपयोगी निर्माण कार्य पर विशेष महत्व न देना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर विभाजन होने पर निम्नलिखित मतानुसार अस्वीकृत हुआ :---

पक्ष में---३२,
विपक्ष में---९७ । )

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:---द्वाराहाट-गनाई मोटर मार्ग का प्रस्तुत बजट में प्राविधान न होना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**---श्री कन्हैयालाल बाल्मीकि ने अपना प्रस्ताव वापस लेना चाहा है, क्या सदन की अनुमति है कि वह वापस किया जाय ?

(सदन की अनुमति से प्रस्ताव वापस किया गया । )

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:---जिला उन्नाव में विक्रमपुर-रुझिहई, बक्सर और बिहार भगवन्तनगर, ऊंचागांव-बक्सर सड़कों के न बनवाने से उत्पन्न कठिनाइयां ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:---जिला गोंडा मनकापुर-मसकनवा सड़क पर मनवर नदी पर स्थाई पुल न होने के कारण वर्षा में जनता को कष्ट ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

**श्री अध्यक्ष**---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान में मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है खटीमा, सिखारगंज, किच्छा-टनकपुर-हल्द्वानी, चांमी, खन्स्यूं, ओखलढुंगा-विजयपुर, पहाड़पानी, सौरकुटक, मोटर मार्गों को तथा गोला नदी, कैलाश नदी, दोहानदी स्थान खन्स्यूं में पुलों का अभी तक पूरा न किया जाना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:--- द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५९-६० में भी पिछड़े हुये क्षेत्र (सल्ट) जिला अल्मोड़ा की मोटर रोड, भरचूला-भानिला को स्थान न दिये जाने की शिकायत ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:--- सुल्तानपुर जिले की कादीपुर तहसील के नेमपुरघाट, दीवारघाट तथा कोयरीपुर के पीली नदी के पुलों को न बनवाना ।

दूसरा एक और है---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है कादीपुर-दोस्तपुर-कूड़ेभार-मझवाड़ा, सड़कों को पक्का न करना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३३---लेखा शीर्षक ५०-नागरिक निर्माण कार्य निर्माण कार्यों पर लागत के अन्तर्गत ६,०८,८७,२०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९-६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ । )

श्री अध्यक्ष---अब मांग ३४ पर मैं कटौती के प्रस्तावों पर राय लेता हूं और जब तक इस मांग के ऊपर मत नहीं ले लिया जायगा तब तक यह सदन ५ बजे के बाद भी बैठेगा ।

यह श्री श्रीपाल जी का है---

प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---योजनाओं के अन्तर्गत यातायात के साधनों के सुधार (केन्द्रीय सड़क निधि के लेखे से वित्तपोषित) से संबंधित बजट का अनियोजित रूप से प्रशासन किया जाना जिससे योजना का लक्ष्य पूरा नहीं हो रहा है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर १ रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---नीति का व्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है---अनुत्पादक व्यय की नीति की आलोचना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष---प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य---विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है---कंकड़ की सड़कें न बनवा कर अलकतरा की सड़कें न बनवाना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री सूरतचन्द रमोला**––अध्यक्ष महोदय, मैं श्रीमान् के द्वारा सदन से प्रार्थना करूंगा कि मेरा प्रस्ताव वापस किया जाय ।

(सदन की अनुमति से कटौती का प्रस्ताव वापस लिया गया ।)

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा उठाने का अभिप्राय है:––जिला गोंडा में मनकापुर-दर्जीकुंवा सड़क पर यातायात की बहुतायत पर भी उसका पेंट न करवाना ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि में १०० रुपये की कमी कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य––विशिष्ट शिकायत जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है:––द्वितीय पंचवर्षीय योजना के वर्ष १९५९–६० में भी पिछड़े क्षेत्र की मोटर मार्ग भरचूला मानिला (सल्ट) जिला अल्मोड़ा तथा तत्सम्बन्धी पुल को स्थान न दिये जान की शिकायत ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

**श्री अध्यक्ष**––प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ३४––लेखा शीर्षक ५०––नागरिक निर्माण-कार्य––केन्द्रीय सड़क निधि से वित्तीय सहायता के अन्तर्गत १८,३४,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९५९–६० के लिये स्वीकार की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

(इसके बाद सदन ५ बज कर २ मिनट पर अगल दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
५ मार्च, १९५९ ।

## नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९४ पर)

१९५८-५९ सीजन में गोंडा जिले में ऊख तोलने के कांटे जिन स्थानों पर लगाये गये हैं उनका विवरण ।

| क्रम-संख्या | गेट या केन्द्रों का नाम जहां कांटे लगे हैं |
|---|---|
| १ | बलरामपुर (गेट) । |
| २ | कावापुर (रेल सेंटर) । |
| ३ | इंटिया ठोक (रेल सेंटर) । |
| ४ | श्रीगंज (रोड सेंटर) । |
| ५ | उत्तरौला (रोड सेंटर) । |
| ६ | रेतवागढ़ (रोड सेंटर) । |
| ७ | गोंडा (रेल सेंटर) । |
| ८ | कोरिया (रेल सेंटर) । |
| ९ | विशेश्वरगंज (रेल सेंटर) । |
| १० | बढ़ियापकरी (रोड सेंटर) । |
| ११ | तुलसीपुर (गेट) । |
| १२ | गैंसरी (रेल सेंटर) । |
| १३ | पछपेरवा (रेल सेंटर) । |
| १४ | जरवा (रेल सेंटर) । |
| १५ | सरजू (रेल सेंटर) । |
| १६ | कर्नलगंज (रेल सेंटर) । |
| १७ | मेजापुर (रेल सेंटर) । |
| १८ | नवाबगंज (गेट) । |
| १९ | मोतीगंज (रेल सेंटर) । |
| २० | झिलही (रेल सेंटर) । |
| २१ | मनकापुर (रेल सेंटर) । |
| २२ | मसकनवा (रेल सेंटर)। |
| २३ | रगरगंज (रोड सेंटर) । |
| २४ | दत्तौली (रेहरा) (रोड सेंटर) । |
| २५ | गांधी बस्ती (रोड सेंटर) । |
| २६ | सोनबरसा (रोड सेंटर) । |
| २७ | बभनान (गेट) । |

# नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५१ का उत्तर पीछे पृष्ठ ४६५ पर)

इन्डो टिबेटन बोर्डर एरिया योजना के अन्तर्गत सन् १९५५-५६ में २८ कताई केन्द्र तथा ७ उत्पादन तथा प्रशिक्षण केन्द्र खोले गये थे जो अब तक चल रहे हैं उक्त योजना के अन्तर्गत अन्य प्रगति का विवरण निम्नलिखित है :

| विवरण | प्रगति १९५५-५६ | प्रगति १९५६-५७ | प्रगति १९५७-५८ | प्रगति १९५८-५९ (दिसम्बर, १९५८ तक) |
|---|---|---|---|---|
| शिक्षण--- | | | | |
| (अ) कताई करने वाले . . | ३,५६६ | ४,६२९ | ५,०३३ | ३,७२३ |
| (ब) बुनकर . . | ६८ | ६५ | ४८ | ४० |
| उत्पादन--- | | | | |
| (अ) सूत जो काता गया (मनों में) . . | ४३ | १३१ | १५३ | ८७ |
| (ब) कपड़ा जो बनाया गया (मूल्य रुपयों में) . | १२,१०७ | ५१,७१९ | ९२,६८६ | ६०,६२२ |
| नई डिजाइन--- | | | | |
| नई डिजाइनें जो निकाली गईं . . | ५६ | २०४ | २९९ | १८४ |

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६० का उत्तर पीछे पृष्ठ ४९८ पर)

## झांसी में स्थित महारानी लक्ष्मीबाई तथा राजा गंगाधर राव से सम्बन्धित इमारतों की सूची ।

| क्रम-संख्या | नाम इमारत या स्थान जो लक्ष्मीबाई व राजा गंगाधर राव से संबंधित हैं | नाम मालिक तथा विभाग जिसके प्रबन्ध में है |
|---|---|---|
| १ | झाँसी (गढ़) किला .. | भारत सरकार मिलेट्री विभाग के प्रबन्ध में है। |
| २ | रानी महल, हवेली, महारानी लक्ष्मीबाई | पुलिस विभाग के इन्तजाम में है; मालिक उत्तर प्रदेश सरकार। |
| ३ | फीलखाना तथा घुड़सार, बाहर चांद-दरवाजा, नई बस्ती। | नगरपालिका के प्रबन्ध में है तथा यही मालिक है। |
| ४ | पुरानी कोतवाली, मुहल्ला पुरानी कोतवाली। | जिला बोर्ड के प्रबन्ध में है तथा यही मालिक है। |
| ५ | हवेली यादवनाथ चौधरी, पुरानी तहसील। | श्री गोविन्ददास रामदास, तनय लल्ल, मु० गोपालनीखरा, झांसी के कब्जे म है; वही मालिक हैं। |
| ६ | नाटकशाला, महराज गंगाधर राव शहर गिरजाघर के पास, मानिक चौक। | क्रिश्चियन चर्च के कब्ज में है तथा चर्च मालिक हैं। |
| ७ | मन्दिर श्री रामजानकी महारानी, बड़ी टंकी के पानी के पास, बड़ी बाजार, झांसी। | झांसी की जनता प्रबन्ध करती है; कोई विशेष मालिक नहीं है, सार्वजनिक है। |
| ८ | मक़बरा गजरा तवायफ, सिविल अस्पताल में, मानिक चौक, झांसी। | जिलाधीश के इन्तजाम में है; मालिक उत्तर प्रदेश सरकार। |
| ९ | मक़बरा महाराज गंगाधर राव तहसील के पास। | जिलाधीश महोदय क इन्तजाम में है; मालिक उत्तर प्रदेश सरकार। |
| १० | मक़बरा महाराज गंगाधर राव बाहर लक्ष्मी दरवाजा झांसी। | झांसी नगरपालिका के प्रबन्ध में है तथा यही मालिक है। |
| ११ | मन्दिर श्री लक्ष्मी जी बाहर लक्ष्मी-दरवाजा, झांसी, लक्ष्मी तालाब पर। | जिलाधीश महोदय के इन्तजाम में है; मालिक उत्तर प्रदेश सरकार। |
| १२ | मन्दिर महावीर जी, फिरना चौपड़ा, अन्दर फिरना गट, झांसी। | जनता के प्रबन्ध में है, सार्वजनिक है विशेष रूप से यहां कोई मालिक नहीं है। |
| १३ | खांतिया तालाब, झांसी बाहर खण्डे राव गेट। | जमींदारान झांसी के प्रबन्ध में है, सार्वजनिक है, कोई विशेष मालिक नहीं है। |
| १४ | लक्ष्मी तालाब, बाहर लक्ष्मी दरवाजा | जमींदारान झांसी के प्रबन्ध में है तथा वही मालिक हैं। |
| १५ | बन्द खाकी शाह, लक्ष्मी तालाब बाहर बड़ा गांव गेट, झांसी। | नगरपालिका के प्रबन्ध में है तथा वही मालिक है। |

पी० एस० यू० पी०—ए० पी०—१ एल० ए०—१९५९—८४५।